Seventeenth Series, Vol. XVIII No. 26

Wednesday, April 06, 2022
Chaitra 16, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eighth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XVIII contains Nos. 21 to 27)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Sunita Thapliyal
Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XVIII, Eighth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 26, Wednesday, April 06, 2022/Chaitra 16,1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 481 to 486	10-40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 487 to 500	41-89
Unstarred Question Nos. 5521 to 5750	90-671

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 673-683

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 684

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

7th Report 685-686

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

Statement 687

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

Statements 688

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

13th Report 689

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

169th Report 690

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

33rd Report 690

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation in Ukraine 710-729

Dr. Subrahmanyam Jaishankar 710-728

MATTERS UNDER RULE 377 730--753

(i) Regarding promotion of natural farming

Shri Ganesh Singh 730

(ii) Regarding establishment of a DRDO lab, ordinance factory, Sainik School and Defence Recruitment Centre at Deoghar

Dr. Nishikant Dubey 731-732

(iii) Need to curb pollution in Indira Gandhi Canal and also to grant Membership of BBMB to Rajasthan

Shri Nihal Chand Chouhan 733

(iv) Need to establish Kendriya Vidyalayas in Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan

Sushri Diya Kumari 734

(v) Regarding plight of Jute Mills and Jute growing farmers

Shri Arjun Singh 735

(vi) Regarding alleged irregularities in storage of paddy in Chhattisgarh

Shri Chunnilal Sahu 736

(vii) Need to accelerate pace of construction work of Rewa-Singrauli railway line, part of Lalitpur-Singrauli Railway line Project

Shrimati Riti Pathak 737

(viii) Need to continue the services of Poshan Sakhi in Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 738

(ix) Regarding construction of Rajasthan Sabarmati link Canal

Shri Parbatbhai Savabhai Patel 739

(x) Regarding construction of a bridge for pedestrian traffic across railway lines in Naroda railway station, Ahmedabad, Gujarat

Shri Hasmukhbhai S. Patel 740

(xi) Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir

Shri Jugal Kishore Sharma 741

(xii) Regarding road accident insurance plan for licensed vehicle drivers

Shri R.K. Singh Patel 742

(xiii) Regarding declaration of state road from Mannarkkad to Coimbatore via Attappadi and Chinna Thadagam as sub Highway to National Highway No. 966

Shri V. K. Sreekandan 743

(xiv) Regarding prices of life-saving drugs

Adv. Dean Kuriakose 744

(xv) Regarding setting up of a trading point along the Indo-Bangladesh Border in Murshidabad district, West Bengal

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 745

(xvi) Regarding naming of Centrally sponsored schemes by Andhra Pradesh Government

Shri Raghu Rama Krishna Raju 746

(xvii) Regarding sanction of an integrated cold storage for Potatoes in Arambagh Parliamentary Constituency

Shrimati Aparupa Poddar 747

(xviii) Regarding hike in prices of Petroleum products

Prof. Sougata Ray 748-749

(xix) Regarding construction of RoB, VUP and CUP on N.H. 52 in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Rahul Kaswan 750

(xx) Regarding implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (G) in Odisha

Shri Chandra Sekhar Sahu 751

(xxi) Regarding resolution of water disputes between Rajasthan and other States

Shri Hanuman Beniwal 752

(xxii) Regarding start of several flights from Belgaum

Shrimati Mangal Suresh Angadi 753

WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AND THEIR DELIVERY SYSTEMS (PROHIBITION OF UNLAWFUL ACTIVITIES) AMENDMENT BILL, 2022 754-832

Motion to Consider 754

Dr. Subrahmanyam Jaishankar 754-755, 823-830

Shri Uttam Kumar Reddy 755-758

Col. (Retd) Rajyavardhan Rathore 758-763

Shri A. Raja 763-767

Prof. Sougata Ray 767-773

Dr. Sanjeev Kumar Singari	774-777
Shri Vinayak Bhaurao Raut	777-779
Shri Chandra Sekhar Sahu	779-781
Shri Ritesh Pandey	781-784
Shrimati Supriya Sadanand Sule	784-788
Shri Jayadev Galla	788-792
Shri Manish Tewari	792-796
Dr. Satya Pal Singh	796-800
Shri E. T. Mohammed Basheer	801-803
Shri N.K. Premachandran	803-806
Shri P. Ravindhranath	806-808
Shri Hanuman Beniwal	808-810
Shrimati Aparupa Poddar	811-812
Shri Kuruva Gorantla Madhav	812-813
Kunwar Danish Ali	813-817
Dr. Nishikant Dubey	818-820
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	820-823
Clauses 2 and 1	831
Motion to Pass	832

MOTION RE: 33rd REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTE 833

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions 789

Member-wise Index to Unstarred Questions 790-796

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions 797

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 798

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, April 06, 2022/Chaitra 16,1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, प्रश्न संख्या – 481, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी।

(Q. 481)

श्री विनायक भाउराव राऊत : सर, मेरा एक पॉइंट ऑफ आर्डर है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल में पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं होता है।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से इस प्रश्न का जवाब दिया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दिशा-निर्देश से यह काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, जो आरयूबी है, खासकर जो बरसात वाला एरिया है या फिर जहां बरसात के समय बाढ़ आती है, वहां आरयूबी की हाइट से ऊपर, रेलवे लाइन के ट्रेक के नीचे तक पानी आ जाता है और इसका समाधान का तरीका यह बताया गया है कि पम्प सेट से पानी निकाला जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब नजदीक में नाला होगा तभी तो वहां से पानी निकाला जाएगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसका कोई वैकल्पिक उपाय सोचना चाहिए और जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के समय तो यह आरओबी बंद रहता ही है, उसके आगे चार महीने तक भी बंद रहता है।

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने यहां पर जो आरयूबी में वाटर लॉगिंग का विषय रखा है, वह वास्तव में सभी माननीय सदस्यों का विषय है। अभी रेलवे ने सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के अंडर पूरे देश भर के चीफ इंजीनियर्स की एक डिटेल्ड वर्कशॉप रखी थी कि किस तरह से हमारे पास समाधान के जितने भी ऑप्शन्स अवेलेबल हैं, उन ऑप्शन्स को इसमें यूज किया जाए।

मान्यवर अध्यक्ष जी, इसमें चार ऑप्शन्स यूज किए जा रहे हैं। पहला, पम्पिंग का है। पिछले साल भी पम्पिंग बहुत की गई थी। इस साल हम उसको और अधिक मात्रा में करेंगे। दूसरा, हम डिजाइन में चेंज कर रहे हैं। हमारे कर्नाटक के सांसद महोदय भगवंत खुबा जी, जो कि एमओएस हैं, उन्होंने मीटिंग में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि अगर एक किलोमीटर दूर भी लेवल लोअर है और एक किलोमीटर लंबी पाइप

लाइन भी बनाते हैं तो अच्छा होगा। हम उस सुझाव को भी अमल में ला रहे हैं। तीसरा, बहुत सारी जगह आरयूबी को थोड़ा चौड़ा करके जैसे अगर बाकी हिस्से का लेवल नीचे है तो हम कुछ हिस्से का एक-एक मीटर का हिस्सा ऊपर लेने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अब यह कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आरओबी बनाएं, ओवरब्रिज बनाएं ना कि अंडरपास बनाएं, क्योंकि अण्डरपास में चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन दूर-दराज के इलाके में वाटर लॉगिंग तो होती ही है।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : माननीय मंत्री जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में भी बोला है कि बरसात और बाढ़ ग्रसित एरिया के लिए सभी माननीय सदस्यों का प्रश्न उनके पास आता है कि ऐसे एरियाज़ में आरयूबी कारगर नहीं है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जितने भी आरयूबीज़ में जल जमाव का मामला है, क्या आप इनके संबंध में सभी परियोजनाओं को क्लब करके और इनको राष्ट्रीय परियोजनाओं में चिह्नित करके वहां आरओबी बनाने पर विचार रखते हैं?

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद का जो प्रस्ताव है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। यथासंभव आरयूबीज़ को आरओबीज़ में कन्वर्ट करने का प्रयास चल रहा है। अध्यक्ष जी, दोनों की कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आरयूबी दो-तीन करोड़ रुपये में बन जाता है, जबकि आरओबी में 50 से 60 करोड़ रुपये की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ आरओबी जल्दी से जल्दी बने, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। अभी 218 के आसपास स्टैडंर्ड डिजाइन्स बनाई गई हैं, जिससे कहीं पर भी अप्रूवल का झमेला ही नहीं रहेगा।

डिजाइन आलरेडी एप्रूव करके फील्ड में भेजी गई है, जिससे एप्रूवल का कोई झमेला ही न रहे, फटाफट एप्रूवल हो और काम आगे बढ़े।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर जल भराव नहीं होता, पम्पिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, मार्ग उपलब्ध है और वहां, केवल जो रेलवे एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर खिसकाता है और वह अंडरपास चालू हो जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में वनखेड़ी, बागरातवा, सोनतलाई और बारापुरा ऐसी जगहें हैं, जहां वाटर लॉगिंग नहीं होती

है, मार्ग उपलब्ध है और वहां अंडरपास बन सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां पर वाटर लागिंग नहीं होती है, क्या वहां पर माननीय मंत्री जी यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे?

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर अध्यक्ष जी, जहां पर भी एम्बैंकमेंट की हाइट करीब तीन मीटर से अधिक है, वहां पर आरयूबी बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। जहां से भी इस तरह के प्रस्ताव आएंगे, जरूर उन पर विचार करके उचित निर्णय लिया जाएगा।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, instead of expeditious execution of railway projects, a number of railway projects have been suffering from procrastination. सर, मैं आपका थोड़ा इंडल्जेंस चाहता हूं और दूसरे एक मुद्दे को उठाना चाहता हूं, जो मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पिछले आठ-नौ वर्षों से एक आरओबी – 131, चुआपुर-बहरामपुर और दूसरा आरओबी – 132, पंचाननतला-बरहामपुर, आरयूबी नम्बर-111, in all these projects everything was sanctioned, tenders were done, and contracts were awarded. But no progress has so far been achieved, barring 60 per cent job at Chuapur ROB. Not only that, in so far as low-cost RUB is concerned, there is no visibility in the Salat to Azimganj project under Howrah Division. मैं जानता हूं कि यह सम्पर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ डिस्पर्शन क्या करें। आरओबी की हालत यह है, आरयूबी का हाल यह है, आप यहां कहते हैं कि पम्प आउट करना चाहिए, लेकिन पम्प आउट कौन करेगा? सूबे की सरकार को कहना पड़ेगा, लेकिन वे कहते हैं कि इसमें हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट योगदान नहीं कर सकता है। ऐसे में हम क्या करें और कहां जाएं? पम्प आउट करने के लिए क्या आपके पास कोई क्षमता है? आपको सूबों की सरकार पर निर्भर करना पड़ेगा।

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर अध्यक्ष जी, कोई भी आरयूबी या ओओबी अगर बनता है तो उसमें रेलवे की जमीन, रेलवे की पटरी के ऊपर वाला हिस्सा और उसके नीचे वाला हिस्सा आता है और उसके साथ राज्य सरकार की कोई न कोई सड़क जुड़ी हुई होती है। बहुत ही अफसोस की बात है कि कुछ सूबे ऐसे हैं, जिनमें मान्यवर एलओपी साहब का सूबा भी है, जहां परमीशन्स ही नहीं मिलती हैं। आप छोटे से छोटे काम

के लिए भी अगर परमीशन लेना चाहें तो कई बार दिक्कतें आती हैं। एलओपी साहब ने जिन स्पेसिफिक एलसी, आरओबी और आरयूबी का नाम दिया है, उनके बारे में जानकारी लेकर मैं मान्यवर एलओपी साहब को दे दूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम।

... (व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : सर, हमने नोटिस दिया था।... (व्यवधान) इस विषय को उठाने के लिए हमें समय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं।

11.08 hrs

At this stage, Shri Nama Nageswara Rao and some other hon. Members left the House.

SHRI S. S. PALANIMANICKAM : Thank you, Sir. As per the answer given by the hon. Minister about RUBs, all the RUBs are under the RDSO. But, all of a sudden, the Railway Board and the Railway Ministry have decided to convert all the manned and unmanned crossings into RUBs. Indian Railways covers the longest coastal area in the country. During monsoon season, all the coastal areas in the country get submerged into water, and at present, the Railway Department is not able to drain that water into the nearby areas. So, the Railway Ministry should reconsider its decision of converting all manned and unmanned crossings into RUBs. There must be some new proposal in this regard or the Railways may continue manned and unmanned crossings.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker, Sir, the point raised by the hon. Member is a very valid point. But the decision to eliminate unmanned crossings and the decision to close down manned crossings was taken purely after many years of

discussion in which every LC used to have the danger of accidents. There were very unfortunate incidents in the past. So, I think, this is a very good decision taken by the Railways. I would request the hon. Member to support this decision. This has reduced so many grave accidents. On the contrary, we must try and find more technical solutions or engineering solutions rather than taking a decision to reverse the closure of LCs.

HON. SPEAKER: Q. No. 482**,** Shri Sanjay Kaka Patil.

… (*Interruptions*)

(Q. 482)

KUMARI GODDETI MADHAVI: Thank you, Speaker, Sir. The liberalisation of regulations of geospatial mapping was meant to boost planning for infrastructure, development and businesses which are data-based. Since de-regulation, what improvements have been seen in these sectors and how does the Government plan to consolidate these gains?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, I am glad that the hon. Member has asked this question. As she is rightly mentioning, liberalisation in the geospatial policy and the new guidelines were brought in to enable ease of working, ease of science and also ease of mapping. Now that the Government has undertaken several flagship programmes like the SVAMITVA programme where it is intended to map the habitat areas of all the villages across the country, the role of this organisation, the Surveyor General of India office also has enhanced. You would also appreciate that this is in keeping with the policy of Prime Minister Narendra Modi to reduce the compliances and reduce the regulations where not required. Earlier, there was unlocking of space technology. Now, this is followed by liberalisation of the geospatial policy so that it is accessible to all except for the security concerns wherever they are applicable. Several safeguards have been put in place. Now, also there is some liberalisation in the drone guidelines. So, this is all in keeping with the new context and the new agenda of the Government for the coming years.

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE: Thank you hon. Speaker, Sir. During the Russia and Ukraine war, we have seen that all the geospatial, financial and health related data was shut down by the international companies because of their presence in Russia. Now, Russians cannot use their credit cards and debit cards. Neither is their data on foreign land accessible to them because it is with the international companies. So, through you, I would like to know from the hon. Minister whether our country is dependent on foreign companies for our geospatial, banking, health, telecom, and e-governance data. Also, if our country faces such a warlike situation, is our data of Government health record and data of Indian enterprises safe on cloud controlled by foreign entities? Also, is the Government planning to transfer the entire technology of foreign entities to our Indian companies?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, the concern of the hon. Member is well taken. But there is no such reason to be worried as far as the safety of the data is concerned. Liberalisation of the regulations was meant to make it more accessible.

Even otherwise, data was available through other sources. Now, it is accessible to the domestic users and the domestic agencies. However, if a foreign entity has to access our data, then there are already guidelines in place even in normal circumstances, even if it is not a warlike situation. There is a separate list of sensitive attributes which I can narrate, but it will take long. This is called negative list of sensitive attributes. These clauses have already been in place even for the peace times.

SHRI MANISH TEWARI : Thank you very much, hon. Speaker, Sir. I would like to thank the hon. Minister for a very detailed reply. But I would like to ask one question

to the hon. Minister because there seems to be some kind of a confusion in the answer which he has given. He said that as per the guidelines for acquiring and producing geospatial data and geospatial data services including maps, which were issued by the Department of Science and Technology on 15th February, 2021, -- and the last three lines say -- terrestrial mobile mapping survey, street view survey, and surveying in Indian territorial waters shall be permitted only for Indian entities irrespective of accuracy. Hon. Speaker, Sir, my question is this. Today, all of us are using Google Maps, Google Earth, and various other kinds of applications where very detailed street views and also, the minutest details of all our cities, metropolises, and towns are available. So, under those circumstances, how are these guidelines really compatible with what is the existing situation? Is the Government going to bring out some additional guidelines which will validate the status quo which is already in play? Are you going to invalidate Google Maps and other Google applications, and all other global geospatial services which are being used by the citizenry, at large, across the world, including India?

DR. JITENDRA SINGH: I am glad that the hon. Member has asked this question. Of course, this was one of the considerations when the regulations were relaxed. As you have rightly mentioned, the data was available from other sources like Google. Now, as far as we are concerned, we have tried to restrict the use to the domestic users as much as possible and also, we have reduced the extent of scientific resolutions that will be available to the non-Indian entities. But that is not the end of it. I agree with you. We are in the process of formulating a policy which would outline the approach and strategy for holistic development of geospatial ecosystem because the

technology is moving very fast. I agree with you that this new policy will then, finally replace the existing National Mapping Policy, which was formulated way back in 2005. So, to that extent, of course, we need to update ourselves from time to time. We will also take all these concerns into consideration and will come out with a comprehensive policy. The work, in this regard, is already going on as a follow-up to the changed new guidelines.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 483, श्री शंकर लालवानी।

(Q. 483)

श्री शंकर लालवानी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रश्न का उत्तर दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आपका विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। हम ने यह कोविड में भी देखा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होंगी और इंदौर में 4G की सेवा कब प्रारंभ होगी?

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सांसद का पूरक प्रश्न इससे अनरिलेटेड है, फिर भी मैं बहुत ही संतोष के साथ सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में डेवलप्ड, भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट्स ने जो डेवलप किया है, आज उसको पूरी दुनिया देख रही है, वैसा 4G कम्पलीट कोर नेटवर्क, रेडियो ऐक्सेस नेटवर्क, पूरा उसका टेलीकॉम इक्विप्मेंट का सेट-अप बन कर तैयार है और बीएसएनएल 6000 से ज्यादा टावर्स का पहला ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मैं आपको चेक करके यह बता दूंगा कि उसमें इंदौर सम्मिलित है या नहीं। उसके तुरंत बाद में और 6000 टावर्स और उसके बाद में पूरा एक लाख टावर्स का ऑर्डर प्लेस होगा। इसके साथ ही साथ 5G का डेवलपमेंट इन-पैरलल चल रहा है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, इस अमृतकाल में मान्यवर प्रधान मंत्री जी ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 4G और 5G देश में अपनी निर्मित टेक्नोलॉजी डेवलप हो कर तैयार हो रही है।

श्री शंकर लालवानी : मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि आप संचार मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं। कभी-कभी जनता की ओर से मांग आती है कि क्या भविष्य में रेलवे में नेट शुरू किये जाने की संभावना है?

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न फाइब्राइजेशन से बहुत दूर है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सौ किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने के लिए मिनिमम 5 जी

चाहिए होती है, 4 जी की स्पीड में डिसरप्शन आना शुरू हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी का एक इवोल्यूशनरी समय है। जैसे-जैसे 5 जी भारत में डेवलप होगी और प्रोलिफरेट होगी, वैसे-वैसे रेलों में भी मिलने लगेगी।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल: माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से और विस्तार से जवाब दिया है। लेकिन जब मैं जवाब पढ़ रही थी, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पिछले लगभग पचास-साठ वर्षों में इस देश में जितने बीटीएस नहीं लगे थे, उससे कहीं ज्यादा पिछले आठ साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संबंधित मंत्रालय द्वारा पूरे देश में बीटीएस लगाए गए हैं। मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगी कि पूरे देश में अब 23, 07,068 बीटीएस लग चुके हैं। यह डिजिटल इंडिया की ओर बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। मेरा एक छोटा-सा प्रश्न यह है कि गुजरात में भी 1,40,066 बीटीएस लग चुके हैं। लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि गुजरात में जितने टॉवर ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने के लिए बाकी हैं, क्या उसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है या नहीं?

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य महोदया को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया।

मान्यवर, अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस 'अमृतकाल' में सैचुरेशन लेवल पर पहुंचना है। कोई डिसक्रिमिनेशन न करते हुए, जितने भी अन-कवर्ड एरियाज या विलेजेज हैं, चाहे वे गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, नॉर्थ-ईस्ट, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल आदि कहीं भी हों, सभी स्थानों पर फाइबर भी पहुंचाना है और टॉवर की सर्विसेज भी देनी है। इससे संबंधित अभी एक सर्वे चल रहा है, जो बहुत ही डिटेल्ड सर्वे है। प्रॉपर रेडियो सिगनल की स्टडी के हिसाब से उसका पॉवर लेकर यह किया जाएगा। अभी इसका सर्वे चल रहा है। जैसे ही यह सर्वे कम्प्लीट होगा, उसके बाद जितने भी बचे हुए गाँव हैं, उन सब गाँवों में, सभी क्षेत्रों में फाइबर टॉवर के लिए व्यवस्था की जाएगी।

SHRI DAYANIDHI MARAN : Thank you, Speaker Sir.

Sir, the hon. Minister has given a very good answer to the question that the major hurdle in having fibre connectivity or laying fibre is the Right of Way.

Sir, this answer is not the first time being given in the Parliament by our Minister. Previous Telecom Ministers have also expressed their inability to make sure to by-pass State laws and give Right of Way to all telecom providers.

Sir, Today when fibre to home has reached its peak and people are demanding high speeds, the Union Government should come forward to make a policy and make it more viable and uniform throughout the country so that laying of fibre lines by telecom operators and cable tv operators are made easy and it is a one-stop shop and they do not have to run from pillar to post.

You have BharatNet by which the Union Government is trying to make internet available to villages. All this could be made easier if the policy is done properly. You have the TRAI on your side. Why is it that you are not putting your effort and heart and soul so that Right of Way is ensured for the telecom providers and cable TV operators?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: I welcome the hon. Member's suggestion and in fact, he knows a lot about telecom. So, it is a very wise suggestion.

Sir, I would like to place on record our appreciation for BSNL which has done an excellent experiment over the last almost one year.

On what exactly what the hon. Member has said, the cable operators, the local entrepreneurs, somebody in the village, are willing to take that risk and put that effort to take the fibre to the home and today, almost on an average, one lakh connections

are given every month. So, that is exactly what you said and now, we want to scale it up that experiment up to a larger level.

In the federal structure, can the Central Government enforce something which is purely the mandate of the State and the local Governments? That is the question on which already a lot of discussions have happened in the past. Hopefully, almost 12 States have aligned with the Central Government's policy. I would like to request the hon. Members of Parliament to please request their State Governments to reduce the cost of RoW. In some of the States, the cost of RoW is as high as Rs. 25 lakh per kilometres. How would fibrisation happen? That is the kind of big burden that some of the States are putting. I will request all the hon. Members to please work with their respective State Governments and make sure that the cost is reduced.

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, देश की सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिससे सचमुच भारत की तस्वीर बदल जाएगी, जब हम छ: लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर से लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर लेंगे। हमारे पास बीएसएनएल है, उसके बाद हमने बीबीएनएल बनाया, लेकिन अचानक सरकार ने किसी समय, हमारी सरकार ने नहीं, पिछली सरकार ने बीबीएनएल और बीएसएनल के हाथ काट दिए।

एक संस्था से स्पेशल परपज व्हीकल बनाकर सीएससी बनाने की बात कही, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इनश्योर करेगी। इस प्राइवेट संस्था में स्पेशल परपज व्हीकल बनाया गया। जिस अंतिम घर में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है, उसकी सीएससी को जिम्मेदारी दी गई, जिसके बारे में चर्चा की गई है।

महोदय, टैंक में अगर पानी हो और टंकी से पानी न निकले, तो मेरे लिए टैंक का पानी बेकार है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे आग्रह किया है कि सीएससी की फंक्शनिंग, जो एक प्राइवेट इंस्टिट्यूशन है, जिसकी उपस्थिति न तो सांसदों की बैठक में है और न

किसी को उसकी जानकारी है, उस प्राइवेट संस्था के बजाए वापस बीबीएनएल और बीएसएनएल को इसे सुपुर्द करें, ताकि हम देश के हर गांव, हर घर तक प्रधान मंत्री जी की इस बड़ी योजना को पहुंचा सकें।

खासकर, बिहार में जो सीएससी है, वह एक ऐसी संस्था है, जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। हर गांव में लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए जब तक हम ऑप्टिकल फाइबर को चालू नहीं करा देते हैं, जिसे 'अप' कहा जाता है, तब तक हम इस योजना में कामयाब नहीं होंगे।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि सरकार इस पर कोई नीतिगत फैसला लेगी, तो शायद बीएसएनएल और बीबीएनल दोनों कामयाब होंगे और इस प्राइवेट संस्था से हम मुक्त हो सकेंगे, जिससे सभी सांसदों की भागीदारी बढ़ेगी।

मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। वे मुझसे पर्सनली मिले भी थे।

अध्यक्ष जी, भारतनेट के रोल-आउट में वक्त-वक्त पर, समय-समय पर कई तरह के चैलेंजेज आए। देश भर में ऑप्टिकल फाइबर का इतना बड़ा रोल-आउट, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और विशेषकर एक फेडरल स्ट्रक्चर में, जिसमें राज्य सरकारों को भी साथ लेना होता है और लोकल गवर्नमेंट्स को भी साथ लेना होता है। ऐसे कई चैलेंजेज आए, इन चैलेंजेज में कभी-कभी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। मैं मानता हूं कि सीएससी को एक वक्त में इनवॉल्व करके, उनके जरिए से कोशिश करना, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी सब जगह पहुंच सके, यह अच्छा एक्सपेरिमेंट था। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : किसी सांसद से सीएससी के लोग मुलाकात नहीं करते हैं, दिशा कमेटी की बैठक में उसके अधिकारी नहीं आते हैं। ... (व्यवधान) वह एक प्राइवेट संस्था है। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, हर प्रोजेक्ट में कुछ प्लसेज होते हैं और कुछ माइनसेज होते हैं। ... (व्यवधान) इसमें जरूर कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अब एक बहुत क्लियर डायरेक्शन में भारतनेट को ले जाया जा रहा है, जिसमें जो मिडिल-माइल है, जो सबसे क्रिटिकल है, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया कि पानी के टैंक में पानी हो, लेकिन नल में पानी न आए, तो जो मिडिल-माइल – जितना भी कनेक्टिंग फाइबर

है, उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल एजेंसीज को लगाकर, उनके साथ स्टडी की जा रही है। उस नेटवर्क की पूरी टोपोलॉजी चेंज करके, लीनियर की जगह रिंग-टोपोलॉजी लाने का प्रयास अभी चल रहा है, जिसके बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स भी आएंगे।

मुझे आशा है कि माननीय सांसद जी की इसमें सहमति रहेगी।

श्री गोपाल शेट्टी: माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, जिसके बारे में मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूं, क्योंकि कुछ उत्तर आ गए हैं। शहरी इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर केबिल के लिए जो डिगिंग होती है, उससे बड़ी परेशानी होती है। शहरी इलाकों में व्हीकल्स की संख्या बहुत होती है, इसलिए समय-समय पर वहां खुदाई का काम होने से बड़ी परेशानी होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि बगैर डिगिंग से इस कार्य को किया जा सके? टैक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। आपने अपने उत्तर में भी कहा है कि रेलवे में अगर 5G आ जाएगी, तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डिगिंग किए बगैर इस नेटवर्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस प्रकार हो सकता है, यह मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर काम हुआ और आज देश में सबसे ज्यादा बीटीएस - 2,40,000 महाराष्ट्र में लगे हैं। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि बिना डिगिंग के फाइबर बिछाना, यह संभव नहीं है। एक तरीका है कि इलेक्ट्रीकल पोल्स के ऊपर उसे लगाया जाए, लेकिन इलेक्ट्रीकल पोल्स पर ले जाने में दिक्कत यह है कि वह कभी भी कट हो सकता है। कभी उसकी सैगिंग हो जाती है। यह एक्सपेरीमेंट्स कई जगह किए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए हैं इसलिए डिगिंग और ड्रिलिंग तो करनी पड़ेगी। यदि हॉरीजोंटल ड्रिलिंग करें, तो हो सकता है कि कम से कम डिसरप्शन हो, लेकिन यह तो अनिवार्य है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम है कि टावर्स को आप्टीकल फाइबर के साथ जोड़ रहे हैं। इसकी गति पहले धीमी थी,

लेकिन अब गति में थोड़ी तेजी आई है। इसका सबसे बड़ा लाभ केवल प्राइवेट ऑपरेटर्स ले रहे हैं। बीएसएनएल का नाम गांव में 'भाई साहब नहीं लगेगें' है। बीएसएनएल की यह फुल फार्म बन गई है। बीएसएनएल की सेवा लगातार गिर रही है। बीएसएनएल आज तक 4जी यूज नहीं कर पाया है और आप 5जी में चले गए हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीएसएनएल की बेहतर परफोर्मेंस के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है, क्योंकि आपके बीएसएनएल के जो कस्टमर्स हैं, वे प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास शिफ्ट हो रहे हैं?

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, यदि माननीय सदस्य ध्यान देते तो मैंने प्रश्न के पहले ही सप्लीमेंटरी उत्तर में बताया था कि भारत में निर्मित 4जी का बीएसएनएल अभी रोल आउट स्टार्ट कर रहा है और जैसे 4जी रोल आउट होगा, वैसे-वैसे बीएसएनएल की सर्विसेज डेफीनेटली बहुत इम्प्रूव होंगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 484, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे।

(Q. 484)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि मूल प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत रूप से दिया है। मेरे उप-प्रश्न NMICPS के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने उत्तर में ब्यौरा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें हमें निवेश करने की आवश्यकता है और सरकार National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System, NMICPS के माध्यम से Development and translation of futuristic technologies specially in the areas of Artificial Intelligence पर काम कर रही है, लेकिन फिजिकल टार्गेट्स NMICPS के अंतर्गत हैं। वे बहुत कम हैं। जैसे Job creation under the Mission was set as 2,54,000 against which the Department could only achieve 1,157 which is 0.46 per cent. टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का लक्ष्य 607 था, इनमें से केवल 45 पूरे हुए हैं और यह केवल सात प्रतिशत है। Start-up and spin-off companies जिनका लक्ष्य 1170 था, उनमें से सिर्फ 54 ही पूरे हुए हैं, जो कि पांच प्रतिशत है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे महत्वपूर्ण एरिया के लिए चलाई जाने वाली योजना के नॉन परफोर्मेंस के कारणों की क्या सरकार ने समीक्षा की है और इसमें सुधार करने के लिए भविष्य में सरकार की क्या योजना है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य इस विषय के जानकार हैं, इसलिए इन्होंने दो-तीन भागों में यह प्रश्न किया है। जहां तक स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के नए आयामों का संबंध है, निश्चय ही यह सरकार की प्राथमिकताओं में है और आपको स्मरण होगा कि वर्ष 2015 में लालकिले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री जी ने स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया का आह्वान किया था और उसके बाद वर्ष 2016 से एक नीति निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत इसे बहुत तीव्र गति दी गई। हालांकि this is on the assent, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि इसे आगे बढ़ना है, लेकिन यदि इससे पहले की स्थिति और पहले के आठ वर्षों का समय वर्ष 2006 से 2014 तक देखते, तो उस समय सरकार की तरफ से फंडेड स्टार्ट-अप्स की संख्या मात्र 1650 थी, क्योंकि उस समय इतनी प्राथमिकता

नहीं दी जाती थी। जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की चर्चा हुई, ड्रोन्स की चर्चा हुई और बहुत सारे आयाम जैसे हैली वॉर टेक्नोलॉजी आई तथा अन्य बहुत सारे क्षेत्र आ गए। प्रधान मंत्री जी के आह्वान के पश्चात् गत आठ वर्षों में, वर्ष 2014 से 2022 तक टोटल फंडेड 10600 स्टार्ट-अप्स की संख्या हो गई। यानी आठ वर्षों की तुलना में दस गुना स्टार्ट-अप्स की संख्या बढ़ी है।

ये वे स्टार्ट अप्स हैं, जो सरकार की ओर से फंडेड हैं, फिर चाहे वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से हों चाहे अन्य विभागों से हों। अगर आप मात्र रजिस्टर्ड स्टार्ट अप्स की संख्या लें, जो कि डीपीआईआई में फंडेड ऑर नॉन फंडेड होते हैं, तो उनकी संख्या वर्ष 2016 से 67 हजार है, यानी जब से इसको प्राथमिकता दी गयी, तब से। We are now a part of the global world and we have to live up to the global benchmark.

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसका उपयोग ड्रोन्स में भी किया जा रहा है। यहां तक कि आपको हैरत होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में भी किया जा रहा है।

यदि कोई याचिका आती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से 'बिटवीन द लाइन्स' पढ़ा जा सकता है कि उसने जो बात कही है, उसके अतिरिक्त भी कुछ है। सरकार प्रतिबद्ध है, अगर आप कहेंगे तो मैं सारी संस्थाओं की संख्या भी आपको दे सकता हूं, यद्यपि उसकी आवश्यकता नहीं है। यह एक संतोषजनक बात है कि we are now in the third position in the world after USA and China as far as unicorns are concerned. We already have 99 unicorns. शायद मेरे बात करते-करते 100 हो गए हों। मैं कल सुबह का आंकड़ा दे रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि काफी तेज गति से यह हो रहा है और आम जनमानस में भी इसके प्रति उत्साह है। We are aware of it and we will cooperate with the startup movements and encourage them.

श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, मेरा दूसरा प्रश्न बायो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। प्रदूषण जैसी समस्याओं का निवारण करने के लिए बायो टेक्नोलॉजी एक बहुत व्यापक माध्यम है। आज देश में भारी मात्रा में स्टार्ट अप्स बन रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट टैक्नीक के स्टार्ट अप्स का अभी भी अभाव है।

मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जैसे सरकार ने कोरोना महामारी के समय NIDHI4COVID 2.0 शुरू किया था, क्या वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट और बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्ट अप्स के लिए एक डेडीकेटेड योजना लाने का सरकार का कोई विचार है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह निश्चित रूप से आधुनिक मापदंडों के साथ जुड़ती है। हुआ यह है कि जानकारी का अभाव है। बायो टेक्नोलॉजी के माध्यम से I am proud to share with the House that भारत की जो वैक्सीन डेवलप हुई है, उसके ट्रॉयल्स हमारे ही विभाग में हुए हैं। फरीदाबाद में हमारा एक संस्थान है, वहां पर बाद में भारत बायोटेक ने उसे डेवलप किया। इसके अतिरिक्त नेजल वैक्सीन जो डेवलप हो रही है, वह भी बायो टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। बायो टेक्नोलॉजी पिछले कुछ वर्षों में बहुत सक्रिय हो चुका है और स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए वहां पर बिराक नामक संस्था है, Biotechnology Industry Research Assistance Council. It has become quite popular in recent times.

जहां तक स्पेसिफिकली वेस्ट मैनेजमेंट का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा कि जानकारी का अभाव है। हमारे यहां नजदीक ही मोती बाग कालोनी है, जहां पर सरकारी अधिकारी रहते हैं। वहां की सोसायटी की एक बिल्डिंग में एक प्लांट भी सीएसआईआर के माध्यम से लग चुका है। जो पानी वहां से निकलता है, उसी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है। But I agree with you that we should create more awareness ताकि स्टार्ट अप्स भी और आएं और इन टेक्नोलॉजियों का उपयोग भी अधिक हो सके।

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Sir, the hon. Minister has given a very detailed answer. I want to know about the Technology Development Board which comes under this Ministry. It provides financial assistance to the startups. In your reply, you have mentioned that hon. Prime Minister also wants the startups to be promoted. A sum of Rs.75 crore had been allocated in 2021-22. But we have seen that only 30 per cent of it has been utilised till 30th January, 2022.

I want to know from the hon. Minister about the reason for this low utilisation. I would also like to know whether the Ministry is planning to build a partnership with venture capital firms and investment network across the country for reaching out to a wider group of investors.

DR. JITENDRA SINGH: Mr. Speaker, Sir, I would like to share with the hon. Member that the Technology Development Board was constituted about 25 years ago and it has got some good success stories as far as the startups are concerned. One of them is Bharat Biotech which started its career from the Technology Development Board (TDP).

From the Technology Development Board (TDB), one of the first fundings was done to him and today they have built up an empire. Then, Biocon Limited also shares a similar story. I agree with the hon. Member that now I try to go one step further. I have decided to go in for a start-up hunt. What was happening earlier was, the start-ups used to come to us and we would fund them. But if we have a mechanism to reach out to the most deserving companies who already have the capacity but require resources, then, actually, we will not only be able to support start-ups, but also ensure sustainable start-ups for a sustainable future economy. The recent Beating the Retreat Show, which you saw, was also funded by the Technology Development Board. You saw those 1,000 drones which were put up and which lighted up the entire sky over the Vijay Chowk. That was the most watched Beating the Retreat Show ever since Independence and that had happened on the 29th January, 2022. There were three youngsters who were funded through the same Technology Development Board and within six months, they have done that show

which has created a record, because the world record is 5,000 drones; they have already reached 1,000.

So, we are trying to activate it. But I agree with you that we need to activate it further and we should also reach out to those who are actually looking up for such support.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Mr. Speaker, Sir, the Minister has not replied to the question about low utilisation of fund.

SHRI JITENDRA SINGH: Sir, actually, it is not low utilisation of fund; it is only the optic of the figures, because there is a mechanism of funding. We do not straightway give the amount. For example, for the Beating the Retreat Show, initially they were given Rs. 50 lakh, then they came out with something, and then further funding was done. But the process is continuous. I would also like to call upon all the Members that we should also try to help in searching out the right kind of people so that the funding goes to those who may not have reached us, but we have reached out to them.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Mr. Speaker, Sir, the Minister has given a very detailed reply. In his reply, he has mentioned about the various schemes that are available for start-ups as well as for research and development. But unfortunately, I could not find any mention about the National Research Foundation in the reply. This had been announced by the Finance Minister in her Budget Speech of 2021-22 and she had allocated Rs. 50,000 crore for this. The idea was to spend Rs. 10,000 crore per year. But unfortunately, there is no mention about this. So, I would like to know from the Minister whether any proposal has been mooted to form the board to

run the National Research Foundation. If it has been formed, I would like to know whether the money has been spent in the last one year. Can the Minister elaborate on that?

SHRI JITENDRA SINGH: Sir, I appreciate the memory of the hon. Member. It was, indeed, announced in the Budget of 2021-22. But we are still working on it. That is why, it has not been included, because it has not yet been finalised. The National Research Foundation (NRF) concept was mooted. What has happened was, there was some mismatch between the funding and the research. In certain cases, a lot of funding went through the universities, whereas the research was happening in scientific institutes. So, we have tried to bring some kind of uniformity so that there could be a channel which could be uniform for funding and now we are also trying to evolve a single portal to avoid overlapping. For example, JRS examination is conducted by different agencies and this examination is held three or four times in a year. We are trying to streamline it. We are working on the concept of the National Research Foundation. The process is going on. It is not yet finalised. That is why, it was not included.

The reason is, it requires a very exhaustive exercise, because we are going to overhaul the entire process and if any loophole is left, then again, we will be on the backfoot. But we are working on it. The Principal Scientific Advisor to the Government is also actively involved in it.

PROF. SOUGATA RAY: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has mentioned Bharat Biotech company as an example of a successful start-up. The people from Andhra Pradesh are saying that they are all proud of Bharat Biotech. The founders of Bharat

Biotech, Shri Krishna Ella and Shrimati Ella have also been awarded Padma Bhushan by the Government of India. Bharat Biotech was producing Covaxin. But I saw in newspapers that the manufacture of Covaxin has been stopped, because the WHO has said that the manufacturing quality is not up to the mark.

They should stop producing the vaccine, and they should do up their manufacturing facility.

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

PROF. SOUGATA RAY: Since it concerns COVID vaccination, would the Minister kindly tell us, what is the position with regard to Bharat Biotech, which he mentioned earlier, which is a manufacturer of Covaxin?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, there is a famous proverb in the English language: 'Success has many fathers." So, responding to the first part of the hon. Member's supplementary, yes, it is right. Now, Bharat Biotech is being owned by more than one State because the person whom he named – Krishna Ella -- is a very successful entrepreneur. He was born in Chengalpattu District of Tamil Nadu. Then, he got himself trained in Bengaluru, Karnataka; and has some roots in Andhra; and then he got funded from this Department.

So, now that he is successful, everybody would own him, and there is no harm in doing so.

Now, as far as the second part of his Supplementary is concerned, of course, the nasal vaccine is now under trial; and we have not yet put it for manufacturing purposes.

As far as the credibility of Covaxin is concerned, I leave that to the Health Ministry to respond to because we are directly not engaged in that policy … (*Interruptions*)

As far as we are concerned, we conducted the trials which were successful, and then only it was developed and used for vaccination.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 485, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव।

(Q. 485)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO: Sir, India has played a leading role in launching the 'Mission Innovation', a global initiative during the COP-21 in 2015; and it continues to play a pivotal role in the 'Mission Innovation' programme by participating in various areas of Clean Energy Innovation Challenges through collaborative projects and also supporting start-ups at their early stage of innovation.

In fact, under the leadership of our hon. Prime Minister, India has climbed 35 spots on the Global Innovation Index from being ranked 81st in 2014 to 46th in 2021. So, now, we are in the second phase of the Mission Innovation for five years from 2021 to 2025.

My supplementary to the hon. Minister is, what goals/targets have been set under the 'Mission Innovation-2', and what are the initiatives taken by India so far?

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I thank the hon. Member for asking this question. You would also be glad to know that the 'Mission Innovation' was born somewhere in 2015, and it was a follow up of the COP-21 meeting which was attended by our hon. Prime Minister. It is a matter of pride for us that the nomenclature 'Mission Innovation' was also suggested by Shri Narendra Modi. Then, it was adopted. Now, we have 22 countries, which are the Members of this Mission. Broadly speaking, in a single sentence, the objective is: research and development of clean energy, which is attractive, which is affordable, and which is accessible to all. In that direction only, the Mission-2 has also been taken up as a follow up. Also, we have engaged in wider synergism. Only two days back, we had bio-refineries understanding under the

Mission Innovation in which we are engaged in a 'private-public alliance', which they call in their parlance; and here we call it 'participation' with other countries like Netherlands etc. So, we are trying to integrate not only the public sector but also the private sector, not only domestically, even across. It is because the stakeholders are widespread. There has to be a synergism between the academia, between the industry, between the start-ups and also among the researchers because otherwise it is not possible to have sustainable start-ups as I said.

But I am glad that now 'Mission Innovation' in the second phase has categorised itself in different sections, and we are now catering separately for rural areas, for farmers, for young start-ups, and for women. So, I can give her the details if she wants. I still have it also. If she is interested, I can read out also, but I do not think the hon. Speaker will allow that kind of time.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO: Thank you hon. Minister. My second supplementary is very small.

In your reply, it is mentioned that 36 Biotech-KISAN Hubs have been established in collaboration with ICAR in a number of districts including the Aspirational Districts.

Sir, mine is an Aspirational District. I would not be restricted to that. I would like to know how many Biotech-KISAN Hubs have been set up in Odisha, especially, in Bolangir District. If not, is it likely to be established in the near future?

DR. JITENDRA SINGH: You are right, I have mentioned it there. We have set up a programme called Biotech-KISAN as a part of our mission 'innovation'. It is meant for enhancing and coordinating various Central and State Departments for

biotechnological interventions in the farming sector to help both, the women as well as farmers. There are 15 agro-climatic zones in the country which have also been taken into consideration. We have 25,000 households across the country. I am not carrying specifically the Odisha part. I have a State-wise long list but it will take much time. I will separately provide you the Odisha list.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. जयंत कुमार राय – उपस्थित नहीं।

क्वेश्चन नंबर 486 – श्री चंद्र शेखर साहू।

(Q. 486)

*__SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU:__ Sir, I have taken your permission to speak in Odia. Hon'ble Speaker Sir, my question relates to the Handloom sector. I have received the reply but I am not satisfied. The reply clearly mentions that Covid pandemic has adversely affected the Handloom sector in the last two years. No survey has been conducted to assess the impact on the weaver's community. In Odisha also no survey has taken place. In fact there is no specific announcement regarding any special package for the weaving community.

माननीय अध्यक्ष : आपका मूल प्रश्न क्या है?

श्री चंद्र शेखर साहू : सर, मैं उस पर आ रहा हूं।

*Sir, in my constituency, there are a sizeable number of weavers. In Odisha, Berhampur, Bargarh and Sambalpur are places where most of the weavers reside. That is why I expected a specific financial package from you. As we all knew in the last 2 years the pandemic has completely destroyed their livelihoods. They had to work, nor was there any demand for this craft or produce. So their economic condition is in shambles.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से उन्होंने चिंता जताई है कि कोविड महामारी के समय सिर्फ वीवर्स के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसका असर हुआ था और सभी क्षेत्रों को उसका सामना करना पड़ा। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 20 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

गया और उसके बाद ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई थी। कोविड के समय हमारे यहां मास्क नहीं बनते थे।

लेकिन लाइवलीहुड कम्पनियों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से हमने उसकी शुरुआत की। सबसे पहले वर्ष 2020 में 'वोकल फोर हैंडमेड' और वर्ष 2021 में 'वोकल फोर माइ हैंडलूम माइ प्राइड' दोनों को हैश्टैग करके सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सभी केन्द्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने तरीके से इस अभियान में उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जागृत किया है।

हैण्डलूम की चीजें किस तरह से खरीदी जाएं, किस तरह से उनको बढ़ावा मिले, इसका प्रयत्न शुरू भी किया गया। जब कोविड के हालात पैदा हुए, तब सबसे ज्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग स्किल को बढ़ावा दिया गया। कोविड के समय यह विशेष अभियान चलाया गया। पहले 6 हज़ार लोग जैम पोर्टल पर ऑनलाइन थे, अब, कोविड के बाद से कम से कम हम लोगों ने डेढ़ लाख वीवर्स और संगठनों को पोर्टल पर ला कर उनको मदद की और उनकी बिक्री 1 लाख 35 हज़ार करोड़ रुपये की हुई है। ये आंकड़े 28.02.2022 तक के हैं। जो मार्केटिंग की स्किल है या जो बुनकरों की स्थिति है, उसमें बदलाव करने के लिए काफी प्रयत्न किए गए। सभी राज्यों ने भी बहुत सारे सहयोग किए। क्योंकि सभी मुख्य मंत्रियों को भी कहा गया था कि बुनकरों को सपोर्ट करें। इसमें ज्यादातर केरल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों ने, उसी समय उनकी जो छोटी कंपनियां होती हैं, जैसे एपेक्स सोसाइटी तमिलनाडु में है, बोयानिका, कोप्टेक्स, तंतुजा के माध्यम से भी इन चीजों की खरीदी की गई और बुनकरों की स्थिति सुधारने में हम लोगों ने काफी प्रयत्न किया।

[*]**SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU:** Is the Central government planning to launch any special scheme for their betterment? Hon'ble Minister referred to Self Help Groups. Let me tell you that in Odisha maximum number of people are engaged in Self Help Groups. There are many SHGs which have been established by Shri

[*] English translation of the speech originally delivered in Odia.

Naveen Patnaik. The Chief Minister has announced a package for waver community as well as ancillary supporting workers. But the Central government is yet to announce any such special package. So far as I know SHGs have no connection with the Handloom sector. HSGs are mostly doing tailoring jobs. Like stitching of masks. They are not weavers. My second supplementary question is regarding the Central Silk Board team who were invited by Berhampur Municipal Corporation to do a local survey. I want to knew what is the status of that survey report and what are the recommendations?

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाज़िब है, लेकिन सबसे ज्यादा वीवर्स भी ओडिशा में हैं। हम लोगों ने 5,297 वीवर्स को इसके लिए सहायता प्रदान की है। उनका कौशल उत्पन्न किया है और 82 बुनकरों को वर्कशेड की सहायता दी गई है।

श्री राहुल रमेश शेवाले : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सप्लिमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। महोदय, हैण्डलूम सैक्टर के बारे में मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से रिप्लाई दिया है। मंत्री जी सूरत से ही आते हैं तो टैक्सटाइल्स की प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा पता हैं। टैक्सटाइल मिनिस्टर के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है।

नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन के तहत मुंबई में टैक्सटाइल मिलों के हज़ारों श्रमिकों की दयनीय हालत के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कोविड-19 महामारी के दौरान एनटीसी के अधीन मुंबई के 4 टैक्सटाइल मिलों को बंद कर दिया गया था। तभी से इन मिलों के मज़दूरों को वेतन का महज़ 50 पर्सेंट ही मिल रहा है। वह भी 2-3 महीनों के बाद मिलता है, जिससे उन्हें परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़। आपको उत्तर का समय नहीं मिलेगा, आप प्रश्न बोलते रहो।

… (व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले : अध्यक्ष महोदय, लास्ट कह रहा हूँ। … (व्यवधान) उन मिल मज़दूरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन दिन खराब होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन टैक्सटाइल मिल्स को चालू कर के मिल मज़दूरों को 100 पर्सेंट तनख्वाह दी जानी चाहिए। वे मिल मज़दूर जिस घर में रहते हैं, वे हैबिटेट कंडीशन में नहीं हैं। बारिश में वे घर गिर सकते हैं। तो क्या मंत्रालय के माध्यम से उनको पक्के घर देने की योजना है? … (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: अध्यक्ष महोदय, मुंबई की सभी और एनटीसी मिलें जहां पर भी लगी हुई हैं, वहां के सांसदों ने यह चिंता व्यक्त की है। यह हैण्डलूम से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। फिर भी एनटीसी मिल के बारे में लिए गए निर्णय के बारे में हम लोग आपको भविष्य में बता देंगे।

12.00 hrs

श्री रामशिरोमणि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौखिक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आप एक मिनट में अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री रामशिरोमणि वर्मा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश भर में हथकरघा के क्षेत्र में कोरोना महामारी की वजह से हथकरघा बुनकरों के व्यापार और आय काफी प्रभावित हुए हैं। … (व्यवधान)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: बुनकरों के लिए प्रोड्यूसर कंपनी बनायी गई है। खासकर उन्होंने यू.पी. के बारे में बोला है। मैं बताती हूँ कि वहाँ से जो ऑनबोर्ड किया गया, उसके माध्यम से इस आर्टिज़न को 22 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी सात प्रोड्यूसर कंपनीज़ से मिला है। सभी राज्यों ने अपनी-अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनायी हैं, जिसके माध्यम से उन बुनकरों को सहायता प्रदान की जा रही है।

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 487 to 500

Unstarred Question Nos. 5521 to 5750)

(Page no. 45 to 671)

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.01 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

… (व्यवधान)

12.01 ½ hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Prof. Sougata Ray, Shri Vinayak Bhaurao Raut and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया है।

…(व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 – डॉ. जितेन्द्र सिंह।

… (व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7001/17/22]

(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अंतर्गत भारत के लोकपाल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7002/17/22]

(4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति परिलाभ) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीनों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 183(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीनों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7003/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते की ओर से, मैं मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7004/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.

बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 7005/17/22]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7006/17/22]

(3) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7007/17/22]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7008/17/22]

(6) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7009/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री पंकज चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)

(2021 का प्रतिवेदन संख्या 25) - मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयुध निर्माणियां और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

[Placed in Library, See No. LT 7010/17/22]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- वर्ष 2019-2020 (01.04.2019 से 30.10.2019) के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जम्मू-कश्मीर सरकार) (2021 का प्रतिवेदन संख्या 3)।

[Placed in Library, See No. LT 7011/17/22]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रकों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्या 4)।

[Placed in Library, See No. LT 7012/17/22]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- 31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए संघ राज्यक्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन) (2022 का प्रतिवेदन संख्या 1) ।

[Placed in Library, See No. LT 7013/17/22]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए वित्त लेखा खंड-एक।

[Placed in Library, See No. LT 7014/17/22]

(दो) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए वित्त लेखा खंड-दो।

[Placed in Library, See No. LT 7015/17/22]

(तीन) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए विनियोग लेखा।

[Placed in Library, See No. LT 7016/17/22]

(चार) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए वित्त लेखा खंड-एक।

[Placed in Library, See No. LT 7017/17/22]

(पांच) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए वित्त लेखा खंड-दो।

[Placed in Library, See No. LT 7018/17/22]

(छह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए विनियोग लेखा।

[Placed in Library, See No. LT 7019/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7020/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 7021/17/22]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub- Section 13B of the Central Silk Board Act, 1948:-

(i) S.O.610(E) published in Gazette of India dated 11th February, 2022 notifying the nomination of following Officers, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this Notification.

(ii) S.O.611(E) published in Gazette of India dated 11th February, 2022 notifying the nomination of the Joint Secretary (Silk), Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi to serve as a member of the Central Silk Board for a period of three years with effect from 26.02.2022, subject to the provisions of this Act.

(iii) S.O.293(E) published in Gazette of India dated 21st January, 2022 notifying the nomination of the members of Rajya Sabha having been duly elected to be Member of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 22.12.2021 or till completion of their term in Rajya Sabha, whichever is earlier, subject to other provisions of the Act.

(iv) S.O.5158(E) published in Gazette of India dated 13th December, 2021 making certain amendment in Notification No. S.O.4589(E) dated 20th December, 2019.

(v) S.O.2984(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2021 notifying the nomination of the persons, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act.

(vi) S.O.4990(E) published in Gazette of India dated 6th December, 2021 notifying the nomination of the persons, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act.

(vii) The Central Silk Board Silk-worm Seed (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. G.S.R.861(E) in Gazette of India dated 16th December, 2021.

(5) Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iv) to (vii) of (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 7022/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7023/17/22]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for

the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7024/17/22]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7025/17/22]

12.03 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

1. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th April, 2022 agreed without any amendment to the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30th March, 2022."
2. "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th April, 2022 agreed without any amendment to the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30th March, 2022."

———

12.03 ½ hrs

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 5 अप्रैल, 2022 को सभा में प्रस्तुत अपने सातवें प्रतिवेदन सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:-

1. श्री संजय शामराव धोत्रे	31.01.2022 से 11.02.2022
	14.03.2022 से 08.04.2022
2. श्री चौधरी मोहन जटुआ	06.12.2021 से 21.12.2021
	31.01.2022 से 11.02.2022
3. श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय	31.01.2022 से 11.02.2022
सिंह	14.03.2022 से 08.04.2022
4. श्री मोहम्मद आज़म खां (जब से	30.11.2021 से 22.12.2021
त्यागपत्र दिया है)	31.01.2022 से 11.02.2022
	14.03.2022 से 22.03.2022
5. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	13.12.2021 से 22.12.2021
	31.01.2022 से 11.02.2022
	14.03.2022 से 25.03.2022
6. श्री सुखबीर सिंह बादल	13.12.2021 से 22.12.2021
	31.01.2022 से 11.02.2022
	14.03.2022 से 27.03.2022
7. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट	14.03.2022 से 29.03.2022

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हाँ।

माननीय सभापति: अनुमति प्रदान की जारी है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

———

12.04 hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

Statement

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएच.डी में प्रवेश और शिक्षकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय पांच में शामिल सिफारिशों के संबंध में अंतिम उतरों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

Statements

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, while expressing solidarity with my Party, I beg to lay the Statements (Hindi and English versions) showing further Action Taken by the Government on the following Reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology (2021-22):-

(1) Twenty-eighth Action Taken Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-second Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Communications (Department of Posts).

(2) Twenty-ninth Action Taken Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-third Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(3) Thirty-first Action Taken Report (17th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-fifth Report (17th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2021-22)' of the Ministry of Information and Broadcasting.

_____

12.04 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

13th Report

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं 'सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की तेल संस्थापनाओं की संरक्षा और सुरक्षा – चक्रवात तौक्ते के दौरान पश्चिमी अपतट में हुई दुर्घटना के विशिष्ट संदर्भ में' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

169th Report

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): I beg to lay the 169th Report (Hindi and English versions) on Action Taken by Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its One Hundred and Sixty-first Report on 'Review of the Intellectual Property Rights Regime in India' of the Standing Committee on Commerce.

12.05 ½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

33rd Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to present the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee.

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): महोदय, मधुबनी लोक सभा अंतर्गत दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित अहिल्या स्थान ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है।... (व्यवधान) कथाओं के अनुसार माता अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी तथा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं।... (व्यवधान) हिन्दू परम्परा में इन्हें सृष्टि की पवित्रतम पाँच कन्याओं में से एक गिना जाता है और इन्हें प्रात: स्मरणीय माना जाता है।... (व्यवधान) कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से इसी स्थान पर भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया और तत्पश्चात् ईशान कोण से चलते हुए, ऋषि विश्वामित्र के साथ विदेह नगरी जनकपुर पहुँचे।... (व्यवधान) इस पौराणिक स्थल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है।... (व्यवधान) वहीं वर्ष 2013 में ही इस स्थल का पुरातत्व विभाग, भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है।... (व्यवधान) तथापि वर्षों से पुराने मंदिर वहाँ अवस्थित हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।... (व्यवधान)

मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्री से आग्रह करता हूँ, माँग करता हूँ कि वहाँ पर जो मंदिर है, वह एक ऐतिहासिक मंदिर है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसका जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है।... (व्यवधान) मैं सरकार से ऐसी माँग करता हूँ, धन्यवाद।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैं कहना चाहता हूं कि जब यूक्रेन की सिचुएशन पर चर्चा के लिए इन लोगों ने पूछा था, तब डिटेल में चर्चा हो गई है। ...(व्यवधान) माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने इंटरवीन करते हुए पूरा डिटेल में उत्तर दिया।...(व्यवधान) इन लोगों ने ही मांगा था कि यूक्रेन पर चर्चा हो जाए।...(व्यवधान) उसमें इंटरवीन होते हुए, पेट्रोलियम मंत्री ने डिटेल में उत्तर दिया और अभी माननीय विदेश मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं।...(व्यवधान) क्या ये लोग चर्चा नहीं चाहते हैं?...(व्यवधान) ये लोग क्या चाहते हैं?...(व्यवधान) I appeal to them to kindly participate in the debate. The hon. External Affairs Minister would like to reply in detail. Kindly listen to the reply. This is my appeal. ... (*Interruptions*)

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में दक्षिण-पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत चक्रधरपुर रेल मंडल में पिछले दो वर्षों से पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर लोकल ट्रेन,

डीएमयू एवं ईएमयू ट्रेन्स का परिचालन रेलवे मंत्रालय द्वारा बंद कर दिया गया है।...(व्यवधान) इसमें मुख्य रूप से उत्कल एक्सप्रेस, साउथ बिहार, इस्पात एक्सप्रेस, टाटा-एर्नाकुलम, शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-संबलपुर एक्सप्रेस, टाटा-बिलासपुर ईएमयू आदि ट्रेन्स बंद हैं।...(व्यवधान) रेलवे आम जनों की बोली जाती है, लेकिन इन ट्रेन्स का परिचालन बंद है।...(व्यवधान) इसके अलावा आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं।...(व्यवधान) आमजनों के साथ आप आखिर न्याय कब करेंगे? ...(व्यवधान) पेट्रोल, डीजल के दाम भी कम किए जाएं।...(व्यवधान)

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।...(व्यवधान) विदित है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस में छूट के साथ ही आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतियोगी छात्रों और युवाओं को यह सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है।

महोदय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने वाले अधिकतर छात्र और युवा ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं दुर्बल आय वर्ग के परिवारों से आते हैं। इन्हें स्वयं को वर्तमान की कड़ी प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के लिए अपने आपको तैयार करने में ज्यादा समय देना पड़ता है।

जब तक प्रतियोगी अपने आप को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर पाते हैं, तब तक आयु की सीमा के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वर्ग के प्रतियोगियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रदेश जैसे गुजरात, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में इस वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 वर्ष तक आयु में छूट दी गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में प्रतियोगियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि युवाओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए देश और सभी प्रदेशों में ऐसे प्रतियोगियों की आयु सीमा एवं फीस में छूट प्रदान करने की कृपा की जाए। धन्यवाद।

12.11 hrs

At this stage, S/Shri Adhir Ranjan Chowdhury, T.R. Baalu, Dr. Farooq Abdullah and some other hon. Members left the House.

माननीय सभापति : श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर जी।

श्री दिनेश चन्द्र यादव जी।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, कोसी नदी पर 13.3 किलोमीटर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 10.1 किलोमीटर पूर्वी बकौर की तरफ से, 2.1 किलोमीटर पश्चिमी भेजा की तरफ से, 1 किलोमीटर एप्रोच का निर्माण होना है। इस निर्माणाधीन पुल क्षेत्र में 14 पंचायत अवस्थित है, जिसकी आबादी 1 लाख 75 हजार है। इसके बीच कई अन्य पथ भी हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, इसके बीच कोसी नदी भी है।

उक्त लंबे पुल के बीच कहीं भी पुल के ऊपर चढ़ने एवं उतरने की सुविधा नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस पुल के बीच आबादी में बने पथ से जोड़ने के लिए आंदोलन भी किया जा रहा है। इसी कोसी नदी पर ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर 4 लेन पथ पर एवं रेलवे लाइन पर 1.9 किलोमीटर पुल बना है।

माननीय मंत्री गडकरी साहब कई बार कह चुके हैं कि आम लोगों को विकास से जोड़ना है, ऐसे में 14 पंचायत के 1 लाख 75 हजार लोगों को छोड़ देना विकास यात्रा के विपरीत है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा मिले। जनहित में इस लंबे पुल के बीच 100 नम्बर पिलर के सामने पुल पर आने-जाने की सुविधा सरकार दिलाए। यही आग्रह हम आपके माध्यम से सरकार से करना चाहते हैं।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, मेरा प्रश्न इंटरनेट सुविधा से संबंधित है। हमारे देश में डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष बजट में घोषणा की है।

माननीय सभापति : आपका विषय नौसेना युद्ध पोत ट्राफी के बारे में है?

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सभापति महोदय, विषय चेंज कर दिया है।

माननीय सभापति : आपको बताना चाहिए था।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सभापति महोदय, हमारे देश में डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं। वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में घोषणा की है कि सभी को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्राहक अपने अकाउंट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस में मनी ट्रांसफर दूसरे बैंकों से भी कर पाएंगे। भारत सरकार की योजना सराहनीय है, लेकिन वर्तमान में सारे पोस्ट ऑफिस में मूलभूत सुविधा जैसे इंटरनेट का अभाव है। जहां इंटरनेट है वहां स्पीड बहुत कम है, इससे ग्राहक जिसमें किसान, वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको असुविधा होती है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स और कार्य अब ऑनलाइन होते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। देश में पोस्ट ऑफिसेज की कनेक्टिविटी दो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जाती है, प्राइमरी रूप से बीएसएनएल और एमटीएनल और सीफी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स द्वारा की जाती है। 12.10.2020 के जारी किए गए मेमोरेंडम के अनुसार पोस्ट ऑफिस इंटरनेट सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकडों के अनुसार एमटीएनएल और बीएसएनएल का वर्ष 2020-21 में 64 हजार 700 लिंक फेल्योर है। सीफी के 15 हजार 134 लिंक फेल्योर हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल का 4जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से संचालित नहीं हुआ है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव के कारण कार्य बाधित होता है, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान गाइडलाइन्स में संशोधन करके पोस्ट ऑफिस को ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वह ट्रांसपेरंट बिडिंग प्रॉसेस से अन्य नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवा ले सके जो बेहतर कनैक्टिविटी दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में सब पोस्ट ऑफिसेज़ में 4जी कनैक्टिविटी का प्रावधान किया जाए ताकि भविष्य में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से काम करने की घोषणा की जा सके।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairman Sir. I am very happy, hon. Railway Minister is here. I am raising a very important issue regarding the Silver Line project.

The Kerala Rail Development Corporation is a joint venture organization jointly established by the Government of Kerala and the Ministry of Railways, Government of India with 49 per cent equity. Am I correct, hon. Minister? Indian Railways has 49 per cent equity. I would urge the Ministry of Railways, Government of India, which holds 49 per cent equity, to withdraw and cancel its equity and stake from K-Rail, Kerala Rail Development Corporation on absolute ethical grounds as the Kerala Rail Development Corporation is nothing but an instrument of political agenda, a vehicle of vendetta against people, and a violator of the rights of people.

The K-Rail Limited unethically uproots people from their homes and properties in the name of establishing Silver Line. The Ministry of Railways must revoke and cancel all and any permissions sanctioned to the K-Rail including the Railway Board letter No. 2018, JV CELL/GEN/SPV-POLICY for land acquisition. The In-Principle Approval (IPA) that was granted by the Government of India for taking up pre-investment activities, including payment of land acquisition, detailed project report, construction of boundary wall, access roads, site offices, temporary construction must be revoked. … (*Interruptions*) Sir, it is a very important point. The hon. Minister is here. I want a reply from the hon. Minister.

I demand that the Finance Ministry must revoke and cancel any approval given by it to the Kerala Government to obtain external or bilateral loan. In Kerala, on the K-Rail issue, the BJP party is also agitating but the Ministry of Railways, Government of India has given in-principle approval. The Ministry of Finance has also given approval for discussion with various international agencies for getting loan. On the one side,

you are agitating, from your party, hon. MoS, V. Muraleedharan is leading the agitation in Kerala, but here, what is your stand. … (*Interruptions*)

Sir, let me complete. The hon. Railway Minister is here. I am raising a very important issue. It is a very burning issue.

HON. CHAIRPERSON: The issue has been raised.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, we cannot go to our constituency because the Silver Line project is entering into all the properties, all the houses. They are putting the stones there. … (*Interruptions*) I am concluding. Chairman Sir, at least you have to be sympathetic with us please. … (*Interruptions*)

What I am saying is this. I want to know from the Government that on the one side BJP party is agitating against this project in Kerala… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are not concluding.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am concluding.

HON. CHAIRPERSON: So, conclude then.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are a very senior Member.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am a very disciplined Member in this House.

HON. CHAIRPERSON: Okay, now please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Whatever Chair advises, I always agree to it. But in my constituency, thousands of people are being thrown away because of this project. That is why I am very sentimentally and emotionally raising this issue. You must understand my feeling. The hon. Minister is here. The Government should clarify this. I am asking the hon. Minister, through you. … (*Interruptions*)

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Sir, thank you for giving me the opportunity for raising an important issue pertaining to the Railway Ministry in my Vizianagaram constituency.

Sir, construction of Limited Height Subway (LHS) line at level crossing at unmanned level VS-04 on Bobbili-Salur line is very essential for free movement of people and vehicular traffic to YSR Jagananna Nagar and YSR Jagananna colonies. If it is constructed, almost 17,000 people belonging to economically weaker sections would get benefit along with those who are getting *pucca* houses under the YSR Jagananna Nagar Urban Housing Scheme. I have already submitted a request to the DRM, East Coast Railways, Waltair Division, Vishakhapatnam with an estimated cost of Rs. 5.73 crore on 23.11.2021. However, it seems that no action has been taken by the officer concerned in this regard.

Hence, I would request the hon. Minister for Railways, through you, to kindly consider my proposal and see to it that sanction is accorded at the earliest.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, Assam and the North-East became a part of British India very late. But when the Britishers came to Assam, they introduced a local time in Assam, so that the administration could utilize and optimize efficiency and productivity in industrial activities. In the aftermath of Independence,

the IST has been imposed, and we are back to square one. The reason why I am telling you this is that in the eastern place of Arunachal Pradesh, there is a place called Jairampur and Vijaynagar, and from there to Jaisalmer and Gujarat, there is a difference of 30 degree longitude. That means that the time difference is almost two hours. When we have a single time zone, the people of the North-East are being discriminated because we lose precious day time hours and hence productivity. It creates a lot of problems. After Independence, with the imposition of IST, Assam became a land of *lahe lahe*, that means Assam became very slow. We want to optimize the productivity and efficiency, and that is why, we should have different time zones. You will agree with me that different nations across the world have different time zones. Bigger nations like USA have got 11 time zones; France has got 12 time zones. Why can we not have a separate time zone for the North-East to optimize and utilize the productivity of our people? That is my concern and that is my request to the Government of India.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the hon. Member is raising a very important issue. He has been raising it again and again. I would like to associate with him. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर - उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र गावित जी।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 42 खलासी आदिवासी मछुआरे पिछले 3 महीने से लापता हैं। गुजरात में अधिक मजदूरी मिलने के कारण गुजरात में जो ओखा और पोरबन्दर है, वहां से पालघर के तलासरी, दहाण और पालघर विक्रमगढ़ तालुका के काफी आदिवासी

युवक मछली पकड़ने के लिए गुजरात जाते हैं। गुजरात में पाकिस्तानी बॉर्डर पर, अशिक्षित होने के कारण गलती से पाकिस्तानी सीमा के आगे जाने के कारण, पाकिस्तान सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

सभापति महोदय, 347 भारतीय कैदी अभी भी लांधी जेल, करांची में हैं। वे वर्ष 2017 से जेल में हैं। जेल की अवधि पूरी होने के बावजूद भी भारतीय कैदी को रिहा नहीं किया जाता। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय कैदियों की राष्ट्रीयता की पुष्टि भी की है। लेकिन, भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौते के अनुसार उन्हें रिहा नहीं किया जाता। जेल में बंद कम से कम 8 कैदी मेरे मतदार संघ के हैं। गुंडनपाड़ा, तलासरी से पालघर, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, जानकारी के अनुसार भारत के कुल 608 कैदी अभी भी पाकिस्तान जेल में हैं। इनमें से 347 कैदी अपनी जेल सजा पूरी कर चुके हैं।

सभापति महोदय, ऐसा ही एक इंसिडेंट 6 नवम्बर को हुआ था। श्रीधर चामड़े की पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने ओखा और पोरबन्दर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैं आपके माध्यम से फॉरेन मिनिस्टर की से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 42 खलासी आदिवासी मछुआरों के बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करके शीघ्रातिशीघ्र पता लगाया जाए और आदिवासियों को न्याय दिलाया जाए।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के जो गरीब तबके के मरीज हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको सुविधाएं देने के लिए 200 शय्या का मातृ शिशु चिकित्सालय बनाया गया है। वह निर्मित हो गया है। उसको कोरोना कार्यकाल के दौरान कोरोना सेंटर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था और उसमें कोरोना के मरीज भर्ती किए गए थे। कोरोना खत्म होने के बाद इस समय उस अस्पताल का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

महोदय, चित्रकूट के जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड में भीड़-भाड़ बनी रहती है तथा जगह का भी अभाव रहता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बेडों की कमी होने के कारण जमीन पर लिटाकर ही उनका इलाज किया जाता है। इसी प्रकार से जनपद बांदा में भी 300 शय्या का उच्चीकृत मंडलीय चिकित्सालय का निर्माण कराया जा चुका है। किंतु वहां पर स्टॉफ की भर्ती नहीं हो पाई है और अभी तक मशीनरी उपकरण भी नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण बांदा और चित्रकूट के अस्पताल चालू नहीं हो पाए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट और बांदा में जो मातृ शिशु चिकित्सालय निर्मित हो चुके हैं, एक 300 शय्या और दूसरा 200 शय्या का है, उनमें स्टॉफ की भर्ती करके उनको तत्काल चालू कराया जाए।

माननीय सभापति : श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी – उपस्थित नहीं।

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर जी।

*__श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद):__ Hon'ble Chairman Sir. Thank you very much.

Today, I would like to share and express the pain and agony of EPA 95 pensioners. Around 70 lac EPS 95 pensioners are there and Rs.417 or Rs.541 or Rs.1250 per month would be deducted from their salaries during service time. After their retirement now they are getting only Rs.500-2500 as a monthly pension. How can they manage with this meagre amount when the inflation is all time high? The government needs to think about it.

Koshyari Committee was constituted to look into it and the same committee had recommended to give Rs.7500 plus dearness allowance eight years ago. But, it has not been implemented till date. Supreme Court had also given an order in this regard on 04/10/2016 and that is also not followed.

Hence, through you, I would like to request the Central government to look into it urgently because the pensioners are agitating for fulfillment of their demand. Justice should be done to them by sanctioning a pension of Rs.7500 per month to each one of them.

Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member. … (*Interruptions*) What is the Supreme Court doing in it? … (*Interruptions*) The Supreme Court has not even constituted the Bench for hearing the case of EPS-95. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly send slips to the Table.

… (*Interruptions*)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : सभापति महोदय, मैं मराठी भाषा में अपनी बात रखना चाहता हूं।

*Hon'ble Chairman Sir, we have been demanding the Central government to grant classical language status to Marathi for the last many years. But, the Central government is deliberately ignoring our demand.

Marathi language has many dialects and it has a glorious history of 2200 years.

In the famous Epic Dyaneshwari, Marathi is regarded to be sweeter than nector. Marathi language has got a great literary tradition and many great Marathi authors like Sant Dyaneshwar, Sant Tukaram, VS Khandekar, Vinda Karandikar, PL Deshpande, Bhalchandra Nemade, Mangesh Padgaonkar and others have contributed to Marathi literature. Every Maharashtrian has the feeling of pride and honour for Marathi.

All the people of Maharashtra love Marathi language from the core of their hearts. They have a very strong feeling for it. We have a divine bonding with Marathi.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

Hence, I would like to request the Central government to respect the sentiments of all Marathis and grant the status of classical language to Marathi language as early as possible.

Thank you,

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Sir, at the outset, let me congratulate the Department for the whopping increase in the budgetary allocation under the PMGSY scheme for the fiscal year - 2022-23. As you are aware, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was launched by the Government of India to provide connectivity to unconnected habitations as part of a poverty reduction strategy.

As the budgetary allocation under the said scheme is raised by 36 percent to Rs. 19,000 crores, I would like to apprise you that since the past three years, Maharashtra as a State is being neglected.

There has been no construction of new roads under the PMGSY and this pains my heart. I would request you to kindly intervene and issue fresh directives to your Department so as to consider the list of proposals sent by the Government of Maharashtra under the PMGSY - Third Phase. The proposal along with the DPR is sent to the Central Government, Department of Rural Development. For the past six months, the same is pending. I would like to request the Government, through you, Sir, to sanction the same immediately without any further delay to rectify injustice meted out to Maharashtra, especially my Raigad parliamentary constituency.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहनें, जो कि सेवा भाव से काम करती हैं, उनकी एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना

चाहता हूँ। चूँकि भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति भारतवासियों का इमोशनल झुकाव रहता है। हमने भारत के भू-भाग को भी माँ माना है तथा हमारे यहां दैवीय शक्ति के रूप में देवताओं से पूर्व महिला शक्ति को सर्वोपरी माना है। नवरात्रों के इस पर्व के वक्त भी हम शक्ति दायिनी माँ भगवती को ही मानते हैं, जो अधर्मी लोगों का विनाश करती है, लेकिन वहीं दिल्ली का मुख्य मंत्री खुद पीड़ित बनकर रेडियो और टेलीविजन पर अपने …* को ढकने का प्रयास करता है तथा लोकतंत्र में 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' के समर्थन में कहता है कि यह आदमी का फंडामेंटल राइट है और वह अपनी बातें रख सकता है। शाहीन बाग, गाजीपुर बॉर्डर तथा सिंधु बॉर्डर पर सड़क रोकने वाले लोगों को भोजन परोसा जा रहा था और इसके लिए वह कहता है कि यह उनका अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के कसीदे पढ़ने वाले मुख्य मंत्री द्वारा दिल्ली में लगभग 10 हजार आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी कुछ जायज मांगों के लिए दिल्ली के मुख्य मंत्री के घर धरना दिया था। जो बहनें मामूली से मेहनताने पर गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करती हैं तथा वे उन्हें कुपोषण जैसी बीमारी से बचाने के उपायों के साथ-साथ केन्द्र व राज्य सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का काम करती हैं और अपना सम्पूर्ण जीवन सेवा में लगाती हैं। मेरी दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि जिन 10 हजार बहनों को सस्पेंड किया गया है, वे केवल अपनी बात रखने के लिए धरने पर बैठी थीं, इसलिए उनके साथ न्याय किया जाए। मैं आपके माध्यम से यह बात सदन में रखना चाहता हूँ। धन्यवाद।

* Not recorded

*श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): Thank you, Sir. I want to draw your attention towards the plight of farmers who are residing on the Indo-Park border in Punjab. In Punjab, Gurdaspur, Pathankot, Ferozepur, Tarn Taran, Amritsar etc. share 438 kms. of border with Pakistan. Barbed wire fencing of the entire border area has been done.

Sir, the agricultural land of these farmers lies beyond the barbed wire fence and they do farming there. Gates have been installed there and farmers get hardly 4 or 5 hours to do the farming. The government has accepted giving Rs.10,000/- per acre, per year to the farmers. Even this compensation amount is not given in a timely manner. When I was elected an MP in 2017, at that time, I found out that compensation amount had not been granted to the farmers from 2012-2017. After repeated pursual and reminders, this compensation amount was granted to them. However, the compensation due to the farmers have not been paid till now from 2017 to 2022. This backlog amount is pending. Only one installment has been paid. Four installments of compensation amount is yet to be paid. Sir, in Amritsar district, in Tehsil Ajnala, Lopoke and Attari, over 380 hectares of such land falls outside the barbed wire fence. A sum of Rs.3,38,12,401/- is yet to be paid to these hapless farmers as compensation. This is the amount to be paid for one installment. Five such installments are yet to be paid to the farmers. Sir, during war with Pakistan, these farmers 'help you' counter the enemy...

HON. CHAIRPERSON: Don't call it 'you help'. Call it 'our help'. The farmers are Indians.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA: O.K. Sir. I am sorry. The farmers provide us help. When India was balkanised and Pakistan created, the border area farmers suffered the most. Sir, the compensation of our farmers must be granted to them. Delays should not be there. These are small and marginalised farmers who have only 2 or 4 or 5 acres of land, They are not rich farmers.

So, I urge upon the government to release the 4 installments of compensation amount to the farmers of Punjab, especially to farmers of my area.

Thanks.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): धन्यवाद, सभापति महोदय । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में आया है कि भारत सरकार द्वारा अरहर दाल के आयात को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके कारण अरहर दाल और तुअर के दामों में गिरावट देखी जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी फसल की कीमत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अत: मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अरहर दाल के आयात पर तत्काल जून महीने तक रोक लगाई जाए, ताकि किसानों की निकाली हुई तुअर की फसल बाजार में बिक सके और अरहर दाल को उचित दाम मिल सके। अगर आवश्यकता पड़े तो आवश्यकतानुसार अरहर दाल का आयात किया जाए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस संबंध में अवश्य निर्देश देते हुए किसानों के हित में कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Respected Sir, I would like to bring to the notice of this House how primitive our procedure for the assessment of a disaster situation is.

Firstly, the time taken to constitute a disaster assessment team and to deploy it to a site after a disaster has struck is lengthy, often taking several weeks after a disaster has struck. It takes even more time for the team to be constituted, a plan to

be developed and logistics to be arranged for these teams to assess the site of a disaster. The methods of assessment are also primitive and are done manually as opposed to being mechanized and digitized. After a few weeks pass from the occurrence of a natural disaster, important information regarding the intensity of the disaster is lost and the severity is underplayed due to ineffective assessment modules. The requisite assistance is not provided. Particularly for coastal States like my State, natural disasters such as floods and cyclones keep coming due to our geography.

Through you, Sir, I request the Minister of Home Affairs to improve our disaster assessment mechanism so that the States are supported in the correct way during their time of need.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक विषय को मैं पिछले पांच साल से सदन में उठा रहा हूं। आप जानते हैं कि मुंबई शहर में बीडीडी चॉल के काम्प्लेंक्सेस हैं - वर्ली, नायगांव, नामाजोशी मार्ग और सिवड़ी । इनमें से तीन काम्प्लेक्स राज्य सरकार की जमीन पर बने हैं। राज्य सरकार ने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि ये जो बीडीडी चॉल करीब 100 साल पुरानी हैं और गिरने वाली हो गई हैं, उनका पुनर्विकास करने के लिए राज्य सरकार ने एक कानून बनाया है। अब उसमें उन लोगों को 650 स्क्वायर फुट जगह फ्री में मिलने वाली है। सिवड़ी में एक बीडीडी चॉल का काम्प्लेंक्स है, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की लैण्ड पर स्थित है। अब उसके लिए आज तक केंद्र सरकार से परमीशन नहीं मिल रही है। उसकी वजह से इसका काम शुरू नहीं हुआ है, बाकी तीन काम्प्लेक्सेस का काम शुरू हो गया है। वहां 680 लोग रहते हैं, 80 परिवार रहते हैं। उसमें खाली जमीन मिलेगी, जिसे बीपीटी और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन आपकी अनुमति के बिना राज्य सरकार कदम नहीं उठा पा रही है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बहुत देर हो गई है, देर आए दुरुस्त आए, जल्दी दुरुस्त हो जाएं और

जल्दी से जल्दी उसकी अनुमति प्रदान करें, ताकि उन बिल्डिंग्स के पुनर्विकास का जो काम राज्य सरकार कर रही है, उसको समर्थन मिले। धन्यवाद।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लो महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्व को सम्बद्ध किया।**
Shri Pradyut Bordoloi	Shri Abdul Khaleque
Dr. Shrikant Eknath Shinde	Shri Gajanan Kirtikar Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Pavan Rajenimbalkar
Shri Shrirang Appa Barne	Shri Gopal Shetty Shri Arvind Sawant Shri Rajendra Gavit Shri Gajanan Kirtikar Shri Prataprao Jadhav Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Pavan Rajenimbalkar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rajendra Gavit	Shri Gopal Shetty Shri Gajanan Kirtikar Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Pavan Rajenimbalkar
Shri Om Pavan Rajenimbalkar	Shri Shrirang Appa Barne Shri N.K. Premachandran Shri Rahul Ramesh Shewale
Shri Prataprao Jadhav	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale

	Shri Om Pavan Rajenimbalkar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Arvind Sawant	Shri Shrirang Appa Barne Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Pavan Rajenimbalkar
Dr. Ramapati Ram Tripathi Shri Ramesh Bidhuri Shri Gurjeet Singh Aujla	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri R.K. Singh Patel	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Geeta Kora	Shri Malook Nagar

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आइटम नं. 17 पर बिल लगा हुआ है, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो आइटम नं. 18 में 'यूक्रेन में स्थिति' पर चर्चा है, पहले उसका रिप्लाई हो जाए, बिल बाद में ले लिया जाए। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति : ठीक है। आइटम नं. 18 को लेते हैं।

माननीय मंत्री जी, चर्चा का जवाब।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, एक बात है।

माननीय सभापति : इसको बाद में कर लेंगे। प्लीज आप बैठिए।

… (व्यवधान)

12.41 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

DISCUSSION UNDER RULE 193

Situation in Ukraine* – Contd.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Hon. Speaker, Sir, I first of all thank all the hon. Members for their views, concerns and sentiments about the ongoing situation in Ukraine. Yesterday, twenty-eight Members spoke on this subject, I listened to all of them with great attention, and all of them made some points of relevance and consideration.

Mr. Speaker, Sir, we strive to ensure that foreign policy is a subject of maximum consensus in the country. Certainly, that should be the case with a subject as important as Ukraine, and I was glad to see yesterday that was the case. I was also very pleased that four Ministers spoke on this matter because these Ministers went to the neighbouring countries, they participated in the evacuation operations, and they brought a ground perspective which was very important for the House to listen.

Hon. Members would all agree that India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest, and by our national strategy. Let me dwell on each of these aspects before addressing some of the specific issues that were brought up by hon. Members yesterday.

---

* Further discussion on the situation in Ukraine raised by Shri N. K. Premachandran on 5th April, 2022.

What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood, and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any dispute. And one should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states.

If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principled stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates including in the United Nations.

Sir, many hon. Members brought up the incident, the happenings in Bucha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation.

Sir, the conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications, and deciding what is best for our national interest. Members are aware that in a complex and globalised world every nation takes into account the reality of interdependence. Therefore, even as they express their position in words and deeds, they also adopt policies that safeguard the wellbeing of their population. As a result, we have seen, even in Europe, that energy flows continue despite tension. Similarly, a conscious effort was made to insulate the fertiliser market from volatility. There are numerous other measures and different domains including financial and payment

carve outs. Even non-essential goods that have salience for individual economies have been factored in the equation.

So, what should India do in these circumstances? At a time when energy costs have spiked, clearly, we need to ensure that the common person in India is not subject to an additional and unavoidable burden. Similarly, fertilizer prices have a direct implication for the livelihood of the majority of our population, and indeed for food prices, for all of us. Even the security of the nation is at stake as we maintain our defence posture in the manner that the current security challenges warrant. All these are legitimate pursuits of national interest by India. They are similar to what other nations are doing from their particular perspective. Attributing a political colouring to it is uncalled for; it is unfair. I do not even wish to get into which country is doing how much. Eventually, the numbers will speak for themselves.

Additionally, there was a natural concern for our citizens, especially our students who were trapped in conflict zones. The House will recall that I had made a *suo moto* statement on this subject. But some comments were made yesterday about 'Operation Ganga'. I would like to respond to that a little later.

Keeping these factors in mind, what should be our national strategy? The Government believes that it should have four elements. One, in terms of diplomacy, India continues to press forcefully for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia including at the level of their Presidents. The Prime Minister himself has spoken to them both in this regard.

This was precisely the message that was conveyed to Russian Foreign Minister Sergey Lavrov when he was in Delhi. If India can be of any assistance in this matter, we will be glad to contribute.

Two, the ground situation calls for urgent humanitarian relief. We have already provided 90 tonnes of relief material. I was glad to see that many hon. Members yesterday noted it and appreciated it. We did it even while we were in the middle of an evacuation. So, I think, that also is a factor that should be recognised. Ukrainian Deputy Prime Minister Yulia Svyrydenko called me a few days ago to request for supply of more medicines. The House will be glad to know that this is underway and delivery should start very soon.

Three, we will work with the international community and partner countries to mitigate the economic hardships that are resulting from this conflict. Obviously, our focus is to soften its impact on our own economy. But equally, there are partners who are going through very tough times. Coordinating on lowering energy prices is one collective initiative. In the case of a neighbour like Sri Lanka, we are even supplying fuel and food on credit. Food security is another major concern. India has been approached for the supply of wheat and sugar by many countries and we are responding positively. The House will be glad to know that whether it is basmati rice, non-basmati rice, sugar, wheat, our exports in the last quarter have gone up very, very substantially. We have delivered for the world in terms of vaccines. We did it earlier for medicines. So, I would like to assure the House, through you, that we will also step forward where global demands for food grains and other materials are

concerned, and we will do it in a manner that is helpful to the global economy, which will not take undue advantage of countries in distress.

Four, there are cases, there are issues like the supply of edible oil. Some Members referred to it yesterday because we import sunflower oil in very large quantity from Ukraine, or fertilizers that I spoke about.

Now, our commercial diplomacy has to find additional sources to address this disruption. There could be more such examples in the days to come. I would like to apprise this House, through you, that whether it is the supply of lentils, edible oils, or the requirement of raw materials for fertilisers, we are really looking today in different ways at global markets, from Mercosur to Kazakhstan, Tanzania, Australia, and Canada, to see how we can lighten the burden for the common people in India as a result of this crisis.

Let me say that overall, therefore, India's approach will be to promote dialogue, to end the conflict, and to mitigate economic distress for itself and for the world, and to work with its partners to these ends. I can also say that many other nations which have engaged us recently, at the level of the hon. Prime Minister and at my level, with other hon. Ministers, share such a view. Many of them are glad to work with us and many of them are pleased that we have taken the lead on many of these issues.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को 'ऑपरेशन गंगा' के बारे में बताना चाहता हूँ। कल इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। यह ठीक है कि हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारा जो अनुभव है, उसे भी यह सदन जाने। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जो चार मंत्री वहाँ गए, जिनका वहाँ डायरेक्ट यानी हैंड-ऑन तज़ुर्बा था, वे कल सदन के सामने बोल पाए।

'ऑपरेशन गंगा' के बारे में, मैं एक प्रकार से एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला इवैकुएशन ऐसा था कि हमारे स्केल में आज तक किसी देश ने इवैकुएशन नहीं किया। हमारे जो 20 हजार नागरिक आए और जो दूसरे देशों के नागरिक, जिनको हम भारत वापस लाए। यह काम किसी और देश ने नहीं किया। मैं यह भी कह सकता हूँ कि बाकी विदेश मंत्री, जिनसे मेरी बात होती है, कुछ ही दिन पहले यहाँ एक विदेश मंत्री आए। उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं अपने देश के नागरिकों से भरे दो प्लेन्स यूक्रेन से लाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने प्लेन आए? वे हैरान हो गए, जब मैंने कहा कि हमने अपने नागरिकों से भरे 90 प्लेन्स लाए। यह बात भी है कि जो बाकी देश हैं, वे हमारा उदाहरण देखकर, एक तरह से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि भारत कर रहा है, तो हमारी ओर से भी ऐसा कुछ करना चाहिए।

कल एडवाइज़री की बात हुई। यह स्वाभाविक है कि ऐसे क्राइसिस में लोग यह कहें कि आपने जल्दी की या नहीं की या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था या आपके शब्दों के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारी एडवाइज़री का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, तो हमारे चार हजार नागरिक कांफ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वे इसीलिए निकले क्योंकि उनकी समझ में आया कि एडवाइज़री का क्या महत्व होता है। हम हर रोज़ एडवाइज़री इश्यू नहीं करते हैं। जब किसी भी राजदूतावास की एडवाइज़री है कि जो नॉन-एसेंशियल लोग हैं, वे देश को छोड़कर घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं।

हाउस का यह पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, यह भी स्वाभाविक है। वे इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर स्टूडेंट्स हैं, एक जमाने में हम सब स्टूडेंट्स थे। जब कोई 20 साल का स्टूडेंट है, तो उसके मन में क्या होता है?

स्टूडेंट्स सबसे पहले यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइजर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनसे पूछते हैं। वे टेलिविजन में देखते हैं, न्यूजपेपर पढ़ते हैं। उनको उस समय लगा कि अगर वे उस समय यूक्रेन छोड़कर भारत चले जाएं, तो इससे उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी और उनको नुकसान पहुंचेगा।

यह फीलिंग इसीलिए हुई क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने उस समय ऑनलाइन-कोसेर्ज देने से भी इनकार कर दिया। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि कीव में एक यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन मोड पर कनवर्ट ही नहीं कर सकते। ओडेसा की एक यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम 25 फरवरी तक ही ऑनलाइन की सुविधा दे सकते हैं। खारकीव में जो यूनिवर्सिटी थी, उसको राजदूतावास फोन करता रहा, उन्होंने वहां किसी को भेजा भी, लेकिन वे तो मिलने के लिए ही तैयार नहीं थे। सुमी और विनित्सिया में दो और यूनिवर्सिटीज थीं, जहां हमारे विद्यार्थी काफी संख्या में थे। वे कह रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, लेकिन हमारी राय है कि आप रुक जाओ, यह इतना सीरियस नहीं होगा।

कल एक मेंबर ने हमें याद भी दिलाया, इसी समय रिपोर्ट्स भी निकलीं कि रूस अपनी फौज की कुछ यूनिट्स को वापस ले जा रहा है। मैं उस समय मॉनिटर भी कर रहा था, पर मैंने अपने लिए एक बार और चेक किया कि यूक्रेन की सरकार उस समय क्या कह रही थी? यूक्रेन की सरकार अपने देश और हमारे स्टूडेंट्स, जो उन्हीं के बीच में थे, उनसे कह रही थी कि आप पैनिक मत हो, इसको हम संभाल लेंगे। ओवरऑल सिग्नलिंग जो थी, उन्होंने हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को सचमुच एक किस्म से दुविधा में डाल दिया और इसीलिए चार हजार लोग यूक्रेन छोड़कर आए और बाकी 18,000 लोगों ने कहा कि हम अभी रुक जाते हैं और देखते हैं कि हालात सचमुच बिगड़ते हैं या नहीं।

कल मैं संसद में जो सुन रहा था, क्राइसिस के बाद कहना कि सबको निकलना चाहिए था या हमको ऐसे कठोर शब्दों में समझाना चाहिए था कि सब डर के मारे निकल जाएं, यह मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है, वह इसको पहचानता नहीं है। अगर हम सचमुच ग्राउंड के साथ जुड़े हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की मानसिकता को समझते हैं, तो हमें यह दुविधा भी समझनी चाहिए। ऑपरेशन गंगा के बारे में कल थोड़ी सी यह भी चर्चा ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): गलती स्टूडेंट्स ने की है? ... (व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर : अधीर रंजन जी, यह गलती नहीं थी। ... (व्यवधान) यही आपकी मेंटेलिटी है कि आप गलती ढूंढते हैं। ... (व्यवधान) क्षमा कीजिएगा स्पीकर सर। ... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You are passing the buck on to the students. … (*Interruptions*) मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। … (व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर : स्पीकर महोदय, यह साफ है कि ऐसी सिचुएशन में 22,000 लोग कलेक्टिवली एक निर्णय नहीं ले सकते। … (व्यवधान)

यह भी कल चर्चा हुई कि ऑपरेशन गंगा में क्या कुछ स्पेशल था? क्या यह पहले वाले इवैक्युएशन ऑपरेशन जैसा था या इसमें कुछ अलग था? आखिर के स्पीकर जनरल वी. के. सिंह जी ने बहुत ऑब्जेक्टिवली कहा कि हर ऑपरेशन एक किस्म से यूनीक होता है। कहीं युद्ध है, कहीं नहीं है, कहीं तनाव है, कहीं नहीं है। कहीं सिचुएशन कुछ और है।

कहीं हमने फौज का इस्तेमाल किया है, कहीं सिविलियन – एयर इंडिया का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन गंगा के बारे में मैं यह कहूंगा और मैं 45 सालों के अनुभव से कह रहा हूं कि जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने, इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं निकाला।

13.00 hrs

अध्यक्ष जी, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और इसमें क्या चुनौती थी, वह भी बताता हूं। आपको याद होगा कि हमने वर्ष 2015 में ऑपरेशन 'राहत' यमन में चलाया था। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी। प्रधान मंत्री जी ने सउदी अरब के राजा को फोन करके युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन वहां जाकर हमारे नागरिकों को वापस ला सकें। लेकिन इस समय लड़ाई जारी थी और युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अंत में दो शहरों में युद्ध विराम हुआ ताकि हम अपने लोगों को वहां से निकाल सकें। युद्ध विराम पूरी तरह से नहीं था, केवल दो शहरों में हुआ और बाकी जगह लड़ाई चल रही थी। वहां के नागरिक स्वयं देश से निकलने के चक्कर में थे। जब ऑपरेशन 'गंगा' चल रहा था, तब करीब 30 लाख यूक्रेन के नागरिक स्वयं यूक्रेन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। इस ऑपरेशन की दूसरी खासयित थी कि प्रधान मंत्री जी का इसमें पर्सनल इंटरवेंशन था। प्रधान मंत्री जी ने स्वयं फोन किया और लीडर्स से बात की। दो जगह हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, वहां युद्ध विराम कराया ताकि हमारे लोग

वहां से निकल पाएं। कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि इलेक्शन के कैलकुलेशन के कारण आपने कुछ चीजें नहीं कीं। मैं सदन को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैम्पेन के बीच में प्रधान मंत्री जी दिल्ली वापस आए और लीडर्स से बात करके मीटिंग की तथा डायरेक्टली सुपरवाइज किया। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूक्रेन में दो शहर सूमी और खारकीव थे, जहां हालात बहुत खराब थे। खारकीव में शैलिंग हो रही थी और आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी श्री नवीन की मृत्यु हो गई। सूमी में यूक्रेन और रशिया के बीच फायरिंग हो रही थी। हमारे माननीय सदस्य ने पूछा कि प्रधान मंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उन्हें बता सकता हूं कि मैं उनके साथ कमरे में था, जब उन्होंने खारकीव के विषय पर पुतिन साहब के साथ यह मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे विद्यार्थी डेंजर में हैं, क्योंकि खारकीव में फायरिंग हो रही है। उस बातचीत के कारण हमें इतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स खारकीव छोड़कर एक सेफ जोन, जो कि रशियन्स ने बताया कि यदि आप उस जगह जाएंगे, तो वहां फायरिंग नहीं होगी। सूमी से लोगों को निकालते समय फायरिंग हुई और एक समय तो विद्यार्थी बस में बैठ भी गए थे और हम निकलने वाले थे कि फायरिंग फिर से शुरू हो गई।

प्रधान मंत्री जी ने दोनों प्रेजीडेंट्स से बात की। चूंकि दोनों देश कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है और दोनों को समझाया कि इस समय से इस समय तक आप अपनी फौज को बताएं कि वे फायरिंग न करें। हमने यूक्रेन से सहायता ली, प्रोटेक्शन भी ली तथा रेड क्रास को भी साथ ले गए। सूमी का इवेक्यूएशन ऐसे हुआ। कल यह भी कहा गया कि एम्बेसी क्या कर रही थी? कुछ शहर थे जहां हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर नहीं पाए या हम वहां नहीं थे। एम्बेसी चूंकि राजधानी में होती है इसलिए काफी समय तक स्टूडेंट्स राजधानी में रहे। जब पश्चिमी बार्डर में हमारे बहुत सारे लोग फंस गए, तो हमने एम्बेसी को फेज वाइज, पहले आधी एम्बेसी को और फिर बाकी एम्बेसी लीवीव में गए, जो पश्चिम यूक्रेन में है। ताकि वे बॉर्डर के नजदीक हों और यूक्रेन के अंदर से स्टूडेंट्स की सहायता कर पाएं, क्योंकि हमारी टीम यूक्रेन की बाहरी सीमा में थी। पश्चिमी शहर जैसे खारकीव या सुमी में जो लोग फंसे हुए थे, वहां हमने लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखा। उनको निकालने की सहायता के बारे में कल थोड़ी-सी चर्चा हुई थी। मैं स्टूडेंट्स से क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो झेला है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। यह सत्य है कि

ज्यादातर लोग, जो वहां से निकले, वे ट्रेनों में निकले। स्पेशल ट्रेनें इसीलिए चलायी गयीं, क्योंकि हम लोगों ने यूक्रेन सरकार पर दबाव डाला और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स वहां पर हैं, अत: जब तक वे वहां से पूरी तरह से निकल न जाएं, तब तक आप ट्रेनें चलाते रहें। कुछ लोगों ने अलग से बसें लीं, कुछ लोगों ने कांट्रैक्टरों से संपर्क किया तथा कुछ लोगों के लिए हम लोगों ने बसों की व्यवस्था भी की।

सर, अब 'ऑपरेशन गंगा' पूरा हो चुका है और हमारे स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस समय हमें सोचना चाहिए कि हम लोगों ने साथ मिलकर क्या किया, कैसे किया। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ सबक भी हैं। हम जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं, चाहे 'ऑपरेशन राहत' हो या 'संकट मोचन' हो, तो हमारी मिनिस्ट्री में एक परंपरा है कि हम जो भी इवैक्युएशन ऑपरेशन करते हैं, उसकी स्टडी होती है। हमें वहां से जो सीखना चाहिए, वह हम सीखते हैं। हमें यह मानना चाहिए कि यह 'ऑपरेशन गंगा' एक कलेक्टिव एफर्ट था। यह कलेक्टिव एफर्ट केवल सरकार या मंत्रालयों का नहीं था, बल्कि इसमें इंडियन कम्युनिटी भी शामिल थी। यूक्रेन व उसके पड़ोसी देशों में हमारे काफी बिजनेसेज हैं। उन्होंने हमारी बहुत सहायता की तथा स्टूडेंट्स ने भी सहायता की। हमें इसे भी जानना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वहां से निकले, उन्होंने कैंप्स में काम किया और बाकी स्टूडेंट्स की मदद की।

सर, मैंने यह भी देखा कि एक बस होने पर उनको आपस में डिसाइड करना था कि कौन जाएगा और कौन रुकेगा। स्टूडेंट्स ने काफी साहस दिखाया। उन्होंने दूसरे लोगों को जगह दी। इसे भी हमें जानना चाहिए। कल यह बात उठी कि मिनिस्टर्स का रोल क्या था? यूक्रेन रूस तथा सभी पड़ोसी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को मैं पर्सनली तथा पहले से ही जानता हूं। जब यह फाइटिंग शुरू हुई, तो मैंने सबसे बात की। चूंकि पहले से ही रिश्ते थे, तो उन्होंने रिस्पॉंड भी किया। मैं यह कहूंगा कि अगर हमारे मिनिस्टर्स नहीं जाते, तो हमें उन सरकारों से उस लेवल का अटेंशन नहीं मिलता। वह सहायता वे नहीं देते, क्योंकि उनकी अपनी कठिनाई थी, उनकी अपनी प्रायॉरिटीज थीं। उनके बॉर्डर्स में समस्या थी तथा उनके नागरिक भी संकट में थे। मैं यह साफ कहता हूं कि हमारे मिनिस्टर्स ने मेरी काफी सहायता की। उनके जाने से मेरा काम आधा हो गया। वे इस समय हाउस में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि यह गवर्नमेंट की टीम स्पिरिट है कि अगर एक मंत्रालय पर काफी लोड आ जाए तो बाकी मिनिस्टर्स डिपार्टमेंटल परिप्रेक्ष्य की

बजाय मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं और एक टीम के सदस्य बनकर सब लोग काम करते हैं। मैं इसकी आज प्रशंसा करता हूं।

सर, जो एम.ई.ए. ने किया, उस पर कल बहुत लोगों ने कहा, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इसके आंकड़े मेरे स्टेटमेंट में हैं कि लगभग 13 हजार फोन कॉल्स, 9 हजार ई मेल्स और कई सारे लोगों के पर्सनल कॉंटैक्ट्स से वाट्स अप मैसेजेज आए थे, पर यह बात भी है कि यह हमारा कर्तव्य है। हमें इस समय करना पड़ा। हम आगे भी ऐसी, भगवान न करे कि ऐसी समस्या फिर से आए, लेकिन हमारा जो इस समय का अनुभव है, उसे लेते हुए हम अपनी तैयारी करेंगे।

अब जो स्टूडेंट्स वापस आए हैं, उनके बारे में मेंबर्स ने चिंता प्रकट की है। यह स्वाभाविक है, हमें चिंता करनी चाहिए। अगर वे हमारे परिवार के हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही चिंता करते, जैसे उनके माता-पिता आज कर रहे हैं।

महोदय, मैं हाउस को यह सूचना देना चाहता हूँ कि यूक्रेन गवर्नमेंट ने उनके लिए यह एक निर्णय लिया है, Mr. Speaker, Sir, there will be relaxation for them in respect of completion of medical education. There is an examination called 'KROK-1' for the third-year students going to the fourth year. That has been postponed to the next academic year and the students will be allowed to pass to the next academic year based on the completion of the standard requirements.

For sixth-year students, there is an examination called 'KROK-2'. Normally, you have to pass KROK-2 to be awarded the degree. So, the Ukraine Government has taken this decision and we have pressed them in this matter because the larger number of foreign medical students in Ukraine are mainly from India. There are students from other countries also. So, on the basis of the results of the academic assessments, the students will be awarded the degrees without taking part in KROK-2 examination.

Then the issue was raised regarding the other students. What happens to them? Sir, obviously the Ministries concerned are also discussing this matter. From the Foreign Ministry's point of view, I can say that they are in touch with them. An hon. Member yesterday referred to Hungary.... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I would like to inform the hon. Minister, as I mentioned yesterday, I had met with the hon. Prime Minister last week and we had a discussion on this issue. During our talk, the ... * I would like to know the latest position in this regard. ...*

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I want to update that picture. Yes, there was an offer from Hungary. In addition to Hungary, we have been in touch with Poland, Romania, Czech Republic and Kazakhstan because they all have similar models of education.

There was also a question about education loan. All these students have taken education loan. According to our figures, 1,319 students have outstanding loans. Hon. Finance Minister has informed this House a few days ago that the Government has asked the Indian Banks' Association to assess the impact of the conflict and initiate consultation in regard to the repayment of loans.

This is the information that I wanted to share with the House. But some individual hon. Members mentioned about very specific points. I would like to reply to some of them. I cannot give reply to all of them because of time limit. I do not want the hon. Members to whom I will not reply to think that I have not taken them

* Expunged as ordered by the Chair.

seriously. I have taken everybody very seriously. But I think some points deserve a very specific reply.

I would like to begin with some observations made by Shri Premachandran ji. He contrasted our advisories with those of western countries. Now, I would like the hon. Member to appreciate that western countries had a political approach and a political agenda. Their advisories did not have the same intent like ours, the welfare of the community concerned. They were also the part of a larger political game which they were playing. Again, I want to emphasise that in this case, there was nobody else who has done the evacuation before we did the evacuation.

In fact, when fighting started, many countries – I do not want to take their names – actually told their people, 'Sorry, there is nothing we can do for you, you are there, you are stuck'. So, when we evacuated, again I want to say, we served as an inspiration. There are Foreign Ministers who said, 'We watched you', and said, 'We will also do something'. Yes, we brought back citizens of 18 countries. For example, when we left Sumy, along with us, more non-Indian students came out and they came out because of a ceasefire that we had helped to achieve. So, I would say there is no reason for us to be, in any way, excessively critical of what happened.

There was this issue also that we gave priority to some areas and some cities. We looked after all students. At that stage, in fact, frankly many of our hon. Members and even State Governments approached us and it is natural. A State is worrying about the students of its State. I listened to them very openly. But I gave all of them the same answer. I said, 'I have listened to you, but when I look at the students over there, those students do not tell me they are from one particular State, the students

are behaving like they are all Indians, they are showing a unity, they are showing a collective ability, please do not disrupt us'.

Sir, in fact, we were also under pressure to run flights to different cities. We were asked, 'Can you bring them to a particular State?' If we did this, it would have disrupted the sense of togetherness which the students were showing out there. So, we took a decision that flights would come only to Delhi and Mumbai. But I would compliment every State Government. Every State Government made excellent arrangements, everyone of them worked with us so that the movement of students from airport to their homes was very smooth, and I would like to use this opportunity, Sir, to convey my appreciation of that.

Sir, Manish Tewariji made two observations which I would like to respond to. One was, he said that friends have to be spoken to honestly. These may not have been his exact words, but, I think, this was his sentiment. I can assure him, Sir, through you, all our conversations with everybody on this matter has been very candid, has been very direct, and the positions that I stated in the House have been communicated with as much directness to all our partners. So, nobody has any doubt where we stand on this matter.

There is just one minor issue which I wanted to clarify to him, because he referred to an exchange I had with the British counterpart. She was very careful. She, actually, told me, 'We recognise your sovereign right to take decisions'. The provocative question which was asked was asked by a member of the Press. It was not done by another Foreign Minister whether we are buying huge amounts of oil or

not. I have clarified to Brijendra Singhji about the impact of the Prime Minister's conversation.

I want to tell Dr. Sumathy that the view that no assistance was given to students is not right. Students took trains, students took buses. I accept, many students worked among themselves, worked with their student contractor. But we were guiding every student contractor.

In fact, another Member said, 'What were you doing? You were only issuing advisories'. Let me tell you, at that moment, it was our advisories which told people what to do, saying this border is clear, this is where you should go etc. For example, Dr. Sumathy referred to a situation where we told students to walk. We told students to walk because on that day, Sir, there was heavy firing on Kharkiv. There were hundreds of students who had gathered at the railway station. We were really worried for them. We created a safe zone; the safe zone was 12 kilometres, and we wanted the students to understand, 'It is absolutely important, you move there'.

So, that is the reason why we said this. Again, I applaud what the students have done, and the courage and the endurance that they have shown. I think, we should all appreciate that.

Supriya-ji asked: 'Did you speak to universities? If the universities did not advise properly, did you take it up?' Yes, we did. We were very frustrated with some of the universities, I would also say that. But it is because we would keep talking that eventually, at least, the initial 4,000 actually left.

There was one issue which Shrikant Shinde-ji raised a question about whether other people moved earlier than us. I would say, as regards evacuation, we were the

first. If individual citizens left, yes, many of them did. As I said, many of them left as part of a larger political plan that their particular countries set. But the bulk of the students were there. They were not only from our country. We saw students from Egypt, from Morocco, from Algeria, from our own neighbours -- Bangladesh, Nepal and Pakistan. So, the bulk of the students were there. I think as Gen. V.K. Singh explained yesterday, the psychology of the people was: "No, no, no. This will pass. Let us talk to our friends." Friends are saying: "मैं नहीं जा रहा तो आप क्यों जा रहे हो?" So, that was really what the situation was. I think, we should really show understanding.

Let me, Sir, finally conclude with one common issue which all Members raised, which is: 'worry about the world order'. What is this conflict? What does this mean? There is the relationship between countries. How is this moving?

I want to say this, yes, the world order is changing. The world order has been changing for many years. That is why G-7 became G-20. The world order changed because of COVID-19.

Countries saw what happens when there is too much concentration of economic production in one geography, when there is not enough resilience and reliability in supply chains. The world order is changing because countries today worry about trust and transparency, they are worried where is the data, which technology should they trust. The world order is changing because the Afghanistan-like situation happened. So, we are left with a problem close to our homes, which we are worrying about more than the countries which were there earlier. Now, the world order will change partly because of the consequences of this. But what is the solution to it? To my mind, the solution is, we have to be stronger; we have to reduce our

dependency on the external world. It can never be total. But the way to deal with the new world order is really 'Atmanirbhar Bharat', and 'Atmanirbhar Bharat' is not just an economic policy, 'Atmanirbhar Bharat' is a Bharat, which looks after its people, a Bharat which is capable of running 'Operation Ganga'.

Thank you, Sir.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Minister, Sir, I raised one issue, and it is involving the Prime Minister of the country. I was carrying a letter of a Chief Minister of a State. She placed some proposals for 350 odd students from West Bengal, the State to which I belong. What would be their future? So, she placed some proposals saying, 'I will absorb these students in my own State.' As an outcome, ... * I am repeatedly mentioning these words. And, it was a long discussion, not a one-minute or two-minute discussion. But what would be fate of these students, I want to know.

You are saying they would be sent to the adjacent countries like Czechoslovakia, Hungary, Romania. So, these are the places. We want more specific replies on what would be the fate of these students. You are saying that Ukraine agreed. But what is the existence of the Ukraine Government now? Are they under the control of the Soviet Russia/Russian Federation or are they standing on their own feet? That is still uncertain. It is not clear from your observations made in your speech.

* Expunged as ordered by the Chair.

Let the House and the student community be assured that when and how these students are going to be replaced in different parts of the world, either it is in the Eastern European side or it is, particularly, Hungary in a time-bound manner. What would be the time limit?

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, कल हम लोगों ने चार मंत्रियों का भाषण सुना। आज हमारे जयशंकर जी भी उन्हीं की बात को दोहरा रहे थे। हम आपसे एक नई बात जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि रूस के खिलाफ बहुत किस्म के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ हुए हैं। स्विफ्ट सिस्टम से रूस को निकालने की सारी कवायद हो रही है, फिर भी कुछ बैंकों से कारोबार चल रहा है। इस हाल में रूबल और रुपये की ट्रांजेक्शन में क्या असर होगा? क्या हम लोग स्विफ्ट से बाहर आकर रूपये और रूबल के लिए चिंता कर रहे हैं? I would like to know whether this Government has been approached by other countries to mediate in the war between Ukraine and Russia in order to find out any convenient way so as to solve the issue amicably.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, the future of the students is blinking in unexpected light. What exactly is happening to the admissions of these students? You are giving some relief. I heartily appreciate the efforts taken by the MEA as well as the Government. But, as far as the future of the students is concerned, as there are some suggestions about that, the students still have apprehensions about it. It is because the parents are meeting us and asking about the future of their children. The internship is of six years. You said that KROK-2 will begin, that is fine. But, what about the other students? What measures are we taking about that? I would like to have a specific answer about it.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, broadly, there are two concerns, one is on the future of the students. I completely understand that this is something which all

hon. Members will worry about. I think, this is something which is between the Ministry of Education and other organisations dealing with medical education. They are seized of the matter. I only wanted to update the Members because, specifically, Sudip Bandyopadhyay ji, yesterday mentioned his conversation with the Prime Minister and Hungary.

I wanted to point that in addition to Hungary – again, Hungary was the first one to offer and offered most generously – there were other offers as well which we are exploring. All our embassies are at work and, obviously, our effort will be to see that our students are assisted as much as possible.

Regarding Adhir Ranjan ji's interest on the payment mechanism, I want to assure him that our effort today is to stabilise economic transactions between India and Russia because it is very important for us. Russia is a very important partner in a variety of areas. I think, all hon. Members understand that. So, at the moment, there is an Inter-Ministerial Group which is led by the Finance Ministry seeing how the payments issue can be best addressed. There are experiences from the past which are relevant in this regard. But, I think, this is quite honestly an issue where the Finance Minister would, finally, have to take a call.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने मिल कर इस गंभीर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया तथा जिस तरीके से उस परिस्थिति में अपने देश के बच्चों को निकाला गया, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मुझे लगता है कि पूरे सदन को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। भविष्य में ऐसे मुद्दों पर सारा सदन एक साथ मिलकर देश हित में काम करेगा, ऐसी मेरी भावना है।

सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.29 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

———

14.35 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14.35 ½ hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन मामले।

श्री गणेश सिंह जी।

(i) Regarding promotion of natural farming

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग किसान करे, इस दिशा में कई कारगर कदम उठाये गये हैं। इस बजट में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। भारत सरकार गंगा नदी के 10 किलोमीटर दोनों तरफ प्राकृतिक खेती करने का पायलट प्रोजेक्ट लाने जा रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मध्यप्रदेश में नर्मदा, टमस, सेमरावल, केन, बेतवा जैसी कई प्रचुर मात्रा में जल-प्रवाह वाली नदियां हैं, उन्हें भी प्राकृतिक खेती के लिये पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाय। मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्र सतना के अन्तर्गत टमस सेमरावल और सतना नदी को इस योजना में शामिल करने की मांग करता हूँ।

माननीय सभापति: श्रीमती अपराजिता सारंगी जी।

… (*Interruptions*)

(ii) Regarding establishment of a DRDO lab, Ordnance factory, Sainik School and Defence Recruitment Centre at Deoghar

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar has been included in the list of prominent cities and has been declared as a mega tourist destination by the Ministry of Tourism, Govt. of India. Deoghar is a unique and extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlinga in the country. This is a religious and cultural capital of Eastern India which catapults the holy place to an international acclaim and is visited by over 5 crore pilgrims every year.

I request for kind consideration of the following:

1. Regarding the requirements of land for the proposed Military Station, the area available will be approximately 400 acres which can be reduced or increased once the feasibility is done. The land will be near the ongoing DRDO centre project at Deoghar (Jharkhand).

2. DRDO Lab at Deoghar (Jharkhand)

3. Ordnance Factory or any defence infrastructure project at Deoghar (Jharkhand)

4. Sainik School at Godda (Jharkhand)

5. Defence Recruitment Centre at Deoghar.

You know well that large parts of the State are affected by Naxalism and terrorism. The spread of Naxalism and terrorism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over large sections of Jharkhand's

Santhal Pargana region, which have not only been systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed.

माननीय सभापति: श्री संजय काका पाटील जी। श्री सुनील कुमार सिंह जी। डॉ. सुजय विखे पाटील जी।

… (*Interruptions*)

(iii) Need to curb pollution in Indira Gandhi Canal and also to grant Membership of BBMB to Rajasthan

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, राजस्थान की औद्योगिक ईकाइयों द्वारा पानी में बढ़ते प्रदूषण के कारण इंदिरा गाँधी नहर का पानी पीने व सिंचाई योग्य नहीं रह गया है। राजस्थान प्रदेश में पानी एक बड़ी समस्या है और बहुत ही सीमित मात्रा में इसकी उपलब्धता है। इंदिरा गाँधी नहर, जिसका पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्रदेश को आवंटित होता है, उसमें प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के लिए जीवनदायिनी बन चुकी इंदिरा गांधी नहर अब बीमारियों का कारण बन रही है। पंजाब से आ रहे बेहद प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करने वाले लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं और पीलिया व कैंसर जैसे रोग में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार को कुल 663.20 एमएलडी क्षमता के 26 सीवेज शोधन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए 774 करोड़ रूपए जारी किये थे। अब बीबीएमबी में हरियाणा और पंजाब का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। इसी कड़ी में मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि अब राजस्थान को भी बीबीएमबी में सदस्यता प्रदान की जाए।

(iv) Need to establish Kendriya Vidyalayas in Rajsamand Parliamentary Constituency, Rajasthan

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद (राजस्थान) के अंतर्गत राजसमंद, मेड़ता, भीम और जैतारण में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद में बड़ी संख्या में सैनिक परिवार और केन्द्रीय कर्मचारी निवास करते हैं और उच्च गुणवत्तापूर्व शिक्षा प्राप्ति के लिए यहां केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग लगातार की जाती रही है। मैंने इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर पूर्व में अनुरोध भी किया है। राजसमंद, मेड़ता और भीम में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव संगठन के मुख्यालय में भिजवा दिया गया है जबकि जैतारण की प्रक्रिया अभी बाकी है। स्कूल शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित करने में केन्द्रीय विद्यालय की महत्ती भूमिका है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से विद्यार्थियों का भविष्य संवर सकता है। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। पूरा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र लाभान्वित हो इसके लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति मिलना आवश्यक है।

अत: मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जिला मुख्यालय राजसमंद, मेड़ता, भीम और जैतारण में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं।

(v) Regarding plight of jute mills and jute growing farmers

SHRI ARJUN SINGH (BARRACKPUR): Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Textile Minister to the jute Industry in West Bengal. The jute industry is going down, and the employees of this industry have lost their jobs in large numbers. The bureaucracy is fully responsible for the plight of jute farmers and jute mills. It is because of a big difference in jute prices between the Government price and the market price, mediator in the market gets full benefit, and makes huge profit, which actually belongs to farmers and jute mills. For the first time in the history, the Jute Commissioner had fixed the rate of jute in September 2021 at Rs.6500 per quintal while the market price stood very high at around Rs.6700 to Rs.9000 per quintal, as per the Jute Balers' Association. If the farmers do not get fair price for their crop, they will be encouraged to divert cultivation of jute to other crops. I request the hon. Textile Minister to please look into the matter, and save jute mills and their workers, who suffer due to such fixation of rates. Therefore, Mr. Chairman, through you, I request the Government to look into this issue of public importance.

(vi) Regarding alleged irregularities in storage of paddy in Chhattisgarh

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, छतीसगढ़ के किसानों की धान ग्रामीण सहकारी सभा के द्वारा खरीदी जाती है। जहां राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित एजेंसी द्वारा 72 घंटों में धान को खरीदी केंद्र से उठाकर भंडारण केंद्र में ले जाने का प्रावधान है। लेकिन, दिसम्बर माह मे खरीदी गई धान को अब मार्च में उठया जा रहा है। ऐसे में धान की सूखती आना स्वाभाविक है और सरकार द्वारा भी 3% की छूट दी गई है।

लेकिन, वर्तमान में 0% सूखती दर्शाओ कहकर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धान खरीदी केंद्र प्रभारी एवं संबंधित सह-सभा के प्रबन्धक/ समिति के विरुद्ध कार्यवाही कर यहाँ तक की उनकी मोटर साइकिल और घर सम्पति का ब्यौरा मांगा जा रहा है। इस प्रकार राज्य प्रशासन के अधिकारी खरीदी केन्द्रों के प्रभारियों/ समितियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि उक्त संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही हेतु केंद्रीय जांच दल भेजकर जांच कराई जाए तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यों को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाई जाए।

(vii) Need to accelerate pace of construction work of Rewa-Singrauli railway line, part of Lalitpur-Singrauli Railway line Project

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): सभापति महोदय, आज मैं माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे रेल विहीन संसदीय क्षेत्र सीधी के लिए ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना अति महत्वपूर्ण व रेल के सपनों को साकार करने वाली है। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विशेष रुचि लेते हुए इस परियोजना के कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी जिसके कारण कार्यों में तीव्रता आई। उसी का परिणाम है की बघवार के छुहिया घाटी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे टनल बनकर तैयार हो गया है। अभी कुछ दिन पहले रेलमंत्री जी ने उक्त टनल की फोटो भी पोस्ट की थी, परंतु मैं सनिवेदन अवगत कराना चाहती हूं कि उक्त परियोजना के भाग रीवा से सिंगरौली में तीव्रता लाने की आवश्यकता है। विगत महीनों में परियोजना के कार्यों की गति में कमी आई है।

मेरा आग्रह है की ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के भाग रीवा से सिंगरौली के कार्यों में तीव्रता लाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जाये, जिसके फलस्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजना का कार्य पूर्ण हो सके।

(viii) Need to continue the services of Poshan Sakhi in Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में वर्ष 2016 में राज्य के छह जिलों धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में 10388 पोषण सखी नियुक्त की गई थीं। राज्य में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए लगन और ईमानदारी के साथ विगत छः साल से काम कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप कुपोषण के मामलों में कमी आई है। कारोनाकाल में भी पोषण सखियों द्वारा सराहनीय काम किया गया। इन पोषण सखियों को वेतन के रूप में मात्र 3000/- महीना की दर से मानदेय दिया जाता है। यह मानदेय भी कई महीनों तक लम्बित रहता है। झारखण्ड की वर्तमान सरकार ने 25 मार्च, 2022 को एक आदेश जारी करते हुए इन छः जिलों की सभी 10388 पोषण सखियों की सेवाएं 01 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी हैं । झारखण्ड सरकार द्वारा पोषण सखियों को बेरोजगार कर दिया गया। मात्र 100 रूपये प्रतिदिन मानदेय पर काम करने वाली पोषण सखियां 6 साल तक काम करने के बाद अब कहां पर जाएंगी? इनकी पढ़ाई व महत्वपूर्ण 6 साल राज्य की सेवा में लगा दी है। राज्य को कुपोषण व कोरोना से बचाने में अपना भरपूर सहयोग करने के बाद अब ये पोषण सखियां बेरोजगार हैं।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से मांग है कि झारखण्ड राज्य के छः जिलों धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में 10388 पोषण सखी की सेवाएं स्थायी रूप से जारी रखने के निर्देश दें। पोषण सखियों के लम्बित मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए।

(ix) Regarding construction of Rajasthan Sabarmati link Canal

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले के अंतर्गत धानेरा, दांतीवाडा, लाखनी, डीसा, थराद, अमीरगढ, दांता, पालनपुर और दीयोदर तहसीलों में भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे है और यह भूजल स्तर निरंतर नीचे जाता ही जा रहा है। यदि हम भूजल के वर्तमान स्तर की बात करें, तो यहां हजार फुट पर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। यह अपने आपमें एक जटिल एवं विकराल समस्या का रूप ले रही है और किसान इस समस्या के कारण त्रस्त हैं। इसी वजह से किसानों को सिंचाई के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ मैं स्वयं भी एक किसान हूं, इस नाते मैं किसानों की यह पीड़ा को भलीभांति महसूस कर सकता हूं।

महोदय, मेरा यह क्षेत्र किसान बहुल है और यहां के सभी किसान कृषि और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इनके पास आय का दूसरा कोई श्रोत भी नहीं है। इसलिए जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

भारत में भूजल भण्डार के लगातार कम होने की चिंता को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान साबरमती लिंक कैनाल को बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है। यदि इस कैनाल का कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाए, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त बताए गए तहसीलों में पानी की सिंचाई का एक नया श्रोत मिल जाएगा, जिसका लाभ यहां के किसानों को मिलेगा और एक जटिल समस्या का कुछ हद तक निवारण भी हो सकेगा।

महोदय, इस कैनाल के साथ हमें और भी सिंचाई के साधन को तलाशना होगा, जिससे कि इस समस्या का पूर्णतः निवारण हो जाए। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है की मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए।

(x) Regarding construction of a bridge for pedestrian traffic across railway lines in Naroda railway station, Ahmedabad, Gujarat

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल (अहमदाबाद पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम रेलवे द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व (गुजरात) में आया नरोडा रेलवे स्टेशन को रिनोवेट किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद करता हूं। नरोडा रेलवे स्टेशन रिनोवेट किया जा रहा है। उसके दोनों तरफ बाहर से पैदल आने-जाने का रास्ता नहीं है। जिस वजह से रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ रहने वाले लोगों एवं स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से स्कूल व कॉलेज में छात्रों एवं नौकरी पेशा करने वाले लोगों को स्टेशन ट्रैक के ऊपर से जाना पड़ता है। जिस की वजह से कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। इस वजह से रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ से लोगों को मजबूरी वश रेलवे ट्रैक क्रॉस न करना पड़े, इसलिए पैदल पुल का निर्माण करना अति आवश्यक है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द नरोडा रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल बनाया जाए।

(xi) Need to provide adequate compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of Jammu and Kashmir

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की और ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी के दूसरी ओर जो खेती की जमीन थी एवं जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं। उनकी जमीन ही एकमात्र सहारा है। जब से उनकी जमीन तार के उस पार चली गई है, तब से वह बड़ी मुसीबतों की जिन्दगी जी रहें हैं। उनको भुखमरी की नौबत आ गई है। इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है? ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें उस जमीन का मुआवज़ा अभी तक मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

अतः सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने का कष्ट करें।

माननीय सभापति : श्री राहुल कस्वां जी – उपस्थित नहीं।

श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी – उपस्थित नहीं.

(xii) Regarding road accident insurance plan for licensed vehicle drivers

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति महोदय, देश में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लाइसेन्स धारी ड्राइवरों की प्रतिदिन मौतें हो जाती हैं। ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय दुर्घटना बीमा की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई लाइसेन्स धारक ड्राइवर की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो दुर्घटना के पश्चात उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। जैसे कृषक दुर्घटना बीमा, श्रमिक दुर्घटना बीमा, श्रम कार्ड धारकों का बीमा के तहत इनके आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। किन्तु यदि कोई ड्राइविंग लाइसेन्स धारी ड्राइवर की मृत्यु होती है, तो उनके आश्रित परिवार दर-दर की ठोकरे खाते घूमते हैं। यदि जैसे रजिस्टर्ड श्रमिकों को दुर्घटना बीमा दिए जाने का प्रावधान है, उसी प्रकार लाइसेन्स धारी ड्राइवरों को भी दुर्घटना बीमा योजना दिया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि देश में ड्राइवर दुर्घटना बीमा योजना लागू कराने का कष्ट करें।

(xiii) Regarding declaration of State road from Mannarkkad to Coimbatore via Attappadi and Chinna Thadagam as sub-highway to National Highway No. 966

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): It has been a long pending demand of the people, mostly Tribals, living in Attappadi, to declare the State road from Mannarkkad to Coimbatore via Attappadi and Chinna Thadagam as sub-highway to National Highway No. 966. Declaring this State road as sub-highway to National Highway No. 966 will really help the tribal people. Due to the present condition of roads, the people are not able to save the lives of their near and dear ones as journey to the nearest hospitals at Perinthalmanna or at Coimbatore takes a lot of time, and in between patients succumb to illness.

Moreover, Attappadi is an agricultural area cultivating many types of spices and other agricultural produce. These tribal farmers are finding it very difficult to transport their produce to the nearby market at Coimbatore, and as such are unable to get a decent price for their produce.

Declaring this State road as sub-highway, and the expected development on this account will reduce travel distance from Kozhikode to Coimbatore, and can save fuel as well as pave the way for overall development of this tribal inhabited area. Therefore, it is urged that the said State road may please be declared as sub-highway to National Highway No. 966 urgently.

15.00 hrs

(xiv) Regarding prices of life-saving drugs

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Prices of essential medicines including painkillers, antibiotics, anti-infectives are set to go up from April with the Government allowing an increase of over 10 per cent for the scheduled drugs.

India's drug pricing authority on Friday allowed a price hike of 10.7 per cent for scheduled drugs, which are under price control. This is the highest price hike allowed. Over 800 drugs under the National List of Essential Medicines (NLEM) will see a price rise from April.

The NLEM list includes drugs like paracetamol, antibiotics like azithromycin used to treat bacterial infections, anti-anemia, vitamins and minerals. Some drugs used for treating moderately to severely ill COVID-19 patients and steroids are also included in the list.

These medicines have a profound impact on the lives of people. The Government’s reasoning around inflation indexing of price does not hold water in a country like ours where crores of people struggle to buy food, let alone lifesaving medicines. I urge upon the Government to reverse this decision and ensure that lifesaving drugs stay affordable to the people of India.

(xv) Regarding setting up of a trading point along the Indo-Bangladesh Border in Murshidabad district, West Bengal

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Setting up of a trading point along the Indo-Bangladesh Border in the district of Murshidabad, West Bengal to facilitate commercial exchange with Bangladesh.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Kalanidhi Veeraswamy -- not present.

Shri Raghu Rama Krishna Raju.

(xvi) Regarding naming of Centrally-sponsored schemes by Andhra Pradesh Government

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): I draw the attention of the Government to the issue of renaming the Centrally-sponsored schemes by Andhra Pradesh Government. Almost, all the Central schemes are being renamed on the personal names of the Chief Minister and his family names. For example, PM Kisan Samman Nidhi Scheme has been termed as YSR Rythu Barosa, PM Fasal Bima Yojana as YSR Free Crop Insurance Scheme, and other farmer welfare schemes are termed as YSR Zero Interest Farm Loans, YSR Polambadi, YSR Organic Policy, YSR Agriculture Testing Labs.

State is trying to take credit through nomenclature based on the Chief Minister, his family members and even his lineage while grants are made from the Central Government budgets. Recently, hon. Finance Minister on her recent visit to AP observed and raised the issue before media and alerted the concerned officials to be more vigilant in implementing the schemes. When the matter was brought to the notice of hon. Minister of Women and Child Development, she had promptly acted and communicated that the ban of co-branding any Central-sponsored schemes will be viewed seriously.

I request the Government to take swift corrective action in the matter before it goes out of control.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kuruva Gorantla Madhav – not present.

(xvii) Regarding sanction of an integrated cold storage for Potatoes in Arambagh Parliamentary Constituency

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, West Bengal is a major potato-growing State of India and farmers mainly grow Jyoti, Chandramukhi and hybrid varieties like Super S1, Super 6 and Pokhraj. Around four lakh Lakh acres of land is under potato cultivation in Bengal and an estimated 10 lakh farmers are engaged in potato farming. Potato production in West Bengal is higher by nearly 16 per cent at 110 lakh tonne out of which 71 lakh tonne of potatoes were kept in cold. storage this year.

In Potato farming, cool temperature is of utmost importance for good produce. My constituency of Armabagh has substantial number of potato farmers who store their produce in cold storages for which they have to fork out additional fees, often to private entities. West Bengal has vast growth potential in the horticulture sector and being one of the leading producers of potato, there is a requirement to shift from cold storages to integrated cold chains to realise its full potential. Modernisation-cum-retrofitting of the existing traditional cold storages into multi-purpose cold storages will be the right step. In view of the expected high production of potato in West Bengal in the current year, I request the Government to sanction an integrated cold storage for potatoes in my constituency of Arambagh.

(xviii) Regarding hike in prices of Petroleum Products

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, thank you for thanking us.

Under Rule 377, I point out to the astronomical … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly go by your text.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, one or two lines may be here or there.

माननीय सभापति : आप अपने टैक्स्ट पर रहिए।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, you look at Rule 377 in the book. I am going by the book.

HON. CHAIRPERSON: No.

PROF. SOUGATA RAY: Please allow me. This is a very important matter. Petrol and diesel rates in the country have sharply increased after the latest round of fuel price hike by oil marketing companies (OMCS). Experts have said that the continuous increase in fuel prices will have a widespread impact on citizens and the overall economy. The petrol and diesel prices across the country continued their northward march and its retail rates to unprecedented levels while burning bigger holes in the consumers' pockets. The common people are cutting on their other expenses to manage their spending on fuel prices. Every citizen of the country is in anguish and deep distress regarding the spiralling fuel and gas prices. India is witnessing systematic erosion of jobs, wages and household income. The middle class and those at the margins of our society are struggling. These challenges have been compounded by runaway inflation and an unprecedented rise in price of almost all household items and essential commodities. I urge upon the Government to intervene

in the matter and take immediate steps to check the steep hike in the prices of petroleum products daily.

(xix) Regarding construction of RoB, VUP and CUP on NH 52 in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मेरे लोकसभा क्षेत्र चुरू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को 2 लेन से 4 लेन का किये जाने हेतु कार्य प्रारंभ किया जाना हैं। सड़क निर्माण से पूर्व सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा सड़क का निरिक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनेक स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु VUP व CUP बनाये जाने की अत्यंत आवश्यकता हैं। गाँव भांगीवाद, बाघसरा, आथुना, खोटिया, ढाणी डीसपुरा, रामसरा, ढाढर, लाखाऊ, लादडीया, दुधवा खारा, सादुलपुर बाईपास पर खेमाणा, ढढाल व गुलपुरा के रास्ते पर, श्योपुरा व इन्दासर वे गाँव हैं, जहाँ इनकी अत्यंत ही मांग थी। काफी स्थानों पर ग्रामीणजन के द्वारा इनके साथ-साथ ROB बनाये जाने हेतु भी मांग की थी। इनका एक मुख्य कारण यह भी हैं कि इन गाँवों में रिहायशी इलाका एक तरफ व सभी सरकारी संस्थाएं व रेलवे स्टेशन दूसरी तरफ पड़ती हैं और आमजन को अनेकों बार सड़क को पार करना पड़ता हैं, जिससे लगातार दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती हैं और काफी स्थानों पर दुर्घटनायें होती भी हैं, जिसकी वजह से आमजन का जीवन खतरे में रहता हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार अनुरोध हैं कि इन सभी स्थानों पर ROB, VUP व CUP आवश्यकता अनुसार बनवाए जायें, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को होने से बचाया जा सकें।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Sanjay Jadhav – not present.

(xx)Regarding implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (G) in Odisha

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): The Ministry of Rural Development opened Awas plus window to identify the eligible households left out from the Permanent Wait List (PWL) of Pradhan Mantri Awas Yojana (G) by 7th March, 2019. Our State of Odisha could register only 35,000 households within the stipulated period as the functionaries were preoccupied with the work of General Elections of 2019. After Cyclone Fani, Awas plus window was opened for 14 affected districts during September – October, 2019. Our State identified 7.87 lakh households in these districts making the total registration to 8.22 lakhs. The Ministry allotted the target of 8.17 lakhs under PMAY (G) to Odisha from the Awas plus list. During field verification of August – September, 2021, 5.6 lakh households from the identified 8.22 lakhs were found eligible for sanction of PMAY (G) houses. The hon. PM during his visit after Cyclone Fani committed to sanction 1.84 PMAY Special houses to the Cyclone Fani affected families. I request the hon. Minister of Rural Development to allow opening of the Awaas plus window for one month to accomplish the migration of data of 5.09 lakh households from Rural House Portal list to PWL through Awas plus and also include 1.84 lakh PMAY Special houses to the Cyclone Fani affected families as committed by the hon. Prime Minister in May, 2019.

HON. CHAIRPERSON: Dr. G. Ranjith Reddy – not present.

(xxi) Regarding resolution of water disputes between Rajasthan and other States

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी का राजस्थान राज्य के लंबित जल विवादों के शीघ्र निस्तारण करने की मांग की तरफ आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों के मध्य हुए रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था और इसके अनुसार रावी-व्यास नदियों के आधिक्य जल में से कुल उपलब्ध 17.17 एम.ए.एफ. में से राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया था और उसके बाद पंजाब सरकार उक्त समझौते के विरूद्ध पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2014 लेकर आई तब उसे भी माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने राय देकर पूर्व में समझौते को सही ठहराया साथ ही राजस्थान को यमुना बेसिन राज्यों यथा हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के मध्य दिनांक 12.05.1994 को हुए समझौते के तहत 1.119 बीसीएम यमुना जल का आवंटन हुआ था। इस मामले में ताजेवाला हैड से राजस्थान को उसके हिस्से का पानी प्राप्त नहीं हो रहा है।

साथ ही भरतपुर जिले में भी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्य में अनधिकृत दोहन से यमुना का पूरा पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही हरिके बैराज पर स्थित इंदिरा गांधी फीडर के हैड वर्क्स रेगुलेटर की क्षमता 15,000 क्यूसेक से 18,500 क्यूसेक बढ़ाये जाने हेतु भी भारत सरकार के माध्यम से पंजाब सरकार को निर्देश देना अपेक्षित है ताकि बाढ़ जल की क्षति को रोका जा सके और वो पानी राजस्थान की जनता के काम आ सके।

भारत सरकार को राजस्थान की विस्तृत भौगोलिक स्थिति व मरूस्थल को देखते हुए राजस्थान के लंबित जल विवादों का जल्द से जल्द निस्तारण करने की जरूरत है ताकि राजस्थान में पानी की कमी काफी हद तक दूर की जा सके। इसके लिए केन्द्र को संबंधित राज्यों के साथ भी बैठक करके जल्द निर्णय लेना पड़ेगा। अन्यथा वर्षों से लंबित ऐसे मामलों के कारण राजस्थान को उसके हक व हिस्से का पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

(xxii) Regarding start of several flights from Belgaum

SHRIMATI MANGAL SURESH ANGADI (BELGAUM): Sir, Belgaum airport in the State of Karnataka has the distinction of being one of the oldest airports in the State, having been established and operated since pre-Independence era.

The city Is educationally forward with the establishment of the Visvesvaraya Technological University (VTU) and Rani Channnamma University (RCU). Besides having several engineering colleges, medical and dental colleges, the city is industrially forward too.

It has often been the persistent demand of the Constituency residents for the start of daily flight services on routes: (1) Belagavi-Bangalore (morning flight), (2) Belagavi-Gorakhpur (Uttar Pradesh), (3) Belagavi-Darbhanga-Gaya (Bihar), (4) Belagavi-Shirdi (Maharashtra), and (5) Belagavi-Varanasi with stress for the start of cargo services too.

The potential for further growth of the IT and BT Companies herein is exponential and the city is also a hub of industrial activities. Besides, many people from North Karnataka visit the holy shrines situated in North India frequently.

Belagavi airport has been chosen under UDAN Phase-3 and more than thirteen air services are already found operational. Hence, I request the hon. Minister of Civil Aviation to please look into the matter towards the early start of the above flight services on the said routes along with the start of cargo services. In this regard, I sincerely thank our hon. Prime Minister and hon. Civil Aviation Minister. Thank you.

———

15.18 hrs

WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AND THEIR DELIVERY SYSTEMS (PROHIBITION OF UNLAWFUL ACTIVITIES) AMENDMENT BILL, 2022

HON. CHAIRPERSON: Item No. 17 – Minister of External Affairs.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005, be taken into consideration."

Sir, the House is aware that India implements its international obligations responsibly and this is recognised by the international community. Weapons of Mass Destruction and Delivery Systems Act, 2005 prohibits unlawful activities in respect of biological, chemical, and nuclear weapons, and their delivery systems. The initial focus was on export controls because we thought at that time in 2005 mainly in terms of trade of goods and technologies.

In recent years, however, international regulations relating to weapons of mass destruction have been strengthened. In particular, the recommendations of the UN Security Council and the Financial Action Task Force (FATF) have mandated provisions against financing in relation to these weapons. Presently, there are no specific provisions in the 2005 legislation relating to prohibition or prevention of financing. So, there is a need to amend the WMD Act to do so.

The proposed Bill is intended to prohibit financing of prohibited activities under the Act or any relevant Act in relation to weapons of mass destruction. It also

proposes empowering the Central Government to freeze, seize or attach funds or financial assets or economic resources for preventing such financing or prohibit making available such funds and resources. This Bill is in our national interest. It is in our global interest. It strengthens our credentials and image. I commend it for consideration.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005, be taken into consideration."

SHRI UTTAM KUMAR REDDY (NALGONDA): Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Bill to amend the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. As the Minister just stated, the new legislation prohibits the financing of weapons of mass destruction and their delivery systems. We cannot disagree with the Minister on the Bill. But however, I want to make a few observations and suggestions.

The entire Bill speaks about a person, an individual who finances weapons of mass destruction. Probably, you have only amended the original Act and not had a look at that. But I would like to suggest that more than individuals who finance weapons of mass destruction and their delivery systems, it is organisations; it is countries. Also, the original Act envisaged largely for Indian citizens and extra-territorial applications. But you should now consider that this Act applies to foreigners, foreign citizens where we have extradition agreements with the foreign countries. We all know who is financing the terror operations against India. There is

specific information about them regarding financing weapons of mass destruction. I think, FATF has also put Pakistan on the grey list. The Government of India needs to do more about countries financing weapons of mass destruction against India.

I would like to bring to the notice of the Minister, through you, that as far as weapons of mass destruction are concerned, I have personal knowledge. I have served in the Armed Forces of India. I have served on both China and Pakistan borders as a fighter pilot. It should be alarming that all of the Pakistani aircraft and the modern Chinese aircraft now are delivery systems for any of the weapons of mass destruction. They can deliver tactical nuclear weapons; they can deliver chemical weapons. So, on the one hand, you have the modern acquisitions by Pakistan and China and the present aircraft being able to deliver weapons of mass destruction and on the other hand, the Indian Air force with a sanctioned strength of 42 fighter squadrons has now come down to 28. I think, the Government should take a very, very serious note of this.

I would like to also bring to the notice of the Government, through you, that weapons of mass destruction were seriously used last in World War II when the cities of Hiroshima and Nagasaki were totally destroyed by an atomic bomb.

After that, for many decades, countries were afraid to use weapons of mass destruction. But of late, countries are becoming more brazen in using these weapons whether it is in Syria or in the present Russia-Ukraine conflict where the Russian President himself in his statement asked his nuclear forces to be alert.

I think, the Government of India must take note of this disturbing trend. The Government of India must also take note of the fact that the weapons of mass

destruction -- whether they are nuclear, chemical, or biological -- are now becoming far more potent and powerful. I would also like to caution the Government of India that drones are now being manufactured to carry weapons of mass destruction. This is an alarming situation. Now, we also have a situation where we have instability in our neighbouring country. Actually, anything is possible now.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to mention a few points about proliferation financing, which this Bill talks about. Most countries use existing mechanisms against terrorism and money laundering to achieve non-proliferation financing. The FATF report on 'proliferation financing' suggests that countries must also raise awareness and help clarify the obligations on individuals, firms, and financial institutions to be vigilant to proliferation and proliferation financing as well as provide a basis within the country's legal framework to report suspicious financial activity. The present Bill does not mention either.

In order to fully achieve deterrence against proliferation financing, a level of international cooperation is required with respect to extradition. This is to avoid creating safe havens for violators of the law, and to ensure mutual legal assistance for investigation and prosecution against proliferation financing and against those who are financing weapons of mass destruction. However, at present, India has only around sixty extradition treaties or agreements with other nations.

Once again, I would like to mention about delivery systems. Please do not go by an earlier definition of delivery systems. Today, all fighter aircraft, in Pakistan and China, are capable of delivering weapons of mass destruction. The Government of India must take appropriate measures on that.

Sir, before I conclude, since you were speaking about … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): …. the Indian aircraft are not capable of that. … (*Interruptions*)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: I cannot say that. … (*Interruptions*). Before I conclude … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: A doubt is being raised that the Indian aircraft are not capable of that. … (*Interruptions*)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: At present, India's nuclear policy does not permit tactical nuclear weapons.

We are talking about weapons of mass destruction. We are talking about financing of weapons of mass destruction. From its inception, the institution of the National Security Advisor and the Deputy National Security Advisor is being somehow restricted to the Indian Foreign Service or Indian Police Service. It would be very appropriate if a military expert will also be the NSA or, at least, the Deputy NSA of this country. Thank you very much.

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): सभापति जी, आपने मुझे 'दि वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम्स' (प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टीविटीज) अमेंडमेंड बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, आप इमेजिन कीजिए कि एक थका हुआ इंसान पूरे दिन काम करके घर जा रहा हो और अचानक बिना किसी धमाके से, बिना किसी आग के 11 लोग मर जाएं और साढ़े पांच हजार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं। ऐसा हुआ, टोक्यो के सब-वे के अंदर सरीन गैस केमिकल एजेंट लीक होने से ऐसा वहां हुआ। It was a terrorist attack. यह संभव है और भारत में भी हो सकता है। यह शुक्र की बात है कि वहां जो केमिकल एजेंट इस्तेमाल हुआ था, वह पुअर क्वालिटी का था। यदि वह बहुत पोटेंट क्वालिटी का

होता, तो बहुत तबाही मच जाती। उसी तरह 9/11 को अमरीका पर अटैक हुआ और उसके बाद अमरीका उससे उभर रहा था, उसके बाद लोगों के घरों में चिट्ठियां आनी शुरू हुईं। जो भी चिट्ठी खोलता था, वह मर जाता था। उसके अंदर एन्थ्रेक्स लेस्ड लैटर था। ऐसा भारत में भी हो सकता है। देश की सरकार की जिम्मेदारी देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने की होती है।

इसीलिए यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, यह इस देश को सुरक्षित करने के लिए आया है। छोटा राष्ट्र, रोग नेशन या कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, वे यह सब करने की संभावना रखते हैं और यह जो कैमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत साधारण तरीके से होती है। आप किसी भी रिटेल स्टोर पर जाइए, वहां से अलग-अलग चीजों को खरीदकर और उनको जोड़कर आप केमिकल एजेंट बना सकते हैं। इसीलिए इस बिल को लाया गया है, ताकि इसे रोका जा सके। यह जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका इस्तेमाल भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। यह कहां तक, किस दूरी तक नष्ट करेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका पहले से कोई एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। आप तुलना करें कि यदि आप गोली चलाते हैं तो वह सही निशाने पर एक जगह जाकर लगती है, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कॉबेटेन्ट्स और सिविलियन्स में कोई फर्क नहीं करते हैं। ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं, उसके बाद ये इको सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स से लेकर पूरे इको सिस्टम को ये बर्बाद कर देते हैं।

सर, ये कैमिकल वेपन्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। इन सबके डेवलपमेंट पर निगाह रखी जा सके, इनकी फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, उन लोगों पर भी निगाह रखी जा सके, इसलिए यह बिल लाया गया है। मैं अभी की बात नहीं करता हूं, मैं वर्ष 2014 की बात करता हूं, जब हमारी नई सरकार बनी थी। उस समय एक लोक नीति सर्वे हुआ, जिसमें यह पूछा गया कि वह कौन सी पार्टी है, जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है? Who are you most confident in national security? 31 परसेंट लोगों ने बीजेपी को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टी कहा, जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है।

यह केवल वर्ष 2014 की बात है। इसके बाद तो अनेक ऐसे काम हुए हैं, जो सरकार ने किए हैं, जिनसे देश की सुरक्षा हुई है। मोदी जी का प्रधान मंत्री बनने से पहले एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उनसे पूछा गया कि जब कोई आतंकी ग्रुप या रोग नेशन हमला करता है, तो आप किस तरह से जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये भारत का उन्हीं के तरीके से जवाब देने का एक उदाहरण है। आज देश सिक्योर हो रहा है और टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। प्रधान मंत्री जी द्वारा इंटरनेशनल एंटी टेरर अलायंस बनाया जा रहा है। जो वर्ल्ड ऑडर है, उसमें भारत अपने-आप में उभर रहा है। बदलती वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत भारत बदल रहा है।

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): I want to remind that when Shri Vajpayee Ji was the Prime Minister, Kargil war took place. It was he who ordered the Air Force to strike with whatever weapons they have so that the war could be ended and he succeeded. I think, as you were in the Army, you knew how many casualties you would have had. It was his decision, master decision, to use whatever you have and destroy the enemy in those very bunkers, that were our bunkers, that they were sitting in. You must be clear about it. He did it and he did it with firm determination.

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर: सर, बदलती वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत का स्थान और मजबूत होता जा रहा है। There are possibilities for India to emerge even stronger. भारत का मानवता हेतु हमेशा एक बड़ा रोल रहा है। केवल अभी ही नहीं, बल्कि सदियों से ऐसा रोल भारत का रहा है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' महाउपनिषद् में ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। इसे हम अपने सिद्धांत मानते हैं और अगर हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते है, तो पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री जी ने न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि दूसरे देशों से बात करके इस तरह के नियम भी बनाने शुरू किए, ताकि एक एंटी टेरर अलायंस तैयार हो सके। ब्रिक्स देशों में पूरी दुनिया की 41 प्रतिशत आबादी रहती है। वहां पूरी दुनिया की 24 परसेंट जीडीपी है। उनके

साथ एक काउंटर टेरजिज्म प्लान अडॉप्ट किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उन्हें यह अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित किया। उसी तरह से जी-20 समिट के अंदर Comprehensive global strategy to combat terrorism and a greater role for United Nations. इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने जोर दिया। यूएस के प्रेसिडेंट के साथ बायलेट्रल वार्ता, दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्रियों के साथ उन्होंने बात की। पूरी दुनिया के अलग-अलग राष्ट्रों से इस संबंध में बातचीत हुई कि किस तरह से सारे देश एकत्र होकर एक एंटी टेरर प्लेटफार्म बना सकते हैं?

उसी का नतीजा है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को और मजबूत करना चाहिए तो आज जो बिल आ रहा है, वह यूनाइटेड नेशंस की विचारधारा से आ रहा है, उनकी सोच के हिसाब से आ रहा है।

प्रधानमंत्री जी ने 75वीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेम्बली के अंदर आतंकवाद के ऊपर अपनी आवाज उठाई। स्मगलिंग ऑफ इल्लीगल वेपन्स के ऊपर आवाज उठाई, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। अभी हाल ही में इंडिया के जो डिप्टी, यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट रिप्रेजेन्टेटिव हैं, उन्होंने बॉयोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स के ऊपर जो कन्वेंशन है, उसको और मजबूत करने की बात रखी है। भारत लगातार दुनिया की ताकतों को प्रेरित कर रहा है कि इस तरह के कानून बनें ताकि आतंकवादी को कहीं छिपने की जगह न मिले। ये जो weapons of mass destruction हैं, ये non-State actors, terrorist outfits के पास ये पहुँच सकते हैं और उससे बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। जिस तरह से मैंने कहा कि अभी तक जो वर्ष 2005 का कानून था, वह सीमित था। उस कानून को और मजबूत किया गया है। अब सरकार ऐसे व्यक्ति, जो weapons of mass destruction के अंदर शामिल हैं, उनकी फंडिंग के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी तरह जो उसमें सम्मिलित हैं, उनके अकाउन्ट्स, उनकी सम्पत्ति को फ्रीज करने की ताकत रखता है। वर्ष 2005 का जो कानून था, वह बहुत सीमित था। वह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस था कि जो मैन्युफैक्चर करेगा, उसके ऊपर कानून लगाया जा सकता है। क्या सरकार इंतजार करेगी कि जब तक पूरा का पूरा weapon of mass destruction मैन्युफैक्चर हो तभी वह उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर सके? उसमें तो बहुत देर हो

जाएगी। प्रोलिफरेशन की बड़ी संभावनायें रहती हैं और इसी कारण से आज यह अमेंडमेंट इस बिल के अंदर लाया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि Zero Tolerance towards terrorism; Zero tolerance towards State aggressors और यह जो weapons of mass destruction हैं, ये बड़े साधारण तरीके से बनाए जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर एक टेस्ट केस किया गया कि एक सिविलियन किस तरह से रिटेल शॉप्स पर जाकर इन केमिकल्स को इकट्ठा करके एक वेपन बना सकता है और यह हर तरह से संभावना है कि ऐसा संभव है और इसीलिए इसको रोकने के लिए यह काननू लाया जा रहा है। शैल कंपनीज हैं, छोटी-छोटी चीजें तैयार करेंगी, वह अपने आपमें विनाश का पूरा वेपन नहीं होगा, लेकिन उसका एक हिस्सा हो सकता है और जब ऐसे कई हिस्सों को जोड़ा जाए तो एक वेपन, पूरा का पूरा हथियार तैयार हो सकता है। इसी कारण से जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, जो भी इन केमिकल्स को, बॉयोलॉजिकल वेपन्स को तैयार कर रही है, उसको रोका जा सके। Money laundering and funding of weapons of mass destruction, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए फाइनेंस के ऊपर कि फाइनेंस का रूट क्या है, रास्ता क्या है, जहाँ से फाइनेंस आ रहा है, कौन व्यक्ति इसको फाइनेंस कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। यह एक जीता जागता उदाहरण है कि 9/11 के बाद अमेरिका में बहुत कम आतंकी हमले हुए हैं और उसका कारण यही था कि उन्होंने रूट कॉज को पकड़ा।

जहाँ पर फाइनेन्सिंग हो रही है, उसको पकड़ा और उस कारण से इसको रोका जा सका। इसीलिए आज यह वर्ष 2005 के एक्ट का जो अमेंडमेंट आ रहा है, इसके अंदर मुख्य बात यही है कि जो फाइनेंस कर रहा है, अब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, अब उसको सजा मिल सकती है। अब इसके जितने भी फाइनेन्सियर्स होंगे, वे उतने ही शामिल होंगे, जितने इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन से यह बिल्कुल मिलता हुआ है, उसी विचारधारा का है। The proposed amendment aligns with the United Nations Resolution 1540 of 2004.

महोदय, हम हर तरह से भारत को मजबूत करने के लिए, देश-दुनिया की जो ताकते हैं, उनके साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन की विचारधारा के साथ मिलते हुए ऐसे कानून बना रहे हैं, जिससे देश के अंदर

सभी नागरिक सुरक्षित रह सकें और कहीं इस तरह का हमला न हो, जैसे Nerve gas agents, जैसे टोक्यो में हुआ या Anthrax हुआ या और कोई नए तरीके से, कोई क्रिएटिव तरीके से कोई weapons of mass destruction लेकर आए। एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है। हमारी निकटता कुछ ऐसे देशों के साथ है, जो weapons of mass destruction के विचारों के साथ चलते हैं और कई बार वे weapons of mass destruction या केमिकल वेपन्स या बॉयोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल कर चुके हैं या इस्तेमाल करने की संभावना रखते हैं। इसीलिए हमारे देश को पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है कि हम हर हद तक अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकें। आज जो यह अमेंड विदेश मंत्रालय लेकर आया है, मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Mr. Chairman Sir, I thank you for the opportunity that has been given to me to comment upon Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022.

Sir, I am happy that the Government has brought the Bill to strengthen the earlier legislation which was brought during the UPA Government in 2004 and 2005.

I recall India's role in the domain of disarmament. Ever since Independence, India's Foreign Policy has been in pursuit of global nuclear disarmament. In 1998, at the Special Session of the United General Assembly on Diasarmament at New York, the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, gave a proposal to the United Nations for a phased elimination of nuclear weapons in a time bound framework. But that attempt did not succeed since some of the countries were not cooperating at that time. Since then, time and again, we proved India's status, though we got the status as nuclear weapons State, and we did not mitigate our stand that our objective is nuclear weapon free world.

Sir, India all along advocated International Non-Proliferation Agreement under which countries would agree to stop production of fissile material to be used as weapons but all the attempts including the proposal that was made by the then Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, were futile since the States which were declared as nuclear weapon power States were not willing to accept some of the terms which were proposed by Shri Rajiv Gandhi at that time.

In 1972 and 1998, we have come across some exercises like that of Pokhran but that does not give any impression about us that we are not against disarmament. We proved that all our efforts in this nuclear domain is only for our security and integrity.

Sir, the Bill is aimed to fulfil a limited purpose, namely, to prohibit financing of any activity in relation to weapons of mass destruction and freeze such accounts if any. That is the provision available in the Bill. As such, it is completely consequential to the earlier legislation. Everybody in the House has welcomed it. There is no deviation in that stand.

On the other hand, using this occasion, I want to touch some information on the Non-Proliferation Treaty. Though we are not party to that, in letter and spirit, off the record, we are abiding by the NPT. Even when we are not a member of the NPT, we are strictly following the Treaty. I want to recall some memories, as such.

What type of tangible achievements are going to be made by these legislations passed by India or any other country under the NPT or non-NPT? That is the apprehension in the mind of everyone. What is the mechanism available to holistically implement a legislation passed by the respective Parliament of the State which really

wants to have peace, irrespective of the political entity of the State? That is the question.

My friend from the National Indian Congress says that we are not having adequate mechanism in terms of aircraft and other mechanisms to curb this menace. But when we are making a legislation like this, to implement such a legislation, what type of a Treaty are we going to enter into with other countries? If other countries would not be in line with this legislation, what will be the purpose or solution of this legislation? I have my own doubt about it.

Sir, what did America do in Iran in the name of proliferation? In the name of proliferation, America entered into Iran and did all the inhumane activities. Mass destruction was done in the name of proliferation. Nobody could stop it. Now, what is happening in Ukraine? Russia cannot be stopped by America. America did a wrong thing in Iran and the same wrong thing is being done by Russia. But both the countries are silent. The entire humanity is in peril.

That is why, I want to submit my own apprehension before this House. I want to invite the attention of the hon. Minister through you, Sir, that just making legislations, I think, cannot be a holistic approach to curb the menace. Let some international treaties be initiated by the United Nations.

My learned friend, the hon. Minister, is having a rich experience through his service in various countries. He might have met with many Ministers, many political heads of countries across the world. He must have witnessed many incidents in respective countries where he worked. Yes, State-wise legislation is essentially needed. But what is needed more is a collective and holistic mechanism through the

United Nations or any other forum not only to curb the menace but to implement this type of legislation in a proper manner irrespective of State boundaries. That has to be addressed properly.

Sir, what type of hypocrisy is being perpetuated in North Korea by America? There are many incidents in the world. What is happening in Ukraine? Countries including America have become helpless to address these issues. There are hundreds of incidents of pilferage in black market by the underworld of passing nuclear knowledge, materials and equipment. The hon. Minister might be aware of all these things. Sir, as reported, there are about 34,500 nuclear weapons at present in 50 countries excluding the weapons with the terrorists. As the House is aware, a few years back, a Pakistani nuclear scientist had stirred the issue of transfer of technology of nuclear weapons by proliferating them to the other countries. The world has witnessed this. What happened after that? A new emerging situation and an emerging challenge about the proliferation has arisen as a scientist of a neighbouring country has violated the commitment given to us by Lahore Declaration. The hon. Minister must be aware of what Lahore Declaration says. That was signed by the then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Musharraf. I am quoting from the Lahore Declaration: “The two sides will engage bilateral consultation on nuclear doctrines to development confidence building and to avoid conflicts between us”.

This Declaration was signed by the then Prime Minister Shri Vajpayee and Shri Musharraf. Was it abided by Pakistan? Bilateral talks, agreements, treaties, diplomatic relations at the Minister level or at the Ambassador level or the Secretary level – all these have become a mockery now-a-days. That is why, the Government

has to think what type of mechanism we can put forth before the United Nations to address these issues in a holistic manner.

Sir, there is a big market of nuclear trafficking as the United Nations report says. The report suspects that there are underworld operations behind it. But still, there is no holistic approach. A few years back, the United Nations Security Council requested all the States to adopt measures to criminalise the assistance of acquiring weapons of mass destruction. I think that this Bill has been brought to fulfil this obligation of United Nations Security Council. I wish I am correct in this regard. For this reason, I welcome the efforts of the hon. Minister and the Government.

Sir, I conclude with the words of the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. In his first address to the nation, he said:

> "India is a responsible nuclear power. We will continue to work to prevent proliferation of weapons of mass destruction. At the same time, we remain committed to the goal of universal nuclear disarmament."

Sir, I am happy this Government is keeping the commitment which was given by Dr. Manmohan Singh without any reservation and criticism.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022. This Bill has been brought forward in the interest of national security and national interest. So, we support the Bill.

Sir, this Bill is formed out of the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) to prohibit financing of terrorist activities. It empowers the Central Government to freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic

resources for preventing such financing; prohibit making available funds, financial assets or economic resources for any prohibited activity in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems.

This Bill has been brought forward in a hurry because only on 4th April, the United Nations, meeting at Geneva, expressed deep concern over proliferation of weapons of mass destruction. Our Permanent Representative Dr. Pankaj Sharma said that India has been drawing the attention of the world towards these threats and the need to strengthen international cooperation to address them through its annual consensus. He said: “We are deeply concerned about the proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems, which endangers international peace and security”.

Sir, the whole theory is about a terrorist getting his hands on weapons of mass destruction. What are weapons of mass destruction? They are, nuclear, radiological, biological or chemical weapons. The weapon of mass destruction was last used in Hiroshima and Nagasaki in 1945. Since then, though the world has seen many small wars, weapons of mass destruction, which kill millions of people in minutes, have not been used. This is called Mutually Assured Destruction (MAD) and, that is why, nobody goes for it. But now, there are eight countries in the world, China, Russia, North Korea, Pakistan, India, France, UK and USA which have got weapons of mass destruction. This includes India and Pakistan and five of these countries are signatories to the Non-Proliferation Treaty (NPT). India has not been a signatory to it. We have always cited our own security concern and, that is why, we have not signed

the NPT, though we are for disarmament. Mr. Raja spoke at length about Shri Rajiv Gandhi's initiative in the matter.

Now, the important thing is to ensure the safety of our country in future. We may notice that in the 9/11 terrorist attack America had their twin towers destroyed. Since then, they set up a new department called, Department of Homeland Security and since that time, no major terrorist incident has happened in the United States of America.

If you go to USA, not as a Minister but as an ordinary person, you would realise that they have really tightened their homeland security. The main point is to tighten our own homeland security so that this does not happen.

Now, having said that … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): What is happening in West Bengal? … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: That is not very important. You went to Bengal and lost all the seats. That is why, that place is always in your mind. Why do you forget your defeat? You were going around in those villages and you lost all the seats … (*Interruptions*) Why are you talking about it? You are now a Minister of the Government of India. You forget about your defeat in Bengal … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray, kindly address to the Chair.

PROF. SOUGATA RAY: Yes, Sir.

We have gone through this process long ago. We remember Pokhran, 1998. We remember, just to get out of US sanctions, Jaswant Singh-ji and Strobe Talbot

talked for hours together, days together to bring the Americans to understand our position with regard to vis-à-vis Nuclear Proliferation.

Now, the External Affairs Minister, who as I said, is a diplomat and taciturn, does not waste a single word, does not make a single wrong comment, made a comment today that the world order is changing. He said that he will be on the right side of the world order. I would like to know from the hon. Minister, what world order is he talking of, and which side will we be. Yesterday, I raised some questions. He was busy and I instigated him. He did not reply. I asked: "Why has India gone into passive diplomacy where our diplomacy consists only of the Prime Minister ringing up Putin and Zelensky, and the External Affairs Minister meeting the British Foreign Secretary or the Russian Foreign Minister?

Do we not have anything else?" Tanks of one country are pummelling another country. Leave aside whether Zelensky is pro-American or Putin is right. We do not ask. But look at the courage that the Ukrainians have shown. Everybody thought that Russian tanks would cut through Ukraine like a knife through butter. But the people in Ukraine have resisted which proves that nationalism is still a force in this world.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सर, क्या यह कोई तरीका है? … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : रूस अटैक करेगा, क्या यह अच्छा है?… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात रखिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

प्रो. सौगत राय : सर, इस …* को रोकिए।

Sir, I am saying that we should not take sides. But I say that when a country is being attacked even in today's day and age, we should sit up and take notice. Jawaharlal Nehru would not have been a silent spectator. India's Panchsheel does not advise being a silent spectator to aforesaid genocide. India must be proactive considering her size, her importance.

Our diplomacy … (*Interruptions*) आप लोगों में से जो भी बोलेगा, मैं भी जयशंकर जी को बोलने नहीं दूँगा आप बड़ा …* बने हैं।… (व्यवधान) आप लोग कुछ नहीं करते हैं।… (व्यवधान) यह जगह चेंज करके इधर बैठता है। यह रोज यहाँ पर …* करता है। क्या ऐसा ही होता है? …* … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी आवाज को थोड़ा कम रखिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: You are speaking on an international relations.

PROF. SOUGATA RAY: Why should a Minister disturb me? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप ऐसी बात नहीं बोलिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ कड़वाहट हो। अभी आप अपनी बात रखिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

PROF. SOUGATA RAY: I shall not be cowed down by any threat. I am addressing you.

माननीय सभापति: आप ऐसी बात नहीं बोलिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ कड़वाहट आए। आप अपनी बात रखिए।

---

* Not recorded

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I am slowly in a process of concluding my speech. I started my speech by supporting this Bill. I started by praising Mr. Jaishankar. I said that the Foreign Minister must persuade the Government to take a more pro-active role in the matter of conflict between Ukraine and Russia.

16.00 hrs

What is wrong in that? I am again urging him to take a more proactive role in bringing the world from the brink of Mutually Assured Destruction (MAD) to having a better nuclear-controlled regime. India is totally silent on this issue. Only some officers go here and there. We have not heard a single statement by the Prime Minister on the problem of nuclear proliferation. We have not had any major statement from the Prime Minister on the matter of one country invading another country. Yes, it is said that Foreign Policy is 'enlightened self-interest'. I know that. We have read what Machiavelli said but Foreign Policy is not Machiavelli alone. Foreign Policy is also Panchsheel and Gautam Buddha's teaching. We are a 5000-year-old country. We must have a proper Foreign Policy. That is why, Sir, again, I am assuring the Minister our full support in any further efforts he may take towards the activities of rogue states, rogue individuals, and criminals who tend to use weapons of mass destruction. But, let me tell you, Sir, that on the internet they are showing a method in which a college boy can assemble together a small nuclear device. The point is not that but the point is to have vigilance. Abraham Lincoln said that eternal vigilance is the price of liberty. Are you vigilant enough? Do we keep track of who is doing what in the country? That is the important thing. We must defend ourselves.

Lastly, Sir, I will stop by quoting two lines by John Donne, the famous poet, quoted in Ernest Hemingway's 'For Whom the Bell Tolls'. He said:

Any man's death diminishes me,

because I am involved in mankind;

and, therefore, never send to know for whom the bell tolls;

it tolls for thee.

When somebody else is attacked, I feel the bell is tolling for me. We also have to defend our heights in Galwan or in Pangong Lake. We have to defend our areas in Arunachal. We have to find out friends who defend us in this difficult situation and that should be the crux of our Foreign Policy.

With that, Sir, I support the Bill and thank you for allowing me to speak.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Shri Sanjeev Kumar ji.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, this word …* is unparliamentary or not. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It should be removed from the record.

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, ये बार-बार अपने भाषण में कहते हैं कि मैं बार-बार अपनी सीट चेंज करता हूं।… (व्यवधान) ये इतने सीनियर हैं, इनको पता ही नहीं है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई सीट, केवल कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़कर और अपोजीशन के कुछ…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : कभी उधर बैठते हैं, कभी इधर बैठते हैं।… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : वह मेरी इच्छा है। वह चेयर तय करेगा।… (व्यवधान)

---

* Not recorded

माननीय सभापति : श्री संजीव कुमार जी।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you hon. Chairperson for giving me this opportunity to speak on the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022, on behalf of YSRCP.

Sir, this Bill seeks to amend the principal Act of 2005. The proposed amendment states that no person shall finance any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act and the Government of India shall have powers to freeze attach the assets of such person or organisation, indulging directly or indirectly in such unlawful activities.

Sir, the main objective of the Bill is to prevent unlawful activities relating to biological, chemical and nuclear weapons including export of weapons or transfer of technology to anti-social elements.

Sir, YSRCP supports the proposed amendments because they are related to national security and the security of mankind.

Sir, I would like to speak in Telugu.

*While thanking our Honourable leader Shri YS Jagan Mohan Reddy and people of Kurnool for giving a person like me from ordinary family, this opportunity to speak in Parliament which is a Temple of the democracy. On behalf of YSRCP, I would like to express my views. Recently, United Nations Security Council (UNSC)

---

* ...* English translation of this part of the speech originally delivered in Telugu.

has come out with guidelines against use of Weapons of Mass destruction. Through resolution no. 1540, UNSC has placed responsibility on Member Nations. We need to amend our laws in line with International Society. This is our international responsibility. Therefore, I feel that today we have this need to amend our law. As per the resolution of UNSC, there will be financial sanctions on countries which violates law.

The objectives of this amendment is to punish those who manufacture weapons of mass destruction, to seize financial sources of those persons or organisations which support such unlawful activities, and to see that funds are not collected to support such activities. It is commendable that this act which was passed in 2005, is being amended now after 17 years.

Our enemy nations which are not capable of fighting with us are sowing seeds of hatred in the minds of disoriented youth of our country and thus indulging in indirect war. For such nations, this law should serve as a warning.

Our country is moving ahead in disarmament. Because we believe that whole world is one family. We want everyone to prosper. We want that nuclear weapons are wiped out from the world. This amendment is an effort in that direction. India is committed to 'No first use' policy when it comes to use of Nuclear weapons. Even though we are capable of retaliation against hostile countries which may attack us. We still wish peace. Our country is fighting terrorism for so many decades. If terrorists get hold of weapons of mass destruction, we all know the consequences. We should respect the resolution of United Nations and also make other countries to honour this resolution.

Sir, we should talk about biological weapons in this context. COVID pandemic should be considered as a biological warfare. Before a virus infects a human being, it should first infect an animal. After multiple mutations in animals, that virus would infect human beings. No one could prove that Covid was infected through animals. It is believed by intelligentsia that American Scientists and Chinese Lab were conducting some experiments, which accidently resulted in Corona pandemic throughout the world. We witnessed how humanity suffered during Corona pandemic. Due to scarcity of oxygen, we lost lakhs of lives. I would like to inform the House that Corona is known to mankind for the last 60 years. There were many diseases which were treated successfully. But there are many diseases which are far more dangerous than Corona. Whether we are prepared for any such biological warfare in future? Only due to lack of oxygen, we lost lakhs of lives. We need to have an aim and strategy in place, to face any such crisis in future. In this direction, we need to strengthen our basic health infrastructure, by having adequate quantity of oxygen, ventilators and medicines at village level as well. This should be our plan.

By mere passage of these bills, we should not assume that we are capable of handling any crisis. Like a knee jerk reflex, we witnessed intense suffering due to Corona pandemic, therefore we should be prepared for such unforeseen perils in future so that we can manage them efficiently.

I have a question in my mind for the last 40 years and I would like to seek an answer from the respectable members of the House. India was a slave for more than 1000 years, under foreign rule. The main reasons were, we do not have modern weapons then. There was no unity amongst 750 kings in India. But now the situation

is different. We are an united country. We have powerful weapons with us. Therefore, many countries fear our capabilities. I thank Union government for making efforts in strengthening our country's capabilities.

I thank, hope of weaker sections and trendsetter Shri YS Jagan Mohan Reddy for giving me this opportunity. I also thank honourable Chairman for giving me opportunity to speak on an issue of national security.*

Jai Hind.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय सभापति जी, आज माननीय मंत्री जी ने द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देअर डिलीवरी सिस्टम्स (प्रोहिबिशन एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़) अमेंडमेंट बिल, 2022 लाए हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसी गतिविधियों में कई भारतीयों की जानें चली जाती हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। इससे देश में जो हलचल मच जाती है, इस पर काबू करने की आवश्यकता है। वेपन्स के इस्तेमाल से पूरी दुनिया को परेशान करने की कोशिश हो रही है, इस पर काबू करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारत सरकार की तरफ से इनीशिएटिव लेकर बिल पेश किया है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में शांति और सुरक्षा का निर्माण करने के लिए भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2005 के 17 साल पुराने कानून में पहली बार संशोधन किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन हथियार, जैसे परमाणु, रेडियोलॉजिकल, रसायनिक, जैविक और अन्य उपकरणों के गैर-कानूनी उपयोग पर अंकुश लगाने का काम होने वाला है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र परिषद् में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से अहम निर्णय लिया गया है कि 17 साल पुराने कानून में संशोधन करें और नए सुझाव लाकर नई दिशा की ओर बढ़ें। अब इसकी आवश्यकता का निर्माण हो चुका है। जैसे सौगत दा ने कहा कि सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन के

हथियार जिनके पास हैं, वे आठ देश हैं। उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि उनके पास ऐसे वेपन्स हैं। इन आठ देशों में चीन, भारत, फ्रांस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, युनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। इन देशों ने खुद डिक्लेयर किया है कि जब विश्व में शांति बनाए रखने की आवश्यकता पैदा होगी तो विनाशकारी अस्त्रों का नाश करने को तैयार रहेंगे। इसमें भारत देश भी है, यह हमारे लिए गर्व की बात है।

महोदय, विधेयक में जैविक, रसायनिक और परमाणु हथियारों की विवरण प्रणाली से संबंधित गैर-कानून गतिविधियों को शामिल किया गया है। सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों की रोकथाम के लिए सामग्री, उपक्रम और प्रौद्योगिकीकरण निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिए एकीकृत कानूनी प्रावधान करने की आवश्कता है। सब देशों को खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, गैर-कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, आतंकवादी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसे में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए और पाबंदी लगानी चाहिए। सब देशों को यह निश्चय करना चाहिए। इस दिशा में भारत देश आगे जा रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और युनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल के अनुसार सामूहिक विनाश के हथियार कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को मार सकते हैं।

यह अभी दिख रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद ऐसे हथियारों का उपयोग करने से कितनी संख्या में मानव जाति का संहार हो रहा है, वह पूरी दुनिया जान रही है। इसलिए, मास डिस्ट्रक्शन करने वाले जो वेपन्स हैं, उनको विनाश करने की आवश्यकता का निर्माण हो चुका है।

'परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का पक्षधर है', इस पर हाल ही में भारत के विदेश सचिव ने जब प्रतिनिधित्व किया, तो उन्होंने कहा कि भारत देश परमाणु हथियार मुक्त दुनिया का पक्षधर है और भारत परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य में हमेशा आगे रहेगा। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। आतंकवादियों के हाथ में कैमिकल हथियार पहुंचने से अलग-अलग देशों में कितना नुकसान होता है, वह रूस और यूक्रेन के युद्ध में दिख रहा है।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के माध्यम से कहना चाहता हूं, इसके पहले कई वक्ताओं ने भी कहा है। 26/11 के हमले में अमेरिका में आतंकवादियों ने ऐसे ही विनाशकारी वेपन्स से उस पर हमला किया था। लेकिन, अपने देश में मुम्बई ने भी वर्ष 1992-93 में बम ब्लास्ट देखे। मुम्बई बम ब्लास्ट में सैंकड़ों

लोगों की जानें गई थीं। उसके बाद, 26/11 बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था। लेकिन, इस संसद के बाहर भी वर्ष 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। आतंकवादियों के हाथ में वेपन्स आते हैं, वे उस वेपन्स का दुरुपयोग करके भारत में, चाहे वह संसद हो या मुम्बई, कई जगहों पर आतंकवादियों द्वारा हमला करने के बाद लोगों की जानें गई हैं। उसका अनुभव हम सभी मुम्बई वासियों ने और पूरे सांसदो ने लिया है।

इसलिए, अब ऐसे वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की आवश्यकता का निर्माण हो चुका है। हमारे गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, उन्होंने उसमें भी यही कहा है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि – 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।'

सबकी भलाई होनी चाहिए और सबको शांति से जीने के लिए जागरण होना चाहिए। इसलिए, ऐसे वेपन्स को नष्ट करना आज का एकमात्र संदेश भारत देश के माध्यम से जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी का आभार और अभिनन्दन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Thank you, Sir. I rise to speak on the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022 brought by our hon. External Affairs Minister. This is a very old Act. In 2005 when this Act was passed, it banned only manufacturing of Weapons of Mass Destruction.

Sir, the Bill seeks to provide for provisions against financing of proliferation of Weapons of Mass Destruction and their delivery systems so as to fulfil our international obligations. The United Nations Security Council's targeted financial sanctions and recommendations of the Financial Action Task Force have mandated against financing of proliferation of Weapons of Mass Destructions and their delivery systems, and this Bill has been brought in this background.

Sir, when it comes to preventing Weapons of Mass Destructions and proliferation, we need to be conscious of both State and non-State actors. Money

laundering, terrorist financing and financing for proliferation of weapons of mass destruction can have negative effects on a country which may include increase in violent and organised crime and corruption. From an international perspective, it can result in loss of reputation in the international market, loss of donor functioning, loss of foreign direct investment and loss of credibility for the financial sector. Therefore, identifying, assessing and understanding proliferation financing risks on a regular basis is very much essential.

Sir, India has always made its position clear on this issue. India opposed signing the NPT and CTBT for valid reasons. India had campaigned for imposing a ban on nuclear weapons' testing for a long period. In 1954, India initiated a global call at the UN Disarmament Commission for putting an end to nuclear testing and a freeze on fissile material production. In 1978 and 1982, at the Special Sessions on Disarmament, India proposed banning nuclear testing. In 1988, India introduced an action plan for the time-bound elimination of nuclear weapons. However, in 1993, India took a different course and opposed the treaty on the ground that it is silent on destruction of existing nuclear stockpiles.

The treaty also does not contain any time-bound programme for destruction of nuclear weapons, thereby leaving nuclear disarmament solely to the discretion of nuclear weapon States.

Sir, India underlined the importance of the Chemical Weapons Convention and the Biological Weapons Convention as examples of non-discriminatory treaties in the field of disarmament for the total elimination of specific types of nuclear weapons of mass destruction. India reaffirms that disarmament is a primary goal of Chemical

Weapons Convention and should remain a priority till the complete destruction of all chemical weapons is achieved.

India is a responsible nuclear weapon State and is committed, as per its nuclear doctrine, to maintain a credible, minimum deterrence with the posture of no-first-use and non-use against the non-nuclear weapon States. At the UN, India supports the full and effective implementation of Chemical Weapons Convention and emphasises the strengthening of the OPCW to fulfil its important mandate.

The present Bill is in our national interest and in accordance with our international obligations. I, on behalf of my party Biju Janata Dal, support this Bill. We always support any step in the direction of our national security and global peace.

In fact, our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaikji has advocated for inclusion of *ahimsa*, that is, non-violence in the Preamble to our Constitution. That will strengthen India's position as a leader of peace.

With these words, I support the Bill and conclude. Thank you.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I rise to support the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022.

16.24 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

The Bill, under clause 2, seeks to insert a new section, section 12A which reads out that no person shall finance or provide financial services for any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems.

Sir, I have two small apprehensions on this Bill, and I am sure that through my discussion over here, those points would be addressed. In Resolution 1540 (2004), the Security Council decided that all States shall refrain from providing any form of support to actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery, in particular for terrorist purposes. The Resolution requires all States to adopt and enforce appropriate laws to this effect as well as other effective measures to prevent the proliferation of these weapons and their means of delivery to actors, in particular for terrorist purposes.

Nonetheless, detecting proliferation-relevant illicit financing is even harder than detecting money laundering or terrorism financing. The risks posed by Weapons of Mass Destruction stem not only from ready-made bombs, nuclear, chemical, or radiological material but also from dual-use goods and technology that are traded, shipped, and used globally. Even the components for nuclear power reactors that generate electricity rely on dual-use components and technology that can be used in a nuclear weapons programme. You can find these things in laptops, transistors, and in instant coffee maker also; the same technology is used, which, sort of, is related to the same matter that we are discussing here. A common perception within the private financial sector is that proliferation financing controls refer to the implementation of country-specific sanctions, for example, those designed to prevent North Korea and Iran from tapping into the global financial system for proliferation activities.

However, country-specific sanctions should be seen as integral but not the only part of proliferation financing controls. Financial institutions are aware of UN Security

Council resolutions though they are not always well-equipped to implement country-specific ones. Moreover, sanctions implementation is the limited capacity of financial institutions to distinguish proliferation activity. Financial institutions see only a small part of data related to a given transaction and they do not have the technical expertise to distinguish what is proliferation-relevant and what is not. So, that is a very difficult thing for financial institutions to figure out and that is something that has to be taken into consideration.

One of the most important areas for the Government to work upon is on informing the private sector promptly to match changes in UN designations of entities and individuals. For example, if the UN Security Council designated new entities or individuals as proliferators, but a given country failed to update its lists, what happens is that these financial institutions continue to trade with these entities because they are not made aware of these changes in time. So, that is also something that needs to be considered.

Finally, I would like to say that there are certain practicalities that come into these issues and they need to be resolved. Financial institutions use software that screens transactions against the lists of UN-designated entities and individuals. In practice, such screening systems return a high number of false positives. Basically, what that means is that because of name similarities, when you update the list, a high number of names come back to this system as false positives and that percentage is around 95. So, this is a huge risk. Risk managers spend a lot of time trying to figure this out, which is very, very difficult for them. For example, they have to take such

high volume of numbers and names, and they have to get into a menial job of separating them, which they could use for some other thing.

On behalf of Bahujan Samaj Party and *behen* Kumari Mayawati ji, I would like to support this Bill. I have one more request. We have not passed a single Bill unanimously. There are many Bills that have been passed, and there have been support from the Opposition as well. I think such a Bill, when everybody is supporting it, कम से कम चेयर को भी सर्वसम्मति से हम लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा भी हाथ है। धन्यवाद।

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Sir, I have one request. We have hon. MLAs from Maharashtra. I think it will be nice if you could welcome them.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here in support of the Bill that we are discussing today. I would definitely like to quote what the India's stand at the UN is. It says that "they are deeply concerned over proliferation of weapons of mass destruction and their delivery system." The earlier speaker, Professor Saugata Babu has already spoken about it at length, but in a synopsis, I would like to say that "India supports the full and effective implementation of the Chemical Weapons Convention and emphasises the strengthening of the OPCW to fulfil its important mandate."

Sir, it is very good that we have brought in this Bill and India has always had a very good and a positive image of a peace-loving and peace-making country. So, I congratulate the hon. Minister for bringing in this Bill. But I would like to bring to the notice of the House of what he said. He said that we have come to the "new world order". It is true that the world has changed. There is a book by Mr. WS Carus, called

Defining Weapons of Mass Destruction. It is one of the papers where he had said that the Centre of Study of Weapons of Mass Destruction, which is a National Defence University, has recommended “why do we not expand the scope given how the world is changing?”. Even the war today globally is a hybrid war now as we call it. They have recommended that India’s definition of ‘weapons of mass destructions’ is for nuclear, biological and chemical weapons. So, can we expand it? It may not be literally in this Bill. Maybe in the next few months you could consider this. This is my request to you. There are these new challenges because of this new world order. Can we talk about radiology, talk about high explosives, talk about weapons of mass destruction or in fact potentially include CBRN weapons, other means of causing massive disruptions such as cyber-attacks, electro-magnetic attacks, munitions? If we could make it, I think we will really set a very good order, and a new precedent in the world that India is very serious and committed. That is the only suggestion that I would like to make.

Besides this, I would like to put something on the table. In the larger scheme of things, it is a very small example. In Maharashtra recently there was a small power crisis in Mumbai city for over three hours. People said it was an act of hacking. It was the electromagnetic system which collapsed.

This could be a very small trial, we do not know. But for a city like Mumbai to have no electricity is a big thing. We did not know how it stopped, how it collapsed. There was nothing wrong with the grid. Could it have been an attack? I have no evidence to prove it, but this is how the story begins. The only point I am trying to make here is, could we consider broadening the definition?

Besides this, I would like to talk about some other issue which nobody else has mentioned and that is the zoonotic diseases. It is like a pandemic. There is a story that COVID-19 was probably an attack on the globe. Could we have a broad discussion on this? This is my suggestion to the hon. Minister. What is interesting in this entire debate is this. When we brought the nuclear agreement, at that time we were sitting on that side and you were in a different role, and there were a lot of objections to the agreement. I do not want to get into a *tu tu main main* on this because it is a very serious Bill. I am so glad that the agreement that the hon. Manmohan Singh Ji had led at that time to put India on the global map today has become a reality. In the Nuclear Suppliers Group, we are a very important part. I really want to know from the hon. Minister that with all the new friendships that you have made in the last few years, why have we not joined the Group as yet? What are we doing to excel our position? America was very positive about it. There were a lot of nations which have supported India, but there are nations which have objected like New Zealand, Ireland, Austria, China. They have objected to us. Now. What is our position with such wonderful relations? I still remember this article. I was too tempted and I hope you indulge me with this and take it on a little lighter note or a little banter in Parliament, sometimes. There was a story which I was too tempted to talk about today. It says, “They talked, they posed, and they left.” The Indian Prime Minister and the Chinese President met 18 times since 2014. I stand corrected, it could be more. There were many, many meetings that they have had. I am a big one for dialogue. I am completely against any war.

But what has happened to our position by having so many meetings where they talked, they posed and they left? What really happened between these three activities when they talked, they posed and they left? Something more substantial should come out of it. I would like to ask the hon. Minister where this is.

Like my colleague, Shri Ritesh Pandey talked extensively about the financing of it, I would like to ask this from the hon. Minister. It is a very good Bill. I think that any such thing must be stopped. I think that the entire House in one voice supports your Bill. The only clarification that I would like to ask is that there is a note in the Statement of Objects and Reasons in 5 (b) (i) where it mentions 'freeze, seize or attach funds'. I appreciate it as it is a wonderful thing, but what concerns me and more so because it is something very new.

I am not a financial expert, but I hear so much about the darknet and the crypto, and all these funding being done through this. This is not only our problem. It is a global problem. Right now, our country has taxed it at 30 per cent. The hon. RBI Governor -- and not just the present Governor, but several Governors -- has constantly said about this kind of digital money or 'transaction' as you called it. Right now, I am really confused because it is not legal is what the Government says, but at the same time it is taxing it at 30 per cent. There is too much confusion. So, does an investor invest in it? I am asking this because tomorrow the Government will say यह तो करना ही नहीं था। If they are bringing in this into crypto, then it could be an attack here, but somebody could be paying in some other country. How are we going to 'freeze, seize or attach funds'? This is a completely grey area, which I think we must deliberate upon. It is not only about us, but it is a global issue that we need to raise.

Another thing that happened was actually a little embarrassing for us. I respect the hon. Defence Minister. He was very gracious about -- I would call it -- the 'Brahmos experiment'. It was a mistake that happened. It was a misfire. I know that nobody did it intentionally, but the hon. Defence Minister was very kind enough and showed such humility to come and say that we will take corrective action and we are having an inquiry, but it was not intended at all. But the Philippines has objected to it as per newspaper reports. I am quoting all the data that has come in there. I have no access to any information. I am going by what the media said. If the Philippines has shown concern and if these kinds of situations happen, then how are we going to control it? I think we should make it a little more academic also.

Yes, we support this Bill completely in one voice in this entire House, but we must definitely be very careful about the new technology coming in. We all are just raising our concerns even if these are just to make sure that it is a flawless Bill, and make sure that India is known for what it really is, which is about truth and it is about being a partner to everybody, with absolutely no warfare and a peace-loving nation like the Mahatma would have wanted it. Thank you, Sir.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir. I rise to support the Bill moved by the hon. External Affairs Minister. The objective of the Bill is limited. It seeks to ban funding for weapons of mass destruction and gives power to the Union Government for appropriate action against the culprits under the provisions of WMD Act.

Sir, I have a few quick points that I would like to make. Here, I would like to appreciate first the foresight of our former Prime Ministers, Shrimati Indira Gandhi and Shri Atal Bihari Vajpayee ji, in making India a nuclear State. The reason I say this is

because as we see what is happening in Ukraine, which remained a non-nuclear country since it believed the assurances given to it by the West and NATO and gave up its nuclear arms. But looking at the current situation in Ukraine, a question arises. Would Russia have attacked Ukraine if Ukraine had possessed nuclear weapons? Conversely, could Russia have attacked Ukraine if Russia did not have nuclear weapons with the confidence that it would not be countered by rest of the world?

The traditional arguments for nuclear non-proliferation have been somewhat disproven with this current case. Along with the new world order, we also need a new paradigm or a new nuclear doctrine not only to avoid mutually assured destruction between nuclear powers, which was the case in earlier days, but also how do we assure the non-nuclear countries of their sovereign rights. How do we prevent nuclear countries from misusing their nuclear threat to bully smaller non-nuclear countries? This needs to be addressed by the world at large, and India has a leading role to play in defining this going forward.

What is the future of non-proliferation really needs to be carefully examined, understood as a new paradigm needs to emerge?

One clarification I wish to seek is that the proposed insertion of Clause 12A appears to be a little vague. Here, you are saying no person shall finance any activity prohibited under this Act or under the UN Security Council Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force. I think, this appears to be a bit vague as we have not mentioned which are the relevant Acts under which you propose to take action.

So, I suggest for consideration of the hon. Minister to attach a schedule to this Bill and list the Acts, Agreements, Convention, etc. which come under the purview of this legislation.

The next point I wish to make is relating to India's full support and effective implementation of Chemical Weapons Convention, and strengthening the Organisation for Prohibition of Chemical Weapons, and mandate given to it. And, at the same time, we are also voicing our support for institutional strengthening of the Biological Weapons Convention, and bat for legally binding protocol. But, if you look again at the ongoing Russia-Ukraine armed conflict, we have seen umpteen times statements coming from Russia about use of chemical weapons, and Ukraine claiming that Russia may use biological and chemical weapons at any time. So, does it not defeat the very convention and objective which India and other countries are pursuing. If signatories to the Convention are blatantly breaking it, then, what is the use of this Convention?

Secondly, we are going to have the Ninth Review Conference of the Biological Weapons Convention this year. So, I wish to know what would be the approach of India in this Conference, in the light of ongoing Russia-Ukraine conflict. The third point I wish to make is about the effective response to a chemical or biological attack, particularly on our citizens. I wish to know what sort of mechanism we have in place, be it relating to detection or providing antidotes or decontaminate and guide people not to consume contaminated food and water. I am asking this as we have seen the vulnerability of sarin nerve gas bioterrorism attack in Tokyo, where in spite of having much better mechanism than India, which showed the vulnerability of civilian

population and killed 200 people. So, I wish to know the kind of mechanism and the national strategy that is in place in the event of a chemical or biological attack.

The next point which I want to make, I think, several Members have also asked is about the Coronavirus questioning whether it is a biological attack or not. I don't think we have been able to come to any final conclusion on this because China is neither sharing any information nor allowing any inspections. There are contradicting stories which the hon. Minister is aware of, more than what I could understand. If it is a biological weapon, the entire world could do nothing or even come to a conclusion that it is a biological weapon, leave alone taking action or imposing sanctions on China.

In such a scenario, I doubt that enactments like these would be of any help. I wish to have a response from the hon. Minister on this as well.

Sir, I feel, today, more than chemical and biological weapons, the world is threatened and facing risks posed by cyber weapons, hypersonic missiles, drone swarms, pandemic outbreaks, be it manmade or natural. Now, drones are innovative and novel delivery of weapons of mass destruction, be it chemical or biological, and are operated through artificial intelligence. So, we need to evolve strategies and create firewalls against such attacks on India. I am sure the House would like to know what efforts are being made by the Ministry in this regard since there is nothing in this Bill.

Finally, I am fully with the hon. Minister and the Government to ruthlessly crush financing any activity, which even in any remote possible way, is trying to help any activity, to prepare or produce, or help in making weapons of mass destruction, and

their delivery. But I just wish to seek one clarification. In the pursuit of India's national interest and for more benevolent use of such technologies, scientific research must have been taking place on such technologies. And, hon. Minister is aware that sort of R&D is critical for the country. So, I ask the hon. Minister to simply clarify what the Government has done to ensure that such critical research on such technologies is not impeded, even unintentionally, due to this legislation.

So, Sir, these are some of the issues I thought that I should flag and share with the hon. Minister. I request him to look into them and see how best we can strengthen this legislation from all corners to protect not only this country but also its Exclusive Economic Zone and beyond. Thank you, Sir.

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Chairperson, Sir, I do not think that anybody has a quibble with this Bill. As the hon. Minister Jaishankar explained that it is essentially to make us legally compliant with the mandates of the United Nations Security Council and the recommendations of the Financial Action Task Force, behind the original Bill which this Bill seeks to amend lies an incredible story of multi-partisanship that we as a country need to celebrate. It is a story of how we first of all created, then nurtured, and sustained our strategic autonomy without giving up our principled position towards a world where there is verifiable, universal and comprehensive nuclear disarmament.

This is a story which started at the inception of the Indian nation itself in 1948 where the Atomic Energy Commission was established. In 1954, we had the Atomic Energy Establishment in Trombay which is now called the Bhabha Atomic Research Centre which was brought into existence in 1962. This House legislated the Atomic

Energy Act and after the 1962, Sino-India conflict took place and the 1964 nuclear test was carried out by China at Lop Nur on the 16th October, 1964. We commenced our Nuclear Weapons Programme that culminated in the first peaceful nuclear explosion in 1974 under the leadership of the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi and then in 1998, when Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, we decided to make the De Jure De Facto by carrying out two nuclear tests on the 11th May and 13th May, 1998.

Why I say De Facto De Jure is because some people would recall the history of Operation Brasstacks in 1986 and the Robert Gates Mission in 1990 which essentially sent out a very, very clear signal that not only did we have the capacity in the early 90's but, unfortunately, so did our western neighbour across the border. But the incredible thing, Mr. Chairperson, is that all throughout this long journey, unlike Pakistan which opened a nuclear Walmart, – it had a rogue scientist called A. Q. Khan who was not only accused but finally even held *prima facie* guilty by Pakistan itself for proliferating nuclear and missile technology – India has been able to maintain an impeccable track record insofar as non-proliferation is concerned. I think that was the reason why in 2008 when India negotiated the Indo-U.S. Nuclear Agreement under the leadership of then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the Minister was I think the then Joint Secretary (Americas) and had played a very important role in bringing that agreement to fruition.

Not only were we the first non-nuclear weapon State in order to be able to conceptualise an agreement which effectively smashed the entire architecture of nuclear apartheid which was created when the first peaceful nuclear explosion was

carried out with the formation of the London Suppliers Group but we were able to also get a 'clean' waiver from the Nuclear Suppliers Group with regard to that Indo-U.S. Nuclear Agreement. And that brings me to a couple of questions which I have for the hon. Minister which of course may go beyond the amplitude of this Bill.

My first question is that, unfortunately, after the 2008 Indo-U.S. Nuclear Agreement and the 'clean' waiver that we got from the Nuclear Suppliers Group, we do not seem to have made much progress with regard to getting membership of that particular organisation. My colleague, hon. Member, Supriya Sule ji, had alluded to some of the obstacles that are there in certain countries which are opposing India's membership of the NSG. I would want the hon. Minister to really try and bring this House up to speed as to whether there has been any progress between 2018, when the Summit was held in Kazakhstan if I remember correctly from the top of my head, and 2022 in our efforts to get membership of the Nuclear Suppliers Group.

My second point, which was alluded to by some Members of this House, is this. We have had this impeccable track record of nuclear non-proliferation. Coupled with that we have maintained a very high degree of exactitude insofar as our delivery systems are concerned. Given that the recent inadvertent launch of the Brahmos missile which landed in Mian Channu in Pakistan which, if you go by reports in the public domain, could have not only endangered civilian aircraft which were in the vicinity of the trajectory of this missile but also may have invited a retaliatory launch given that unlike us our western neighbour actually has a first-use posture, could the Minister actually throw light as to what steps the Government has taken after this

inadvertent incident to ensure that something of this sort does not get repeated in future?

My penultimate question is with regard to something strange that I discovered while I was researching for this Bill. In the year 2018, in the Bodh Gaya blast case, the Weapons of Mass Destruction Act was invoked by the National Investigation Agency.

In fact, they invoked Sections 14, 17 and 19 of the Act. The public reports which are there, or whatever is there in the public domain is completely ambiguous about really what happened after these Sections were invoked.

Could the Minister enlighten us whether chargesheets were filed in terms of these relevant Sections of the WMD Act? As I understand it, the Weapons of Mass Destruction Act is essentially to ensure that there is no proliferation of chemical, biological, radiological or nuclear weapons. Since this was the first time that our National Investigation Agency had actually invoked provisions of this Act, could the Minister enlighten the House as to what has been the progress of those investigations?

My last point would relate to our no-first-use posture. On the 17th of August, 1999, after our nuclear test, India had put a draft nuclear doctrine in place, which was then formalised on the 4th of January, 2003 by the Cabinet Committee on Security Affairs. Since then, we have had a posture of recessed deterrence and no-first-use.

In the year 2014, just before the elections, in the manifesto which was brought out by the Bharatiya Janata Party, if I recall correctly at page 39 in subparagraph, there was a certain amount of ambiguity with regard to this no-first-use posture.

Subsequently, former Defence Minister Mr. Parrikar, when he was releasing a book, had actually gone a little further and really suggested that the no-first-use posture possibly could be under consideration. Even the current Defence Minister Mr. Rajnath Singh, on the 16th of August, 2019, had alluded to some ambiguity in it after his visit to Pokhran. The reason why I am posing these questions is because all this has created a consternation. Given the fact that our neighbourhood is extremely becoming difficult, it would be enlightening to hear from the Minister as to whether we continue to maintain a no-first-use posture or is there any rethink in Government which he would like to share with the House?

Thank you very much, Mr. Chairperson.

DR. FAROOQ ABDULLAH: Sir, when Pokhran test took place, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee took me also along. I would like to say one thing.

HON. CHAIRPERSON: If you want to speak on this, you can.

DR. FAROOQ ABDULLAH: We are proud of our scientists. With all the information they have, America had no information that India was going to do this test. I think we should take note of this and congratulate our scientists that no one in the world came to know that we had done these tests. … (*Interruptions*)

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Thank you, Chairman, Sir. I rise here in defence and support of this new amendment Bill, namely the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022. As we know, it was an old Act in the same name which was enacted in 2005, as many of our esteemed Members have mentioned. As the hon. Minister mentioned yesterday and today also that we are compliant or conforming to the

United Nations Security Council's targeted financial sanctions and the recommendations of the Financial Action Task Force which have mandated against financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems. In view of the above, there is a need to amend the said Act to provide against the financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems so as to fulfil our international obligations.

The Bill seeks to insert a new Section 12A – there is not much an amendment in that way – in the existing law which states that no person shall finance any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947, or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems. The Bill would give the Government of India powers to freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic resources owned or controlled, wholly or jointly, directly or indirectly, by such person, or held by or on behalf of, or at the direction of, such person, or derived or generated from the funds or other assets owned or controlled, directly or indirectly, by such person.

I would like to say that this amendment Bill shows the deep commitment of the Government of India to our counter-terrorism measures. I would like to congratulate our hon. Prime Minister for the way he has taken the leadership when he took over as the Prime Minister of this country, appealing to the world leaders to define the word 'terrorism' and to devise an international counter-terrorism strategy. This amendment also shows our commitment to build a strong internal security infrastructure in this country. This Bill also shows our deep commitment to international obligations and

conventions. The Bill also shows our commitment to international peace, security and welfare of humanity.

That is why I would like to congratulate the hon. Minister and the Prime Minister of India. We all know, as has been mentioned earlier, about the devastation and destruction that the weapons of mass destruction carry. We all know the cases of Hiroshima and Nagasaki in Japan. In Hiroshima, it killed 1,40,000 people. In Nagasaki, it killed 74,000 people, and the survivors suffered from cancer and other ailments in their lives. Even otherwise also, as some of my friends mentioned earlier, there have been some recent incidents. Col. Rathore was telling as to what happened in Tokyo subway in Japan in 1995 and in America in 2001. Similarly, one Chechen terrorist threatened that he had buried a dirty bomb in a Moscow park and he will turn Moscow city into an eternal desert. Similarly, recently, one American counter-terrorism official testified before the United States House Permanent Select Committee on Intelligence that Al-Qaeda in the Arabian Peninsula has high intention to procure chemical weapons and biological devices, particularly in Pakistan and Yemen. So, we cannot say that the threat or the risk is over. We have to be much more vigilant than ever before.

17.00 hrs

Hon. Chairperson, Sir, I would also like to share the views of the hon. Member Shri Uttam Kumar Reddy. The present Bill mentions about a person. Perhaps, I would also like to request the hon. Minister one thing. Now, there are such firms and companies. There are also rogue States. Sometimes they try to fund the terrorist activities. Smt. Supriya Sule was talking about it.

The United Nations Security Council Resolution 1540 talks about the chemical, biological, radiological, or nuclear (CBRN) weapons. I would like to ask the hon. Minister whether the Government will include it because there is no clarification on this issue. Similarly, I would also like to request one thing though it is not directly related with his Ministry. It comes under the National Disaster Management Authority, which ultimately comes under the Ministry of Home Affairs. I have attended many conferences and workshops on CBRN. Basically, those conferences or workshops focussed on how to defend ourselves. But unfortunately, even our Disaster Management Manual is not very clear. Who will be the first responder? Let us suppose that there is a biological attack or a chemical attack. Generally, or traditionally, it is the police, which is the first responder for such kinds of emergencies.

Is our police prepared for such kind of emergencies? Is our police trained or equipped to face such a situation? Shri Manish Tewari Ji was also talking about it. The Bhabha Atomic Research Centre is a nodal agency of the disaster management mechanism. I would like to know whether the Bhabha Atomic Research Centre will respond to such a situation. What will really happen? CBRN weapons-related disasters are a matter of grave concern for all of us. The whole country is vulnerable to such kinds of attacks. How do we prepare ourselves? How do we train our forces to tackle such a situation? How do we equip ourselves? Nowadays, we say that the NDRF or SDRF will take care of it. But NDRF is not present everywhere. I think, it will take a lot of time. I think, this is an issue which should be addressed urgently. There should be facilities so as to isolate and decontaminate our patients and victims. There is no clarity on that also in our Disaster Management Manual.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to tell you a story from a book namely 'Anti-Gravity Handbook'. In fact, this story had not come to our notice. In 1985, this book was published. In the said book, there is a wonderful story as to what really happened. In 1965, while Chinese were in occupation of Tibet and Lhasa, they got some Sanskrit manuscripts and those Sanskrit manuscripts were sent to Dr. Ruth Reyna, an American professor, and a Sanskrit scholar and Indologist. At that time, she was on sabbatical at the University of Punjab in Ludhiana. Those manuscripts were sent to her for translation. That Professor translated those manuscripts. The translation was sent to the Indian Institute of Science, Bangalore and to the Chinese as well. Our Indian Institute of Science, Bangalore said that 'that manuscript was not of much use and it could not be used. It is not part of the book that we claim, that is, Young Servers'. But after a few years, in the year 1975, the Chinese spoke at a press conference that that manuscript was very important and that they were going to use it for building interstellar spaceships. Years later, one Prof. A.V. Krishnamurthy, from the same Indian Institute of Science, Bangalore said that they believed that some of our texts, especially Vedas and Sanskrit texts, have the references of our spacecraft, aeronautics, and all these things.

I would like to ask the hon. Minister whether we can have a study on this in order to defend our country and to protect our citizens. Can we study these Sanskrit texts so as to find out some defensive mechanisms? Thank you very much.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on 'The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022.

Sir, of course, this is a good move. The scope of this Bill is very limited. This is a modification of the parent Act to the effect of including funding also within the ambit of the parent Act.

Sir, India's stand was very clear always, now and then. India should stand for protecting the national interests, common goodness, and peace of the entire world.

Coming to this particular topic, we have always advocated for total disarmament. Our desire and ambition was to become a model to the entire world. We have done our level best in this direction. India took the initiative for the International Convention to Prohibit the Use of Nuclear Weapon.

Sir, in 1988, at the special Session of the United Nations General Assembly on disarmament at New York, the then Prime Minister Rajiv Gandhi Ji put forward a comprehensive action plan based on this subject.

Sir, the original Bill in 2005 was moved by the then External Affairs Minister Shri Natwar Singh. Our stand was very clear. Nuclear power can be used for security of the nation, development of the nation but at the same time, we were deadly against the misuse of it – whether it is chemical weapon, biological or toxic weapon. That was our clear stand.

Sir, we should be proud of our leaders. Our country should be really grateful to our former leaders. They always took a bold step. We have to appreciate them for their farsightedness.

Rajiv Gandhi Ji's Ministry has shown farsightedness, commitment for peaceful coexistence, and world peace.

Sir, my tributes to such great leaders on this occasion. It may be noted that India has also an institutionalised mechanism to prevent unlawful access to such weapons and their delivery system.

Use of nuclear energy is a useful thing and at the same time, we have to handle the misuse of it and we must treat it with high-handedness.

Many learned friends were speaking about the consequences. If nuclear power is used in a negative manner, we cannot imagine the havoc it is going to make. It will lead to destruction of life and organisms.

Sir, there are many International Conventions such as Chemical Convention, Biological Convention, Toxic Convention and we are all committed to go according to that.

There are many things. I do not want to say much. UN Security Council Resolution 1540 requires all States to adopt measures to criminalise assistance to non-State actors or to acquire weapons of mass destruction and to put in place domestic control to prevent it. Sir, we were taking such an initiative in the past also.

I would like to say one more thing. Misuse of legislation also is a problem. Last time also, when we were discussing about that, we were warning about that. This legislation is very good and everybody will support it. I have no doubt about it.

Sir, I am concluding by quoting the then External Affairs Minister. 'I would once again reiterate that India is committed to safeguard its security as a nuclear weapon

State and to deepen its autonomous scientific and technical capability for meeting our security imperatives as well as our developmental goals'.

Finally, he said: 'We are committed to ensure that these do not fall into the wrong hands, especially the terrorists and non-State actors. India has an impeccable record in this regard and India will continue to work to prevent proliferation of weapons of mass destruction'.

Sir, I would like to conclude by saying that this is a legislation which has to be passed unanimously. Let us hope for the best. Let us pass the legislation unanimously.

With these few words, I conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson Sir, thank you very much for giving me this opportunity to take part in the discussion on the very important Bill, namely, the Weapons of Mass Destruction and their Delivery System (Prohibition of Unlawful Activities) (Amendment) Bill of 2022.

Sir, the original Act of 2005 has to be amended. Section 12A has to be incorporated by means of which the financing of all these activities -- financing also is becoming an unlawful activity in respect of weapons of mass destruction -- can be stopped. I fully support this amendment Bill, subject to certain specific clarifications from the hon. Minister.

Sir, it is well accepted that the weapons of mass destruction are always a threat to international peace and security. Nuclear weapons, chemical weapons, biological weapons have already been described as weapons of mass destruction by the Resolution 1540 of 2004 of the United Nations Security Council. On the basis of that

we enacted a legislation in 2005 and that Bill was piloted by the then External Affairs Minister, Shri Natwar Singh. That original Act now has to be amended through this Bill.

Sir, we have had the bitter experience of Hiroshima and Nagasaki. On August 06 and August 09, 1945, around 66,000 people died instantly and around 1,60,000 people died because of radiation related diseases by the end of that year. This was the level of devastation caused by these weapons of mass destruction. That is why, in my opening remarks itself I have stated that these weapons are against international peace and security. Under these circumstances, the Disarmament Policy of the Government of India has to be highlighted at all the international forums.

These were first invented by Germany during the First World War. Weapons like poison gas and pressurised tanks which spread deadly toxins over the battle field were used by Germany for the first time. Such weapons killed and wounded thousands of people during the First World War. All these bitter experiences convinced the United Nations to incorporate and adopt this Resolution of 1540 in the United Security Council on 28th April, 2004 in Chapter VII. It is still in existence and India is a strong votary of the Disarmament Policy. Our policy is also very specific with regard to CTBT and NPT.

We have to protect and safeguard the interests of the country and at the same time, we will not use this weapon at first. Such a policy had been framed and is in place since Independence. Just a while ago, Shri Basheer Saheb said we have to salute our forefathers for devising consistent policies in respect of nuclear disarmament.

Sir, coming to the provisions of this amending Bill, I would like to seek a few clarifications from the External Affairs Minister. This is meant to stop financing for proliferation as well as its delivery. Now, here it says, `if any person', any person may include a company and the definition of a company is according to Section 20 of the original Act. So, it is very clear. Section 20 says, `a company includes a group of individuals also'. There is no fault in the definition and there is also no harm in using the phrase `if any person'. I agree with it. My reservation is this. I would like know whether the provisions of the original Act were not sufficient to deal with this subject also. I would like quote Section 15 of the original Act. It says, `Punishment for aiding non-State actor or terrorist: Any person, who with an intent to aid any non-State actor or terrorist contravenes the provisions of Section 9 of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and also be liable to fine.' Any person, `with an intent to aid', `Aid' here means with an intent to finance. So, `financing' would then mean and include involvement in proliferation and delivery of the weapons of mass destruction and will come within the purview of Section 15 of the Act.

This is an amendment to the original Act. My question to the hon. Minister is, whether or not the amendment is highly required or essential. There is no doubt that I fully support the amendment. Already the existing provision in the original Act itself is very clear but there is no provision to seize the property to which I agree.

Sir, let me come to section 17. It says:

"17. Punishment for violation of other provisions of the Act. -

1. Where any person contravenes, or abets or attempts to contravene,…"

'Abets' or 'attempts to contravene' means a person or a company who is financing this proliferation of the weapons of mass destruction and their delivery also. Here, section 17 will be attracted.

I would like to seek these clarifications from the hon. Minister. Also, section 3, sub-clause 4 is very clear. The applicability of the Act is also very clear. There is no ambiguity in this. I am only seeking a clarification.

Hence, I fully support the Bill. With these words, I conclude.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Sir, I would like to support the Bill.

Sir, let me first of all take the opportunity to appreciate our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi for transforming our nation as a global leader through several significant strategic initiatives. Thanks to the vision and leadership of our hon. Prime Minister, India is now playing an active role in being a constructive contributor in the efforts to create an international order through reformed multilateralism and human centric globalisation.

I also wish to appreciate our hon. Minister of External Affairs, Shri Jaishankar whose guidance and efforts are helping India secure improved bilateral relations and regional stability.

Sir, the influence of online media was not that rampant in 2005 when this Bill was adopted. Now, on You Tube or dark web, even a teenager can manufacture a WMD sitting at the convenience of their homes, instructed by an insane terrorist or even a hostile nation and financed by another in a different nation. The web of terror financing has expanded manifold and it is important that we protect our nation from such insane terror or militant attacks.

The United Nations Secretary-General, Antonio Guterres in April, 2020 had warned that the pandemic has revived the spectre of bio-terrorism. He has said:

"The weaknesses and lack of preparedness exposed by this pandemic provide a window on how a bio-terrorist attack might unfold."

Preparation is the key. We cannot be complacent and we cannot be preparing alone. Misuse of WMD leading to incidents like bio-terrorism is a global issue.

India, under the leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi, certainly has reasons to be proud of its achievements. However, in the regional context, India's pride, unfortunately, is also neighbour's envy.

In 2008, when the UPA Government was in power, we saw a massive and coordinated terror attack in Mumbai. This was not an attack carried at the borders. This happened well within our boundaries, at the heart of our commercial capital. Of course, some attackers were neutralized and some were put behind bars. But what about those who financed them? Should we believe that they came within our boundaries without the support of insiders? It means that there is a well-oiled financial network functioning within our nation and across as well.

I support this Bill in anticipation that these terror financing networks will be wiped off from our country as well as across the borders.

I suggest to the hon. Minister that we must encourage the use of technological innovations and policies to improve our counter-proliferation efforts. We must be prepared to combat the use of new mechanisms of financing these weapons, like the use of blockchain technology which supports cryptocurrencies like bitcoin or online crowdfunding websites.

Sir, our Government should ensure that periodic assessment of this enactment should be there so that we can ensure proper functioning of our multiple agencies engaged in this work.

Sir, I support this Bill on behalf of our Party.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सदन में आज सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की। विश्व का हर व्यक्ति यह चिंता जाहिर करता है। अभी रूस-यूक्रेन का मामला था तो भारत में भी सभी लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए, कहीं एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम न फेंक दे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नागासाकी और हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने बम फेंके, उस समय वहां 1,40,000 लोग मरे थे। आज भी इतने सालों के बाद भी जब वहां बच्चे पैदा होते हैं, तो वे कहीं न कहीं गम्भीर आनुवांशिक बीमारियों का शिकार होते हैं। पूरा विश्व इसकी चिंता करता है कि परमाणु हथियार का उपयोग न हो। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

महोदय, इस विधेयक के 'उद्देश्य और कारणों का कथन' में आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के प्रसार से संबंधित विनियमों का विस्तार किया गया है, इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की लक्षित वित्तीय शास्तियां और वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों को सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के प्रसार के विरुद्ध अधिदेशित किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि सामूहिक संहार के आयुधों और उनकी परिदान प्रणालियों के प्रसार को वित्तपोषित करने के विरुद्ध किया जा सके जिससे हम अपनी अंतराष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा कर सकें।

सभापति महोदय, यह विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण से रोकता है और व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से रोकने के लिए केन्द्र सरकार उनके धन, वित्तीय सम्पति या आर्थिक संसाधन

को फ्रीज, जब्त या संलग्न कर सकती है। यह व्यक्तियों को किसी भी निषिद्ध गतिविधि के संबंध में अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने से रोकता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं एक आलेख पढ़ रह था, उसमें जो लिखा था, उस बात को मैं सदन में पढ़ना चाहूंगा कि परमाणु अप्रसार छ: दशकों से अधिक समय से दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन इस दौरान इस समस्या के रूप बदलते गए हैं। खासतौर पर शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से इसमें काफ़ी बदलाव आया है। ग्लोबल न्युक्लियर ऑर्डर के स्थापित होने के बाद से संभावित ख़तरों और सत्ता के संतुलन में व्यापक परिवर्तन हुआ और इस वजह से पहले की तुलना में परमाणु अप्रसार आज कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि ज़्यादातर देशों के लिए परमाणु हथियार अंततः उनकी सुरक्षा से जुड़े हैं और परमाणु अप्रसार व्यवस्था की पेशकश को कमियों के बावजूद इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इससे दुनिया खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करती है।

इसके साथ इस पर भी गौर करना होगा कि परमाणु अप्रसार के बारगेन का असर कम होने के साथ ऐसे देशों की संख्या बढ़ी है, जो परमाणु हथियार की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शीत युद्ध के दौर में इस मामले में सिर्फ़ अमेरिका और सोवियत संघ की होड़ को लेकर आशंका रहती थी और लगता था कि इस वजह से वैश्विक परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा. हालांकि, आज इस खतरे में वेपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन (WMD) यानी सामूहिक विनाश के हथियार, उनके डिलीवरी मैकेनिज्म यानी उन्हें छोड़ने वाली व्यवस्था-तकनीक और परमाणु आतंकवाद भी शामिल हो गए हैं। इस संदर्भ में चीन और पाकिस्तान के बीच परमाणु और मिसाइल के क्षेत्र में सहयोग और उत्तर कोरिया व ईरान में मिसाइल से जुड़ी गतिविधियों का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है। इनमें से हर एक का असर एशिया में सैन्य संतुलन पर पड़ा है।

सभापति महोदय, ताकत के इस खेल से मौजूदा परमाणु प्रसार व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसमें मुख्य चुनौती यह है कि इस खेल में नए देशों के पावर हासिल करने के साथ परमाणु अप्रसार से जुड़ी बहस कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। नई वैश्विक व्यवस्था में होड़, प्रतिद्वंद्विता, अराजकता और संघर्ष बढ़ रहे हैं। अभी तक हम जिस वैश्विक राजनीतिक और सामरिक व्यवस्था को देखते आए हैं, उसकी खास बात कई

देशों के बीच गठजोड, नियम आधारित एंगेजमेंट और अंतराष्ट्रीय कानून का सम्मान रहा है, लेकिन अब इन पर दबाव बढ़ रहा है। दुनिया समझती थी कि अंतरराष्ट्रीय उदार व्यवस्था उसका अधिकार है, जो कि सच नहीं है। जब तक इसे मौजूदा सिद्धांतों और व्यवस्था के आधार पर मज़बूत नहीं बनाया जाता और बरकरार रखने की कोशिश नहीं होती, तब तक इसके ख़त्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, मैं अपनी अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा। चूंकि यह विषय इस बिल का मामला नहीं है, लेकिन आज लोग अवैध लाइसेंस ले लेते हैं और अवैध हथियारों के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। मैं राजस्थान की बात करूं तो इसमें राजस्थान बहुत बदनाम राज्य रहा है।... (व्यवधान)

अभी हमारे एम.पी. साहब बहुत चिंतित हो रहे थे। मैं इनके क्षेत्र को अभी छोड़ देता हूँ। मै गंगानगर को छोड़ देता हूँ। गंगानगर जिले में करोड़ों रुपये लेकर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने हथियारों के फर्जी लाइसेंस जारी कर दिए। अलवर के अंदर कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा कर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में डीएम की नाक के नीचे फर्जी हथियार का लाइसेंस बनाने का मामला सामने आया था। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि राजस्थान के एटीएस ने वर्ष 2017 में ऑपरेशन जुबैदा के तहत दलाल ग्रोवर को गिरफ्तार किया। दलाल ग्रोवर जम्मू-कश्मीर के जिलाधिकारियों और हथियार बेचने वालों के बीच दलाल का काम करता था। उस समय एटीएस ने उससे 565 लाइसेंस जब्त किए थे, जिनमें से 93 लोग ऐसे थे, जिन्होंने कभी जम्मू में नौकरी नहीं की। वहाँ उनके नौकरी-पेशा बताकर लाइसेंस दिए गए। जिला कलेक्टर के अलावा केन्द्र का अपना एक प्रतिनिधि भी होना चाहिए। मेरा यह कहना था कि जिला कलेक्टर लाइसेंस बनाता है, लेकिन उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को वास्तव में लाइसेंस की जरुरत है, वे सालों से कलेक्टेरिएट में चक्कर लगाते रहते हैं, उनको बीस-बीस साल हो गए। लेकिन, जिनको आवश्यकता नहीं है, वे तीन-तीन हथियार लेकर बैठे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें केन्द्र सरकार भी हस्तक्षेप करे और केन्द्र का प्रतिनिधि भी लाइसेंस बनाने की उस कमेटी के अंदर रहे।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022.

This Bill is in line with our international obligation under the UN Charter of promoting international peace and development. The existing law covers unlawful activities relating to biological, chemical, and nuclear weapons and their delivery systems, and provides for integrated legal measures to exercise control over the export of materials, equipment, and technologies in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems, and for prevention of their transfer to non-State actors or terrorists.

Sir, India is a responsible nuclear weapon State and is committed, as per its nuclear doctrine, to maintain credible, minimum deterrence with the posture of no-first use and non-use against non-nuclear weapon States. The parent Act provides overarching and integrated legislation prohibiting unlawful activities in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems. While reiterating India's firm commitment to safeguard its security as a Nuclear Weapon State and its undiminished commitment to global nuclear disarmament, the Act seeks to effectively translate, at the operational level, India's commitment to prevent proliferation of weapons of mass destruction.

Sir, the Indian Government must view nuclear weapons as part of a comprehensive national security strategy that includes diplomacy, arms control initiatives, and conventional forces to maximise stability and peace in the region.

Cyber warfare technology is another trans-domain capability that is spreading rapidly. India's nuclear weapons-related systems should be ready to respond to cyber threats. As India remains particularly vulnerable to biological threats and has a history of hostile political conflicts, India needs to take a lead in ensuring the Biological Weapons Convention is effective in its aim at curbing use of biological agents or toxins. The primary focus of India at the Biological Weapons Convention should be to instil and participate in a scientific advisory board on the same lines as the one attached to the Chemical Weapons Convention. The board should have scientists representing various participating countries, industry, societies, and academics.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRIMATI APARUPA PODDAR: Sir, I am just concluding.

Sir, there should be an immediate reform of DRDO whose top laboratory is the Defence Research and Development Establishment located at Gwalior in Madhya Pradesh. Since DRDO's massive failures of its indigenous weapons programmes do not paint an inspiring picture, I would want the Minister to clarify how the Government plans to revamp production at DRDO.

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Sir, the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022 seeks to prohibit financing of any activity in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems. The Bill also aims to prohibit making available funds, financial assets or economic resources for

any prohibited activity in connection with weapons of mass destruction and their delivery systems.

The Bill seeks to modify the 2005 law – Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. The 2005 Act prohibits unlawful activities including manufacturing, transport, or transfer and delivery of weapons of mass destruction.

The Bill bars people from financing any prohibited activity related to weapons of mass destruction and their delivery systems. To prevent such financing, the Bill empowers the Centre to freeze, seize or attach funds, financial assets, or economic resources held, owned or controlled directly or indirectly.

The Bill also prohibits people from making finances or related services available for the benefit of other persons connected to any prohibited activity.

It is in accordance with the recommendations of the Financial Action Task Force that have mandated against financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems as well as the United Nations Security Council's targeted financial sanctions.

The need of the Weapons of Mass Destruction Bill, 2022 was felt to fulfil India's international obligations.

Sir, I congratulate the Government for bringing this Bill and convey our party's support to this Bill. With these few words, I conclude. Thank you.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Mr. Chairman, Sir, I rise here to support the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022.

सर, सदन का यह इतिहास रहा है कि जब भी इस तरीके का कोई बिल लाया जाता है तो सर्वसम्मति से हम लोग ऐसे किसी भी बिल को पास करते हैं। मुझे इस बात का फख्र है कि गौतम बुद्ध की लैंड से, महात्मा गांधी की धरती से हम पूरी दुनिया को अमन-शांति का पैगाम देते हैं। यह हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा ऐसी चीजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बात रखी है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो आज के विदेश मंत्री हैं, वे कैरियर डिप्लोमैट रहे हैं। उन्होंने भी लगातार इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रखा है। पूरी दुनिया जानती है कि इस तरीके के जो वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, दुनिया ने देखा है कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ? वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के नाम पर इराक के अंदर इतने दिन क्या हुआ? वहां कुछ नहीं निकला। मैं कांप्लीमेंट करना चाहूंगा, हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर श्री नरेन्द्र मोदी जी तक, जितने भी देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उनके समय में हमने न्यूक्लियर हासिल किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। वाजपेयी जी के जमाने में भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। शायद उससे पहले वह हो सकता था, जो मेरी जानकारी है, वह काफी पहले तैयार था, लेकिन उस वक्त के प्रधान मंत्रियों की आफ्टर लिबरलाइजेशन प्रायोरिटीज़ कुछ और थीं या हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ शांति बहाल करने की बात थी, इसलिए शायद उसको डिले किया गया। वाजपेयी जी के टाइम पर पोखरन टेस्ट हुआ। सर, इसमें सीक्रेसी की जरूरत है। मैं अपने देश के साइंटिस्ट्स को कांप्लीमेंट करना चाहूंगा कि उनका यह असली कंट्रीब्यूशन है। हम पॉलिटिशियंस लोग अपनी पीठ भले ही थपथपायें, लेकिन सीक्रेसी का भी महत्व है। ऐसी सीक्रेसी, पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था, देश के अंदर भी सिर्फ तीन लोगों को पहले मालूम था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जार्ज फर्नांडीज साहब और प्रधान मंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर थे, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साहब, सिर्फ तीन लोगों को मालूम था। वहीं हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स थे, उन्होंने इसे लीक किया, वहां की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और वह ऐसे लोगों के हाथ में लग गई, जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन, हमारे यहां सीक्रेसी रही। पाकिस्तान ने खुद माना कि ए. क्यू. खान ने गलती की है और इनफार्मेशंस

लीक की हैं। सभापति महोदय, यहां न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात आई और क्लीन वेवर की बात कही गई।

जब माननीय मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो उस समय इस पर रोशनी डालेंगे। ऐसे हर मामले में हम लोग सर्वसम्मत रहते हैं। वर्ष 2008 में जब हम न्यूक्लियर वैवर लेने जा रहे थे, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन उस वक्त न्यूक्लियर वैवर के खिलाफ आज के सत्तापक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। इस सदन के अंदर ऐसी चीज इस पटल पर रखी गई जो इस सदन के नाम पर काला धब्बा साबित हुई है। हम इस बिल के समर्थन में हैं और इस बिल को सर्वसम्मति से पास करना चाहते हैं।

जब मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में जो लीक होता है, जापान में सुनामी के समय और चर्नोबिल में प्लांट्स में लीक हुआ, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कनور دانش علی(امروہہ): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022.

جناب، اس ایوان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی اس طریقے کا کوئی بِل لایا جاتا ہے تو ہم سب ملکر ایسے کسی بھی بِل کو پاس کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ گوتم بُدھ کی زمین سے، مہاتما گاندھی کی زمین سے ہم پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نےہمیشہ ایسی چیزوں کے خلاف بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بات رکھی ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے جو آج کے وزیرِ خارجہ ہیں، وہ کیریر ڈِپلومیٹ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی لگاتار اسے انٹر نیشنل پلیٹ فارم پر رکھا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس طرح کے جو ویپنس آف ماس ڈیسٹرکشن ہوتےہیں، دنیا نے دیکھا کہ ہیروشیما اور ناگا ساکی میں کیا ہوا؟ ویپنس آف ماس ڈیسٹرکشن کے نام پرعراق کے اندر اتنے دن کیا ہوا؟ وہاں کچھ نہیں ملا۔ میں کومپلیمینٹ کرنا چاہوں گا ہمارے ملک کے پہلے وزیرِ اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے لیکر جناب نریندر مودی جی

تک ، جتنے بھی ملک کے وزیرِ اعظم رہے ہیں، ان کے وقت میں ہم نے نیوکلیر حاصل کیا۔ محترمہ اندرا گاندھی جی کے زمانے میں نیوکلیر ٹیسٹ ہوا۔ واجپئی جی کے زمانے میں بھی نیو کلیر ٹیسٹ ہوا۔ شاید اس سے پہلے وہ ہو سکتا تھا، جو میری جانکاری میں ہے، وہ کافی پہلے تیار تھا، لیکن اس وقت کے جتنے بھی وزیرِ اعظم تھے ان کی آفٹر لبرلائزیشن ترجیح کچھ اور تھی یا ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ شانتی بحال کرنے کی بات تھی، اس لئے شاید اس کو ڈیلے کیا گیا۔ واجپئی جی کے ٹائم پر پوکھرن ٹیسٹ ہوا۔ سر اس میں سیکریسی کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ملک کے سائنس دانوں کو کمپلیمینٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا یہ اصلی کنٹری بیوشن ہے۔ ہم سیاسی لوگ بھلے ہی اپنی پیٹھ تھپ تھپائیں، لیکن سیکریسی کی اپنی اِمپورٹینس ہیں۔ ایسی سیکریسی، پوری دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا، ملک میں بھی صرف تین لوگوں کو پہلے معلوم تھا، عزت مآب وزیرِ اعظم واجپئی صاحب، اس وقت کے وزیرِ دِفاع جناب جارج فرنانڈز صاحب اور وزیرِ اعظم کے سائنٹِفِک ایڈوائزر تھے، ڈاکٹر اے۔پی۔جے۔ عبدالکلا صاحب صاحب، صرف تین لوگوں کو معلوم تھا۔ وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے جو نیو کلیر سائنس داں تھے، انہوں نے اسے لیک کیا، وہاں کی ٹیکنا لوجی ٹرانسفر کی اور وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگ گئی، جو دنیا کے لئے خطرہ بن سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سیکریسی رہی۔ پاکستان نے خود مانا کہ اے۔کیو۔خان نے غلطی کی ہے اور انفارمیشنس لیک کی ہے۔ چیرمین صاحب، یہاں نیو کلیر سپلائی گروپ کی بات آئی اور کلین ویور کی بات کہی گئی۔

جب عزت مآب منتری جی اپنا جواب دیں گے تو اس وقت اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ایسے ہر معاملے میں ہم لوگ منفقہ طور پر ساتھ رہتے ہیں۔ سال 2008 میں جب ہم نیو کلیر ویور لینے جا رہے تھے، اس وقت منموہن سنگھ جی کی سرکار تھی، لیکن اس وقت نیو کلیر ویور کے خلاف آج کے رولنگ پارٹی کے لوگ مخالفت کر رہے تھے۔ اس ایوان کے اندرایسی چیز سبھا پٹل پر رکھی گئی جو اس ایوان کے نام پر کالا دھبّہ ثابت ہوئی۔ ہم اس بِل کے سپورٹ میں ہیں اور بِل کو منفقہ طور پر پاس کرانا چاہتے ہیں۔

جب منتری جی اپنا جواب دیں گے تو نیو کلیر پلانٹس وغیر میں جو لیک ہوتا ہے، جاپان میں سُنامی کے وقت اور چرنوبِل میں پلانٹس میں لیک ہوا، ہمیں اس کا بھی دھیان رکھان چاہئیے۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات مکمل کرتا ہوں ۔ بہت بہت شکریہ ۔۔ (ختم شد)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में The Weapon of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। गीता में 18वें अध्याय में कृष्ण ने पूरा सार कहा है, सार यह था कि

सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकम् शरणम् व्रज

अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुच:॥

आज दुनिया पूरी ग्लोबल वर्ल्ड हो गई है। आज जितना खतरा आम जनमानस को है, उतना खतरा कभी नहीं था। कोविड के बाद पूरी दुनिया बड़ी परेशान है। क्या हुआ, चीन में यह बायॉलाजिकल वेपन के तौर पर यूज हुआ या नहीं हुआ, अमेरिका और चीन एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इस पार्लियामेंट में वसुधैव कुटुंबकम की बहुत चर्चा होती है, हम भी बात करते हैं। लेकिन पिछले दो सालों में वसुधैव कुटुंबकम हो पाया? आज लोग अपने लिए परेशान हैं। हमने कोविड में देखा, बेटा पिता के लाश की जलाने के लिए तैयार नहीं था या पिता बेटे का लाश लेने के लिए तैयार नहीं था।

आज जब माननीय विदेश मंत्री जी कह रहे थे, जिसके ऊपर सभी सदस्यों ने समर्थन करते हुए बड़ी चर्चा की। क्या विदेश मंत्री जी ने ठीक नहीं कहा कि कोई भी विदेश नीति है, आज की डेट में भारत कहां खड़ा है, हमको कहां सुविधा है, हमको कहां फायदा है, क्या कोरोना के बाद भी हम यह नहीं समझे? आज भी हम पूरी दुनिया का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। ईरान में क्या हो रहा है, यू.के में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है? जहां जो हो रहा है, यदि हमको कोई बुलाएगा तो हम अपनी व्यवस्था देंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस तरह से आप टांग अड़ाने की बात करते हैं। आपके साथ कौन है?

फारूख साहब आप जहां से आते हैं, चीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में आ गया, वह पहले हमारा हिस्सा था। वर्ष 1947-48 से पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, वे हमारे नागरिक हैं। लेकिन क्या वर्ष 1947-48 से कोई भी ऐसा कंट्री खड़ा हुआ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे रहा है। चीन ने अक्साई चीन ले लिया, वहां पूरा रास्ता बना लिया। क्या हालत है? आपके साथ पूरी दुनिया नहीं खड़ी है और आपको उतना ताकतवर नहीं मान रही है। आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ठीक कर दें।

आज भी चर्चा चल रही है। मैं बड़े सभ्य तरीके से सभी का बड़ा सम्मान करते हुए कहता हूं कि पहले अपने बारे में सोचिए। मैं आपको कह रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी पंचामृत के सिद्धांत पर चले। केवल हंसने से नहीं होता है, केवल मजाक उड़ाने से नहीं होता है, केवल यह कहने से नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज आपको अपने प्रधानमंत्री पर इतनी ताकत नजर आ आ रही है तभी आप कह रहे हैं। आज यह बिल क्या है?

ग्लोबल वर्ल्ड में आज अलग-अलग एक्टिविटीज़ में किसी के पास पैसा है, किसी के पास बैंक है, किसी के पास कोकीन है तो कोई ड्रग्स दे रहा है। भारत में पुरुलिया में एक कांड हुआ। मेरे बगल में हुआ। पुरुलिया में हथियार गिरा दिए गए। किस कंट्री ने किस इंटेंशन से किया, हम इसकी जांच आधी-अधूरी ही कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं था कि हम किसी की संपत्ति जब्त कर सकें, बैंक एकाउंट फ्रीज कर पाएं या किसी को धक्का पहुंचा सकें। वर्ष 1993 बम ब्लास्ट की बात कर रहे थे।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. We are short of time. The hon. Minister is ready for reply.

डॉ. निशिकांत दुबे: वर्ष 1993 में दाऊद इब्राहिम चले गए। क्या हम उनकी संपत्ति जब्त कर पा रहे हैं? दुनिया में उनकी संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई है। हमारे देश को तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति है। सलाउद्दीन साहब हैं मफ के, वर्ष 1987-88 के बाद चले गए। हम उनका क्या कुछ कर पा रहे हैं? आज हम सबको इस बिल की आवश्यकता है। यूएन का रिजॉल्यूशन आया. एफएटीएफ का रिजॉल्यूशन आया, जिसका सिग्नेटरी होना है। चाहे केमिकल वेपन्स हों, बायोलॉजिकल वेपन्स हों, एटॉमिक वेपन्स हों, साइबर सिक्योरिटी का मामला हो या क्रिप्टो का मामला हो, हम सबको दुनिया के साथ मिलकर इस तरह की चीजों को रोकने के लिए एफएटीएफ रिजॉल्यूशन में मदद करने की आवश्यकता थी और यूएन का साथ देने की आवश्यकता थी। इसी कारण से माननीय विदेश मंत्री बिल लेकर आए हैं। हम इनके समर्थन में खड़े हैं। मुझे लगता है कि विश्वगुरु बनने और भारत को ताकतवार बनाने में माननीय प्रधान मंत्री जी के योगदान के लिए पूरे सदन को धन्यवाद देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the Bill under the nomenclature 'Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022' as it intends to amend the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005. So, without having any reservation or without having any quarrel, all of us are extending our support to this Bill.

Since yesterday, the House has been reverberating and ruminating over the mission, vision, thought, and philosophy of our predecessors such as Jawaharlal Nehru*ji,* Indira*ji,* Rajiv*ji,* and Atal Bihari Vajpayee*ji.* Ours is a great country; so, it is the bounden duty entrusted upon us to defend and protect the country.

In the year 1988, on the 9th June, at the United Nations Special Session on Disarmament, Shri Rajiv Gandhi presented a time-bound action plan for nuclear weapon free world. So, it was enunciated by our country long back about what needs to be done for the people across the world to stem the rot arising out of the nuclear proliferation.

Here, we are all talking about Hiroshima and Nagasaki catastrophic destruction. It is alarming to note that still, the world possesses more than 13,400 nuclear weapons. There have been over 2,000 nuclear tests conducted till date. So, disarmament is the best protection against such dangers. It was first conceived and enunciated by our country.

Jawaharlal Nehru conceived the Atomic Commission. In 1974, the project, Buddha came. In 1998, we had the project, Shanti. We had, at least, made ourselves as a force to be reckoned with.

So, now the point is that we are trying to resist the threat of weapons of mass destruction by adopting some measures that have been depicted here in this Bill.

मैं जयशंकर जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान से एक नहीं, एक के बाद एक भारी तादाद में लोग हिन्दुस्तान के सारे बैंकों को लूटकर देश से भाग रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कैरिबियन सी के किनारे बैठकर वे लोग मस्ती मार रहे हैं और हम उनको यहां फेसबुक और वाट्सऐप पर देख रहे हैं। हमारे देश के सारे धन को लूटकर और हमारे देश को छोड़कर जो आराम से बाहर घूमते हैं, उन लागों के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

इस बिल में है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा, तो उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए आपको एक कानून चाहिए। आप कानून लीजिए, हम तो आपको कानून देना चाहते हैं। मैं लार्जर प्रॉस्पेक्ट में दो-चार बातें जरूर कहना चाहता हूं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not disturb.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Jaishankar Ji, what is the unequivocal definition of weapons of mass destruction? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him complete, please.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I do not have any idea. What is the unequivocal definition of weapons of mass destruction? I think it depends upon the creativity of the enemy. Before 9/11 in America, when the twin tower was demolished, had we, at that time, imagined that an aircraft could be turned into a flying missile? So, it depends upon the creativity of the enemy. So, we have to prepare ourselves for any eventuality. That should be done right at this situation because rogue States are

there. A.Q Khan laboratory, I think, is still existing somewhere in the world. So, how will India be dealing with this kind of unforeseen situation?

Here you are talking about a person. A person cannot do anything on his own capacity. On the one hand, you are talking about State-sponsored terrorism. The implication of it indicates that some States must be behind the terrorist activity. So, we know, and even knowing everything, our hands are tied. We have to plead in the international fora. Besides that, we can do nothing more.

I would even suggest one thing to the hon. Minister and the Government of India. Till date, from 1925 to 2017, 10 International Treaties on Weapons of Mass Destruction have been signed. They are Geneva Protocol, Partial Nuclear Test Ban Treaty, Outer Space Treaty, Non-Proliferation Treaty, Seabed Arms Control Treaty, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, Biological and Toxin Weapons Convention, Chemical Weapons Convention and Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. अब तक ये not in force है। अब वर्ष 2022 आ गया है। अब तक entry into force का जो डेट है, वह डेट अभी तक नहीं पहुंचा है। एक जो सबसे बड़ा Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। कैमिकल और बॉयोलॉजीकल वेपन क्या होता है? This is poor man's atom bomb. Conventional asymmetric को offset करने के लिए स्मॉलर कंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया।

वेपंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज से नहीं है, बल्कि यह बात बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, ये आज की तारीख के नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इन सबसे जूझने के लिए फायरवॉल क्या है? कॉम्प्रिहेन्सिव इमरजेन्सी मैकेनिज्म क्या है? हमारे पास उतना इंटैलीजेन्स है या

नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा इंटैलीजेन्स की जरूरत होती है। अमेरिका पर हमला होने के बाद सारी दुनिया सचेत हो गई थी।

उसके बाद हम भी सचेत होने लगे, लेकिन क्या हमारे पास साधन हैं? हम सिर्फ कानून पारित करके इससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप मेजरमेंट लीजिए, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए आप जो-जो कदम उठाएंगे, हम बिना हिचकिचाहट उसको समर्थन देते रहेंगे। चाहे नेहरू जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इंदिरा जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, राजीव गांधी जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन यह देश हम सबका है, हम देश के निर्माण में सबसे आगे रहे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Mr. Chairman, Sir, I have the privilege of speaking to this august House for a second time today, and I would say that it is a particularly satisfying day in Parliament because twice I have seen that there is unanimity in the House on a foreign policy matter. Earlier in the day I said that foreign policy should be a subject for maximum consensus. I am so glad that people are moving in that direction, and the support that I have had from every Member who has participated – there were totally 21 Members, who spoke on this Bill – is indeed something which is very heartening.

It is also natural that there will be questions, there will be concerns, clarifications sought, and naturally when any Bill is tabled, it is the obligation of the Minister moving it to provide it.

17.52 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Mr. Speaker, Sir, what is it today that we are trying to do through this Bill? We are upgrading a law, which is 17 years old, which like many other legislations clearly

needs updating, and updating laws and ending terminating antiquated rules are both part of good governance. So, today is an exercise in one way of good governance.

Now, to understand this particular Bill, I would take you back to a legislation which was passed by this House in 1947, which is called the United Nations Security Council Act. The Act essentially obligates us that the Central Government will apply any measures, not involving the use of Armed Forces, which will give effect to any decision of the Security Council. So, we have made a commitment as a part of our foreign policy at the very start of our Independence. We are good members of the UN, and therefore, if there is a UN Security Council Resolution, which requires action, we will implement it.

What they did not do at that time in Resolution 1540 was to specifically refer to finance. So, when we moved this legislation in 2005, we took our provisions from the Security Council Resolution. Since then, the importance of finance has increased. Some Members have raised this issue whether finance was implicit in it. I will address that particular issue. This has been the subject of a comment of the FATF.

Now, all hon. Members will understand the importance of FATF. Today, the FATF evaluates whether countries are responsible in terms of their financial policy. We have seen countries, who have done things, who have followed policies and actions which are not right, brought to account. There are very significant consequences of that. I think, most Members are familiar with the countries involved. Some of them are very close to us.

The FATF has a recommendation number 7 which says that countries should implement targeted financial action to comply with Security Council Resolution and

that they should freeze without delay funds and assets and ensure no funds and assets are made available, directly or indirectly, to any person or entity dealing with WMD. So, it is this process – our initial obligation, the 1540 Resolution, the 2005 legislation we passed which today in the light of FATF deliberations and our own security and our international obligation and the importance of finance to this – which is causing us to come to you with this amendment.

Now, some specific issues were raised. I will deal with them very quickly. I think, Uttam Reddyji, who was the first speaker, brought up the issue that we are referring to persons; we are not referring to entities. Now, I would like to inform him, through you Sir, that under the General Clauses Act, 1897, 'persons' is defined to include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not, and it covers entities, companies and organisations, and that the original Act, which we are amending today, also uses 'persons' in view of this. I think, Premchandranji, later on in his remarks, recognised this.

The second issue which came up was this. What is the necessity for this? Can it not be done under the current legislation? Why do we have to take the trouble of amending it? Many other countries have specific legislation. Switzerland has Switzerland War Material Act. Germany has Germany's Foreign Trade and Payments Act. So, there are many examples because FATF and the current requirements need a very specific reference to financing.

What were we doing till now? Till now, we were issuing notifications under the United Nations (Security Council) Act, 1947. What would we do? This would relate to

financial measures. Our notifications are implemented by the Reserve Bank of India and other involved government bodies.

They would advise banks and they would do the monitoring, following the order which MEA would regularly bring out. Our effort today is to give legislative backing so that this is not a one-by-one *ad hoc* measure, but there is a legal statutory way of dealing with what is a continuous problem.

Sir, there was an issue, which was raised, why this is so limited. It is limited. Many hon. Members have raised many other concerns. People have debated disarmament. They have debated world order. They have referred to other issues also.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही बिल पारित होने तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ। … (<u>व्यवधान</u>)

<u>18.00 hrs</u>

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: The issue is whether the proposal is very narrow or not. It is meant to be an amendment for a shortcoming or for something which is missing in the current law. It is not meant to be a new law. It is not meant to be a broad policy directive. So, I acknowledge hon. Members who appreciated it. I appreciate and understand a lot of what they have said on different issues. Many of them are not directly relevant to what we are discussing. For example, there was a reference to BrahMos missile. I think Raksha Mantri ji has made a statement already on this issue. There were some other issues which came up. I do not want to address all the issues. We are already at 6 o'clock. But I want to emphasise that the whole

purpose of this exercise is to make a very specific change in additionality in law so that this country's record, this country' reputation, and this country's security is ensured by financial measures which the Government is in a position to take.

There was also a concern expressed by Ritesh Pandey ji. He mentioned whether businesses by mistake will get caught in this situation that they did not know or something wrong was done or no one told them. Again, in the past, we have experience of this. We have outreach with industry. There is a way of communicating this. There is a long list of individuals and entities who are already sanctioned.

I think anybody who is dealing with this business, who is looking at anything which involves weapons of mass destruction, their technology, their equipment, our reach out, and the nature of the business would alert them to it. So, I think the possibility that somebody would by mistake get caught in a financial law is something which is not realistic. He was also concerned about another issue. He said sometimes you get false positives. You put one name, somebody else's name comes. A sanctions list is not just about names. I have it in front of me. It has a lot of particulars. It has a person's name; it has aliases; it has date of birth; it has place of birth; it has nationality; it has passport number; identification number; address; etc. So, the possibility that somebody would get mistakenly caught in a financial situation, and therefore, will be wrongly harmed is something for which I would say the experience since 2005 has not borne out. If it has not happened in the last 17 years, I think Members should be confident that that is something which would not take place.

There was also an issue whether this would affect legitimate research and development. I think Jayadev Galla ji raised this issue. That is again not the case.

This is a very specialised area. I think the country's scientists and Government are very aware of what they are doing.

Manish Tewari ji raised one particular case. This was relating to Bodhgaya. He wanted to know whether NIA had filed a chargesheet referring to the WMD Act in the case of the Bodhgaya incident in 2018. I would like to confirm to him – he is not in the House – that this was not the case. The FIR had mentioned it. But this was not a decision of the NIA, and when NIA took charge of the case, there was no reference to the WMD Act.

Premachandran ji raised one very specific issue saying that there was a reference to aid and to abet, and if there is aid and abet in the existing law, why should you have a specific reference to finance. The judgement of the Finance Ministry, the Law Ministry, and even the Foreign Ministry is that aid and abet were not sufficient, that it required something very specific on finance. FATF required it. Section 15 only refers to punishment for contravening section 9. He wanted this clarification and he said if I give that clarification, he would be prepared to support the Bill. So, I hope he will support the Bill.

Sir, over and above this, I will very quickly run through some notable points which hon. Members raised. There were references to extradition agreement. It is a very different matter. What extradition agreements we have, what is our success, who have we been able to bring, who did what crime under which regime, is a different subject. We will have, I suspect, differing opinions. We will not have the consensus that we have on foreign policy.

The second issue, I think, is the relevance of this. I think Rajyavardhan Rathore Ji made a very good point. We think of this like something happening in a movie - हो सकता है, कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। These things have happened in real life. In Japan, you had a sarin attack. You had the anthrax letters that he referred to. So, they are not far-fetched scenarios. So, we are dealing with the security of the nation. I referred to the broad purposes.

Saugata Roy Ji today and yesterday made a set of observations, again not specific to the issue. He felt that I was very taciturn. I spoke very little. I think perhaps I am reflective of a Government which does more and speaks less. Maybe he is comfortable with that period, and I noted the remarks of Nishikant Ji. In fact, yesterday, he referred to Krishna Menon. Krishna Menon is known for a record of giving the world's longest speech in the United Nations. Yes. I assure you, I can say the same in six minutes. So, my point is that today, we should be less concerned about giving *gyan* to the world over foreign policy. We should play our role. We should make our contributions. We should look at our national interest. I wish you do this effectively. I am, hon. Speaker Sir, with your permission, referring to this because he made a very specific observation saying that our diplomacy is passive. At the same time, he said, the Prime Minister had spoken to Ukraine and Russia only. अब झगड़ा रशिया और यूक्रेन के बीच में है, who else will he speak to? So, he is speaking to the relevant parties. Maybe doing the relevant thing may look irrelevant to other people, I do not know. But the point I want to make is that we are today in diplomacy very, very focussed. In the morning, we had discussed one aspect of our diplomacy. Today, we

are looking at a policy and legal issue which is very pointedly aimed at something else.

Beyond this, I would make the point that today there are big challenges. A lot of the challenges are there in disarmament, in arms control, and in the proliferation domains. There are regimes and laws which we are part of. One thing which many hon. Members expressed interest in is, where are we in the Nuclear Suppliers Group. The Nuclear Suppliers Group requires a consensus. There is a reason, and many of you are aware of why that consensus is not there. There are countries which genuinely have concerns which they are willing to debate; there are countries which seem to have another agenda and are creating blocks to the consensus. So, it is something that we are working on. But again, the House will appreciate that since 2014, we have become a Member of the MTCR, we have become a member of the Wassenaar Arrangement, and we have a become a member of the Australia Group. So, our role in global arms control, disarmament, proliferation regimes, and initiatives is very strong today. Our reputation is very good, and I believe that the passage of this Bill will strengthen both our national security and our global reputation.

With your permission, this was my response to the queries of the hon. Members.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 Short title and commencement

माननीय अध्यक्ष : श्री विनायक राऊत जी, संशोधन संख्या -1.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, मैंने विधेयक के अमेंडमेंट में यह अमेंडमेंट दिया है। आज इस संसद में मंत्री महोदय ने हिस्टोरिकल विधेयक पेश किया है। मेरी विनती है कि इस विधेयक को आज लोक सभा में और कल राज्य सभा से पास होने के बाद तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होने के तुरंत बाद इसका अमल होना चाहिए। इससे एक आदर्श परंपरा का इस संसद में निर्माण हो जाएगा। यह मेरी विनती है।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप संशोधन को विद्ड्रा कर रहे हैं?

श्री विनायक भाउराव राऊत: मैं विद्ड्रा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री विनायक भाउराव राऊत द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापस लिया जाए?

संशोधन को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18.11 hrs

MOTION RE: 33rd REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा 6 अप्रैल, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सभा 6 अप्रैल, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SEVERAL HON. MEMBERS : Sir, 'Zero Hour'. … (*Interruptions*) Please, Sir. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही गुरुवार, 7 अप्रैल, 2022 को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.12 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 7, 2022/Chaitra 17, 1944 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)